राजस्थान विधान सभा

१६ वीं बैठक, दिनांक २४ मार्च, १९५३

सदन का कार्य ८ बज कर २० मिनिट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ५८८

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Chief Minister (General Administration) be pleased to answer :—

(*a*) How many officers have been "Imported" into Rajasthan from outside Rajasthan ?

(*b*) Please give the names, designations, pay and emoluments of each one of the first ten officers in order of the amount of pay drawn.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(*a*) 43.

(*b*) The required information is placed on the Table of the House.

श्री एच. के. व्यास—I have to draw your attention, Sir, to the fact that an advance copy has not been supplied to me.

श्री जयनारायण व्यास—I think the Hon'ble Member was absent from headquarters and that may perhaps be the reason why a copy was not delivered to him.

श्री एच. के. व्यास—I have standing instructions left with the Assembly Secretariat whether I may be at headquarters or not, there is a place where my 'dak' can be delivered and I shall be responsible for it if any question arises therefor later on. My papers were sent to me earlier also But this time I have found later on. My papers were sent to me earlier also. But this time I have found that the statement in question was not sent.

Page No.2

श्री जसवन्तसिंह—If an Hon'ble Member is absent from headquarters is it necessary that the papers should not be sent to him ? It has happened not only in this case but in regard to some other Assembly papers also.

श्री हरिकृष्ण व्यास—And moreover I came yesterday morning of this fact the Hon'ble Chief Minister may not be aware.

श्री जयनारायण व्यास—I would like to read the information so that the Hon'ble Member............

श्री अध्यक्ष—In order to avoid complication ?

श्री जयनारायण व्यास—Yes, sir, in order to avoid complication.

श्री अध्यक्ष—Is it a long one ?

श्री जयनारायण व्यास—Not very long, Sir.

(विराम)

List of Officers imported into Rajasthan from outside Rajasthan

	Name of the Officer, with designation.	*Pay and emoluments.*
1.	Shri K. N. Wanchoo, Chief Justice	Rs. 4,400/-.
2.	Shri B. G. Rao, I.C.S., Chief Secretary	Rs. 3,000/-.
3.	Shri V. Narayanan, I.A. & A.S., Additional Chief Secretary	Rs. 2,450/- Plus Rs. 600/- Special Pay.
4.	Shri K.D. Billimoria, Inspector-General of Police	Rs. 2,500/- with a staff, car and free unfurnished house.
5.	Shri C.M. Chowdhri, I.F.S., Chief Conservator of Forests.	Rs. 2,500/-
6.	Shri Moti Ram, Chief Engineer, Irrigation	Rs. 2,208/-.
7.	Shri Sundaaram, Chief Accounts Officer	Rs. 2,094/-.
8.	Shri M.K. Kelavkar, Director of Medical & Health Services	Rs. 2,000/-.
9.	Shri Bhajan Lal Chaturvedi, I.A.S., Home Secretary	Rs. 1,812/8/-.
10.	Shri H.K. Thakur, Superintendent	Rs. 1,800/- including Pension.

Page No.3

श्री जसवन्तसिंह--ये इतने सफेद हाथी जो हमारे राज्य में रखे गये हैं या बांधे गये हैं क्या सरकार को यह मालूम है कि इससे अपने राज्य पर कितना बोझ पड़ता है जब कि राजस्थानी भी इससे अधिक अच्छी तरह काम चला सकते हैं और राज्य का खर्च भी कम हो सकता है? क्या यह बात सरकार के ध्यान में है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--यह सरकार की निगाह में है कि ज्यादा तनख्वाह हो और काम कम हो तो एफिसियेन्सी में फर्क आता है और ज्यादा काम हो और कम तनख्वाह हो तब भी एफिशियन्सी में फर्क आता है ।

श्री जसवन्तसिंह--क्या इन सफेद हाथियों का रहना आवश्यक है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--सभी सफेद हाथी हिन्दुस्तान के ही होते हैं। जिनको यहां रखने की आवश्यकता होती है उनको यहां रखा जाता है । ज्यों ज्यों दूसरे हाथी तैयार होते जाते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है ।

श्री जसवन्तसिंह--क्या यह समझा जाय कि सफेद हाथी ही नहीं काले हाथी भी होते हैं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--जो हिन्दुस्तानियों का रंग है उनका भी वही रंग होता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार की निगाह में है कि राजस्थान की सर्विसेज के काम को सम्हालने के लिये उपयुक्त आदमी मौजूद नहीं हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--जो जो व्यक्ति बाहर से आये हैं उनकी जगह यहां के व्यक्तियों को तैयार करके उन्हें रिप्लेस किया जाता है अर्थात् जब यहां के व्यक्ति तैयार हो जाते हैं तो बाहर से आने वाले व्यक्तियों को भेज दिया जाता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मेरा प्रश्न यह है कि इन दस जगहों के लिए जो दस व्यक्ति बाहर से बुलाये गये हैं तो क्या राजस्थान में इन दस जगहों पर काम करने के लिये कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--जिस समय इनको बुलाया गया था उस समय की परिस्थिति को देख कर ही बुलाया गया होगा । ज्यों ज्यों यहां के व्यक्ति तैयार हो रहे हैं बाहर वालों को भेजा जा रहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जो तैयार हो गये हैं तो बाहर वालों को भेजने में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--जो तैयार हो गये हैं उनको उनकी जगह रखा जा रहा है और उनका, जिनको बाहर से बुलाया गया है, पीरियड समाप्त होते ही उनको भेजा जा रहा है ।

Page No.4

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब उन व्यक्तियों को बाहर से बुलाया गया था तो क्या सोच समझ कर ही उनके साथ एग्रीमेन्ट्स किए गये थे ? क्या कुछ केसेज में लम्बे एग्रीमेन्ट्स नहीं किए गए ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—सरकार द्वारा सोच-समझ कर ही एग्रीमेन्ट्स किए गए थे। अगर किसी के साथ लम्बा एग्रीमेन्ट किया गया था तो ऐसी जरूरत समझी गई होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या मैं यह समझूं कि कुछ लोगों को यहां से सरकार भेजना चाहती है किन्तु उनके साथ हुए लम्बे एग्रीमेन्ट्स से कुछ अड़चन आ रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैं समझता हू, नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट्स के बारे में भी यही बात है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस विषय में कोई जवाब नहीं दिया गया है कि कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स के साथ भी लम्बे एग्रीमेन्ट्स से कोई अड़चन आ रही है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५८६ (३७/डी. सी. एम.)

श्री मोतीराम—क्या गृह मंत्री यह बतलायगे:—

गंगानगर सी. आई. डी. ने ऐसी रिपोर्ट की है कि गंगानगर के पुलिस अधिकारी ब्लेक करने वाले लोगों से मिलकर अनाज राजस्थान से बाहर रिश्वत लेकर निकलवाते हैं ? यदि की है, तो उन अधिकारियों के नाम बतलाने की कृपा करें और उन्हें उचित दण्ड देने की व्यवस्था करें।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—चूंकि सी. आई. डी. की रिपोर्ट गोपनीय होती है, इसलिए किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not audible, Sir.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—चूंकि सी. आई. डी. की रिपोर्ट गोपनीय होती है, इसलिए किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा।

श्री मोतीराम—इसका मतलब यह हुआ कि मेरे प्रश्न का उत्तर टाल दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६०

श्री अध्यक्ष—श्री गंगासिंह ।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये) ।

प्रश्न संख्या ५६१

श्री प्यारे लाल—

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५६२ (१६/एफ. एम.)

श्री अध्यक्ष—श्री छीतरलाल शर्मा !

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार टेक्निकल शिक्षा के लिए कोई योजना बना चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो आगामी बजट में कितना व्यय करना चाहती है ?

(ग) किस किस जिले में इस शिक्षा को चालू करने का निश्चय कर चुकी है ?

श्री **नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)**—सरकार ने पांच वर्ष के भीतर १०,५४,०४१) रु. खर्च करके चलायी जाने योग्य टेक्निकल शिक्षा की योजना बनाई है जिसके अंतर्गत हर एक डिविजन के पावर हाउसों से लगे हुए टेक्नीकल स्कूल खोले जावेंगे जिनमें लकड़ी-लोहे का काम, मशीनों को चलाने व मरम्मत करने का प्रारम्भिक काम आदि सिखाये जावेंगे। इस योजना के लिए धन केन्द्रीय सरकार से मिलने की आशा है जिसके लिये पत्र-व्यवहार जारी है। यदि केन्द्रीय सरकार ने योजना को मान लिया तो सन् ५३-५४ में प्रायः ढाई लाख रुपया इस योजना पर व्यय किया जाने की आशा है ।

श्री **जवानसिंह**—प्रश्न का पूरा उत्तर दिया जाना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—मैंने बताया कि इस योजना को पांचों डिविजनों में लागू किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५१३ (७४/सी. एम.)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Chief Minister (General Administration) be pleased to answer :—

(*a*) What is the total number of Government servants drawing more than Rs. 1,000/- per-month ?

(*b*) What is the total amount spent on their salaries and allowances per year ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(a) 67.

(b) Rs. 9,91,196-12-0.

श्री हरिकृष्ण व्यास—In view of the heavy expenditure on the State, does not the Government propose to take steps to reduce the expenditure by reducing the salaries?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—No, not at the expense of efficiency.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार यह समझती है कि एक हजार से ऊपर की तनख्वाह दिए बगैर एफिसिएन्सी नहीं रखी जा सकती है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—एक हजार से ऊपर की तनख्वाह वालों को एक हजार से कम रखने पर एफिसिएन्सी का नुकसान होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्रीजी का ध्यान उस बयान की ओर दिलाऊं जो उनके नेता स्वर्गीय गांधीजी ने दिया था कि वेतन ५०० रुपया से अधिक नहीं देने चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—वह बयान मेरे ध्यान में है और जिस जमाने में वह बयान दिया गया था वह आज के इन भाव-ताव के जमाने से तुलना नहीं खाता। उस जमाने के भाव-ताव मेरे ध्यान में हैं और इस जमाने के भी भाव-ताव मेरे ध्यान में हैं।

श्री जसवन्तसिंह—वह बयान जनरल सर्विसेज के लिये था या केवल मिनिस्टर्स के लिये ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—वह बयान खास तौर पर मिनिस्टर्स के लिये ही था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मंत्रीजी यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि सब मुलाजिमों की तनख्वाह अनुपात से बढ़ी है या एक हजार से ज्यादा पाने वालों की ज्यादा बढ़ी है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—तनख्वाह तो सब ही की बढ़ी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या एक हजार से कम तनख्वाह वाले अफसर रखने पर एफिसिएन्सी में फर्क आ जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—इस सम्बन्ध में मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या यह ठीक है कि राजस्थान मंत्रीमंडल के आधीन काम करने वालों की तनख्वाह मंत्रियों से भी अधिक है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यह सवाल पैदा नहीं होता।

Page No.7

श्री जसवन्तसिंह—क्या एक हजार रुपये से भी कम तन्ख्वाह में सर्विसेज के लिए योग्य व्यक्ति मिल सकते हैं ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—कहीं मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिल सकते हैं; यह Individual posts पर मुनस्सर है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५६४

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister Incharge for Home be pleased to answer :—

(*a*) How many cases of corruption and bribery have been caught by the Anti-Corruption Committee since November, 1952 ?

(*b*) Is it a fact that the following persons were caught red-handed while accepting bribe :——

(*i*) Gopal Lal, Station Master, Jaipur.
(*ii*) Shyam Lal of C.I.D.
(*iii*) Mohammad Khan, Reader.
(*iv*) One Municipal Inspector ?

(*c*) What action has been taken in each case

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—

(*a*) 12 Red-handed cases of corruption and bribery were detected by the Acti-Corruption Department since November, 1952.

(*b*) Yes.

(*c*) Case No. 1 has been handed over to the Ajmer police where it is pending investigation. Cases No. 2 and 3 are pending trial. Case No. 4 is pending investigation with the Deputy Superintendent of Police, City Jaipur.

श्री हरिकृष्ण व्यास—When were the orders for Challan in Cases No. 2 and 3 issued ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—I do not know the exact date, but they are not very old cases.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is the Hon'ble Minister in a position to state whether the orders were issued after the receipt of this question or before the receipt of thsi question ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I presume, before this question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If I put it to him that they were issued after the question was received, is he in a position to contradict it ?

श्री टीकाराम पालीवाल—He is giving some information.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am asking whether he is in a position to contradict the statement if he is asked to. I am asking information.

श्री टीकाराम पालीवाल—I said, I presume the cases were challaned before the questions were received. I cannot say exactly.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Do I take it that the Hon'ble Minister is not in a position to contradict it ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(Perturbed) You can take it.

श्री कानसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलावेंगे कि कितने केसेज पेन्डिग हैं, कितनों का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और बकाया केसेज में क्या हो रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—बाकी के केसों में इन्वेस्टीगेशन हो रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह इन्वेस्टिगेशन कितने दिन पेन्डिग रहेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल—I think every man of commonsense can understand that some cases take more time and some cases take less time.

श्री संतोषसिंह—इस करप्शन डिपार्टमेन्ट ने इस साल में ११२ केसेज में कार्यवाही की है। क्या यह कार्यवाही इस महकमें को कायम रखने के लिये काफी है ?

(श्री अध्यक्ष ने घंटी बजाई)

श्री हरिकृष्ण व्यास—में यह पूछ रहा हूं कि इन केसेज के इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगेगा? यह कॉमन सेंस का मामला कम है। रेडहैंडेड केसेज में आमतौर पर माना जाता है कि समय बहुत ही कम लगता है। इन्हीं केसेज के बारे में पूछ रहा हूं कि इनके इन्वेस्टीगेशन में कितना समय लगेगा ?

श्री संतोषसिंह—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—(श्री हरिकृष्ण व्यास के प्रश्न के उत्तर में) I require notice.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is a directly related supplementary question because I have asked the Government as to what action they have taken. I have also partinently drawn attention to the fact whether they were challaned before or after the question. My idea is whether proper action was taken or not and one of the items of proper action is whether action was taken in proper time. I say that it is a very relevant supplementary and the Hon'ble Minister must be asked to give a reply to it.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—मैंने बतलाया कि चालान हो गया है, कुछ केसेज में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने दिनों से हो रहा है इन्वेस्टिगेशन, यह मैं पूछ रहा हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—I can't say this,

श्री अध्यक्ष—I do not want to enter into any discussion on the question. But the informations wanted by Members must be fully given. (विरोधी दल की ओर से करतल ध्वनि) and no presumption should be made in the House. If the reply will be evasive, then the Members will not insist on the replies being given and I may request the Members to adopt some other remedies which are open to them.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—In this particular question answer can be given but it will be a very detailed answer which might as well be placed on the table of the House. For such answers, however, I think notice must be given.

श्री अध्यक्ष—I again do not want to say anything, but nothing can be presumed. The Member only wants the date as to when the challan was put in, whether it was before the question was tabled or after the question was tabled. This was just a very relevant supplementary question which ought to have been replied.

नेक्सट !

प्रश्न संख्या ५६५

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister-Incharge for Transport be pleased to answer :—

(a) How many Bus permits have been granted on the Jalore-Sumerpur route ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(b) How many Buses run on this route daily ?

(c) Is it a fact that this road is kutcha ?

(d) Is the Government aware that now the condition of the road is almost unusable and dangerous ?

(e) Does the Government propose to undertake the construction of a pucca concrete road on this route ?

(f) If the answer to (e) is in the affirmative, then till what date does it propose to do it ? If it is in the negative, then reasons for it may be given.

श्री **भोलानाथ (यातायात मंत्री)**--(ए) २८।

(बी) ३।

(सी) जालोर से आहोर और सुमेरपुर से तखतगढ़ का हिस्सा कच्चा है और तखतगढ़ से आहोर का हिस्सा ग्रेवल्ड है।

(डी) सड़क काम में लाने लायक है।

(ई) आहोर से जालोर तक सड़क बनाये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(एफ) फंड्स की कमी की वजह से अभी काम शुरू नहीं किया जा सका।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कच्चा रास्ता है वह 'ठीक नहीं' की केटेगरी में आता है या खतरनाक की केटेगरी में आता है ?

श्री **भोलानाथ (यातायात मंत्री)**—'खतरनाक' की केटेगरी में हरगिज नहीं। रोजाना तीन बसें चलती हैं।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**— रोजाना जब तीन बसें चलती हैं तो २८ परमिट किस हिसाब से दिये गये ?

श्री **भोलानाथ (यातायात मंत्री)**—ऑल्टरनेट डेज पर चलती हैं। आर. टी. ओ. से अपने समय का प्रोग्रेम सेट करा लिया है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या खासकर ट्रेफिक के अनुपात से परमिट नहीं इश्यू होते हैं ?

श्री **भोलानाथ (यातायात मंत्री)**—वैसे भी होते हैं और सर्विस की हालत को देखते हुए भी होते हैं।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**--पैसेन्जर के अनुपात से परमिट इश्यू होते हैं या नहीं होते ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--पैसेन्जर के अनुपात से गाड़ियां रोजाना चलती हैं, परमिट का सवाल नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तब परमिट किस अनुपात से इश्यू होते हैं।

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--जिन लोगों की मांग होती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो क्या जितने लोग अर्जियां देते हैं उन सबको परमिट इश्यू होते हैं?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--नहीं। जितने आदमी इस व्यवसाय को रेम्युनरेटिव समझते हैं उतने ही आदमियों को परमिट इश्यू होते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--वही मैं पूछ रहा हूं, इसका क्राइटेरियन क्या हुआ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--यह बिजनेस रेम्युनेरेटिव समझते हैं उतनों को ही परमिट दिये जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। यही क्राइटेरियन है वैहिकल एक्ट के मातहत।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जितने लोग एप्लाई करते हैं वे सभी इस बिजनेस को रेम्युनरेटिव समझते हैं, तो क्या उन सभी को परमिट इश्यू कर दिये जाते हैं?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--जितने लोग एप्लाई करते हैं और जो रेम्युनरेटिव समझते हैं यह तो ठीक है; पर इसके बाद भी दूसरे दूसरे नियमादि और हैं, जिनका भी विचार किया जाता है। पुराने धंधा करने वाले, कोओपरेटिव सोसायटी आदि आदि बातों का भी खयाल किया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--किसको दी जावे, इस संबंध में मेरा सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कितनों को दी जावे, इसके लिए क्या क्राइटेरियन है?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--इसके लिए आर. टी. ओ. डिसाइड करता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्राइटेरियन क्या है?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--मैंने अभी बताया है कि यह सब निर्णय मोटर वैहिकल्स एक्ट के अनुसार होते हैं। आप उसको पढ़ लीजिये।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

श्री हरिकृष्ण व्यास--एक प्रश्न और है।

(विराम)

यदि यह बात ध्यान में लाई जावे कि वहां की सड़क ठीक नहीं है, खतरनाक है तो क्या उसे सुधारने के लिये तुरन्त कदम उठाया जावेगा?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)—सड़क को सुधारने का सवाल जहाँ है उसके बारे में मैंने कहा है कि यह सरकार के ध्यान में है। बसें वहाँ रोजाना चलती हैं। किसी मुसाफिर को, गाड़ी को या किसी कण्डक्टर को कभी कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई। पर खतरनाक बतलाकर अगर हाउस में जोश पैदा करने की बात है तो यह ठीक नहीं है। आप उसे मेटल्ड चाहते हैं तो सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या इससे यह समझा जावे कि किन्हीं दो-चार आदमियों के मरने के बाद ही वह सड़क खतरनाक समझी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५१६

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister-Incharge for Public Works be pleased to answer.—

(a) What are the annual figures of Income and Expenditure of the Kishangarh Power House ?

(b) Is it a fact that the Kishangarh Power House Union has sent repeated communications to the Government detailing out causes of the loss and suggesting methods of reducing the loss ?

(c) Is the Government aware of the fact that the Kishangarh Electric Department Employees Union has repeatedly assured the Government of its co-operation in working for reduction of these losses ?

(d) What steps has the Government taken to listen to their suggestions and to receive and secure their co-operation ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)–(क) किशनगढ़ पॉवर हाउस के सन् १९५१–५२ की आय और व्यय क्रमशः रु०३३८०९) और ६४९९४) हैं।

(ख) ऐसे कोई भी पत्रादि का पता नहीं चलता है।

(ग) सरकार यह बात भी जानती है कि यहां की लेबर ने सहयोग देने की अपेक्षा गड़बड़ पैदा करने की कोशिश अधिक की है। फिर भी दो-तीन इन्जीनियरों ने स्थिति सुधारने की अधिक कोशिश की, परन्तु नतीजा "नहीं" में है। अब एक योग्य इन्जीनियर वहाँ पॉवर हाउस की निगरानी कर रहा है परन्तु उसे भी सहयोग नहीं मिल रहा है।

(घ) उपयुक्त सुझावों पर सरकार सदैव ध्यान देती है और सहयोग यही चाहती है कि प्रत्येक मजदूर अपनी ड्यूटी वफादारी से अंजाम दे। इसके लिये मजदूरों को बार बार समझाया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सच नहीं है कि वहां की आमदनी और खर्च के घोटाले के बारे में और अन्य मामलों के बारे में भी तरह तरह की शिकायतें मन्त्री महोदय को भेजी गईं; इस इरादे से कि वहां जो घाटा है उसे कम किया जा सके।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—रायें भेजीं, उनकी जांच कराई जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—शिकायतें भी भेजीं या नहीं भेजीं।

श्री भोलानाथ—इस तरह की मेरे पास इस समय कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मन्त्री महोदय यह कहने की परिस्थिति में हैं कि वहां से कोई ऐसी रिपोर्ट उनके नोटिस में नहीं आई ?

श्री भोलानाथ—आपने जो लिखा है उसके मुताबिक ही मैंने जवाब तैयार करवाया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह तथ्य नहीं है कि वहां के घोटाले को रोकने और लॉस को रिड्यूस करने के सिलसिले में कोई तजवीज आपके पास भेजी गई ?

श्री भोलानाथ—मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है। अपनी शिकायतें जरूर भेजते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६७

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार शिक्षा के वर्तमान ढंग को बदलना चाहती है ?

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार तथा चारित्रिक शिक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—हां, मिडिल तक की शिक्षा में, कि जिसका पाठ्यक्रम सरकार बनवाती है निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं और किये जा रहे हैं।

(१) हिन्दी को प्रधान और आवश्यक अध्ययन की भाषा बनाना।

(२) सामान्य विज्ञान यानी फिजियोलोजी, केमिस्ट्री, बोटेनी, जूलोजी आदि आदि की मूल भूत प्रारम्भिक बातों के ज्ञान को आवश्यक विषय बनाना।

(३) सामान्य सामाजिक ज्ञान अर्थात् इतिहास, नागरिक शास्त्र, घरेलू अर्थ शास्त्र के प्रारम्भिक ज्ञान को आवश्यक बनाना।

(४) ललित कलाओं और दस्तकारी की आवश्यक शिक्षा।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

(५) फिजीकल ड्रिल।

(६) शारीरिक श्रम और समाज सेवा का क्रियात्मक शिक्षण।

ये सब परिवर्तन व नये पाठ्य क्रम को लागू करके तथा श्रम दान आदि की योजनाओं को शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा क्रियान्वित करा कर किया जा रहा है।

चारित्रिक शिक्षा अध्यापकों के सदाचारपूर्ण जीवन के आदर्श से तो मिलती ही है; उसके अतिरिक्त समय समय पर विद्यार्थियों को इन विषयों पर भाषण और उपदेश दिलाने का प्रबन्ध किया जाता है और सदाचारी और महान् आत्माओं से सम्बन्धित पर्व मनाये जाते हैं।

प्रश्न संख्या ५६८

श्री खेतसिंह—क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के दफ्तर में कितने अहलमद हैं?

(२) वे वहां कितने अरसे से काम करते हैं?

(३) क्या सरकार को मालूम है कि उनमें से बहुतों का अरसे से तबादला न होने के कारण जनता के प्रति उनका व्यवहार दूभर हो गया है?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) एक अकाउन्टेट और १७ लिपिक हैं।

(२) ब्योरा निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या १	नाम तथा २	जोधपुर ट्रेजरी ऑफिस में नियुक्ति की तारीख ३
१.	श्री रूपशंकर अकाउन्टेन्ट	९-७-१९५१
२.	श्री शोधर: अपर डिवीजन क्लर्क	१-७-१९५०
३.	श्री जगरूपमल ,,	१-७-१९५०
४.	श्री ज्ञानमल ,,	१४-७-१९५०
५.	श्री रूपचन्द ,,	१८-४-१९५०
६.	श्री जगदीश लाल ,,	१२-५-१९५१
७.	श्री शंकर नारायण ,,	१४-४-१९५२
८.	श्री मेघदत्त ,,	२२-८-१९५२
९.	श्री सवाई मल ,,	२३-९-१९५२
१०.	श्री किशोर मल (स्टाम्प क्लर्क)	इनकी नियुक्ति की तारीख का पता नहीं चला
११.	श्री रंग राज लोअर डिवीजन क्लर्क	१-१०-१९४९

[श्री जयनारायण व्यास]

१	२	३				
१२.	श्री मोती किशन	,,	..	..	..	१४-१०-१९५०
१३.	श्री केसरी मल	,,	..	..	..	१-१०-१९४७
१४.	श्री रहीम बक्स	,,	..	..	..	१-१०-१९४९
१५.	श्री जगदीश चन्द्र	,,	..	..	..	१४-१०-१९५०
१६.	श्री शिवनारायण	,,	..	..	..	१९-७-१९५०
१७.	श्री तेजराज	,,	..	..	..	२३-८-१९५०
१८.	श्री हसमतुल्लाह	,,	..	..	..	१०-४-१९५१

(३) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री कानसिंह—क्या माननीय मन्त्री यह फरमाते हैं कि श्री किशोर मल की नियुक्ति की तारीख का पता नहीं चला है; क्या सरकार के पास मुलाजिमात का रेकार्ड नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—रेकॉर्ड तो है लेकिन पुराने युनिट्स रेकर्ड इधर-उधर हो जाने से कुछ दिक्कतें जरूर हुई हैं। फिर भी पता चलाने की कोशिश की जा रही है। इसका पता किया जाकर बाद में बताया जा सकता है।

श्री खेतसिंह—सन् १९५० से जो मौजूद हैं क्या उनका ट्रान्सफर नहीं किया जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—आमतौर पर तीन साल तक एक व्यक्ति को एक जगह पर रहना चाहिये। तीन साल बाद भी अगर कोई शिकायत न हो और जरूरत न महसूस हो तो रखा जा सकता है।

श्री जसवन्तसिंह—कुछ कुछ महकमों में एक एक हफ्ते में ही ट्रान्सफर हो जाते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे ध्यान में ऐसा कोई केस नहीं आया।

श्री खेतसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न को ही शिकायत समझ कर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—शिकायत के कारण होने चाहिये अमुक आदमी को हटाने के बारे में। इसके बाद जांच होने पर कार्यवाही की जा सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ट्रान्सफर शिकायतों की वजह से नहीं सिफारिशों की वजह से नहीं किये जाते हैं ?

Page No.16

श्री जयनारायण व्यास—यह तो माननीय सदस्य के दिमाग की उपज है।

प्रश्न संख्या ५६६

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister Incharge for Home be pleased to answer—

(a) Is it a fact that one S. I. Police, named Girbar Dayal Dub at that time stationed at Kotwali, Jaipur, was caught red-handed taking bribe of Rs. 20/- ?

(b) Is it a fact that he was making a demand for Rs. 100/- ?

(c) What action has the Government taken in the matter ?

(d) Is the S. I. P. a friend of one Nanne Khan ?

(e) Is it a fact that protection is being given to him by an ex Minister ?

(f) Will the Government make a full statement ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—(a) Yes.

(b) Yes.

(c) Departmental enquiry is being held in the first instance.

(d) Government have no information.

(e) Government have no information.

(f) There is no need for making a full statement.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that during the last fortnight orde were once issued to hand over this case for chauan and for prosecution ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I said Government have decided to make departmental enquiry and not to hand it over to the Court.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस बीच में ऐसे ऑर्डर इश्यू हो चुके या नहीं कि इनका प्रोसिक्युशन किया जाय ?

श्री टीकाराम पालीवाल—In view of the circumstances of the case and view of the fact that currency notes were not recovered from the person the S. I. himself but from the Manager of the Hotel it was thought preferat to conduct a departmental enquiry rather than to hand it over to Court.

Page No.17

श्री हरिकृष्ण व्यास--My question is, first a decision was taken to hand it over to the police. Two days afterwards this decision was reversed and orders were issued for departmental enquiry. So I want confirmation whether this thing took place or not, whether any decision was taken to hand over the case for chalan or not.

श्री टीकाराम पालीवाल--Decisions are revised and so this question does not arise.

श्री हरिकृष्ण व्यास--This is a question which automatically arises out of it. What was the special reason that this decision was revised?

श्री टीकाराम पालीवाल--I have already said that the facts of the case were such that it was thought preferable and better to have departmental enquiry rather than to put it into Court.

श्री हरिकृष्ण व्यास--What was the special reason for revising the decision?

श्री अध्यक्ष--This is discretionary, next.

प्रश्न संख्या ६००

श्री बृजेन्द्रपाल—

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६०१

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या यातायात मन्त्री (होम) निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में मोटर बसों में जाने वाले यात्रियों के साथ कितना सामान फ्री ले जाये जाने का नियम है ?

(२) इस नियम के विरुद्ध कौन कौन मोटर सर्विस इस फ्री सामान पर भी किराया वसूल करती हैं ?

(३) क्या ऐसी मोटर सर्विसों के बारे में रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के पास कोई शिकायत पहुंची है ?

(४) अगर पहुंची है, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)—(१) २० पौन्ड।

(२) सामान पर किराया वसूल करने की शिकायत जयपुर वाटका सर्विस के विरुद्ध आई हैं, और किसी की नहीं।

(३) उत्तर (२) में आ जाता है।

(४) इसके बारे में प्रादेशिक यातायात अधिकारी ने पूरी जांच कर ली है और यह मामला रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी, जयपुर, के सामने २१-३-५३ को उचित कार्यवाही के लिये रखा जावेगा।

श्री सन्तोषसिंह—क्या २० पौन्ड से ज्यादा वजन किराया देकर भी नहीं ला सकते?

श्री भोलानाथ—अवश्य ले जा सकते हैं।

श्री सन्तोषसिंह—जोधपुर में ऐसे कई केसेज हैं जो २० पौन्ड से ज्यादा वजन नहीं लाने देते।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री जसवन्तसिंह—रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी का पर्सनल कौन कौन हैं?

श्री भोलानाथ—यह प्रश्न अलग है। किस रीजन (region) के विषय में आप पूछते हैं; चार रीजन हैं?

श्री जसवन्तसिंह—सभी की आप बता सकते हैं तो बताइये।

श्री भोलानाथ—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है?

श्री अध्यक्ष—The gazette is being sent to the Hon'ble Members.

प्रश्न संख्या ६०२

श्री भैरूंसिंह। (प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)।

(विराम)

प्रश्न संख्या ६०३

श्री खेतसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान निर्माण के बाद से अब तक राजस्थान से बाहर के कितने व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है?

(२) इनमें से हरिजन और पिछड़ी हुई जाति के कितने व्यक्ति हैं?

(३) इन नियुक्तियों में कितनी नियुक्तियां—

Page No.19

[श्री खेतसिंह]

(i) विशेषज्ञों की,

(ii) बड़े अधिकारियों की,

(iii) और छोटे कर्मचारियों की है ?

(४) क्या इन नियुक्तियों के विषय में कोई विशेष शर्त सरकार ने तय की है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) ४३।

(२) कोई नहीं।

(३) पहले हिस्से की १६, दूसरे हिस्से की २७ और तीसरे हिस्से की कोई नहीं।

श्री हरिदेव जोशी—दुबारा नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास—आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

प्रश्न संख्या ६०४

श्री गंगासिंह—Will the Home Minister be pleased to state:—

(a) Are there any particular rules for laying down traps on corrupt officials while in the act of accepting illegal gratifications?

(b) Do the officials concerned strictly adhere to these rules? If not, what action the Government takes against them?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—(a) No. Though precautions are taken to ensure that the requirements of the law of Evidence Act, are fulfilled.

(b) Does not arise.

प्रश्न संख्या ६०५

श्री तनसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकारी इमारत के इर्द गिर्द २०० फीट की दूरी में क्या कोई मकान नहीं बना सकता है ?

(२) क्या कलेक्टर बाडमेर ने जनकार्य विभाग की सिफारिश पर पुलिस सुपिरिन्टेन्डेन्ट के मकान व डोमीनियम कस्टम के दफ्तर के पीछे की तरफ की जमीन पर शंकर सुनार को मकान बनाने से रोका था ?

[श्री तनसिंह]

(३) क्या उसी व्यक्ति को तीन माह बाद मकान बनाने की छूट दे दी ?

(४) क्या कलेक्टर बाड़मेर ने कचहरियों की नई इमारत के आस पास अभी तक मकान बनाने के लिये नोटिस दे रखा है ?

(५) यह नोटिस किस कानून के अन्तर्गत दिया गया है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(१) पुरानी जोधपुर रियासत में ऐसा हुक्म था कि सरकारी इमारत के २०० फुट इर्द गिर्द नये इमारती पट्टे बिना जन-कार्य विभाग की आज्ञा के नहीं दिये जावें।

(२) हां।

(३) हां, क्योंकि जांच करने पर उसका पट्टा पुराना साबित हुआ और वह जमीन किसी सरकारी कार्य के लिये आवश्यक नहीं थी।

(४) नहीं।

(५) पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या ६०६

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मचन्द।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६०७

श्री तनसिंह—क्या शिक्षामन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

निम्नलिखित तहसीलों में कितनी प्राथमिक पाठशालायें हैं:—

(१) बाड़मेर, (२) शिव।

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—तहसील बाड़मेर में १३ तथा तहसील शिव में ४ प्राथमिक पाठशालायें हैं।

प्रश्न संख्या ६०८

श्री अध्यक्ष—Shri Kast. or Chand, Question No .609. Question No. 608 will be taken after wards as there was a request. (श्री टीकाराम पालीवाल की ओर देख कर) Are you prepared ?

श्री खेतसिंह—I am ready to ask the question.

Page No.21

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—I am ready.

श्री अध्यक्ष—क्वेश्चन नम्बर ६०८।

श्री खेतसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) जब कि पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले पाकिस्तान निवासियों को खुले आम इजाजत दी जा रही है तो राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान से मिलते हुए इलाके के रहने वाले लोगों से उनके पास के मौजूदा शस्त्रों को क्यों पुलिस में जमा किया जा रहा है ?

(ब) क्या सरकार नये लाइसेन्सेज भी वहां के रहने वाले लोगों को देने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—(अ) राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान से मिले हुये इलाकों के रहने वाले लोगों से उनके पास के मौजूदा शस्त्रों को पुलिस में जमा नहीं करवाया जा रहा है। केवल वे ही शस्त्र, जो प्रोहिबिटेड बोर के हैं, अनउपयुक्त लोगों से वापिस जमा कराये जा रहे हैं।

(ब) सरकार उपयुक्त लोगों को सदैव लाईन्सेस देने के लिये तैयार है।

श्री भीमसिंह—गवर्नमेन्ट कौन कौन से बोरों को प्रोहिबिटेड बोर समझती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री) इसके नोटिस मिलने की जरूरत है। ३०३ नम्बर का बोर ऐसा है तथा और भी कई ऐसे हैं।

श्री भीमसिंह—क्या यह सही है कि पुलिस डिपार्टमेन्ट, जो प्रोहिबिटेड बोर नहीं हैं, उनको भी प्रोहिबिटेड करार देकर उनसे वापिस ले रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—ऐसी बात नहीं है।

प्रश्न संख्या ६०६

श्री कस्तूरचन्द—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. भीलवाड़ा से शाहपुरा रोड पर कितनी बसें चलती हैं ?

२. भीलवाड़ा से शाहपुरा सुबह कितनी बसें जाती हैं और शाहपुरा से भीलवाड़ा सुबह कितनी जाती हैं और कितने बजे ये गाडियां स्टार्ट होती हैं और शाम को भी कितनी आती जाती हैं ?

३. क्या सरकार ने इन बसों की बोडीज व पुर्जों को ठीक हालत में देखने की भी कोशिश की है ?

४. क्या सरकार के यह भी ध्यान में है कि इन बसों में मनमानी सवारियां भरकर ले जाई जाती हैं ?

[श्री कस्तूरचन्द]

५. अगर ले जाई जा रहीं हैं, तो बनेड़ा थाना चालान क्यों नहीं करता है ?

६. क्या बनेड़ा थानेदार व सिपाही भी यातायात के लिये इन बसों में मुफ्त आते जाते हैं?

७. अगर आते जाते है तो सरकार उसके लिए क्या करेगी ?

८. क्या एक आंख वाले यानी काने आदमी को भी मोटर चलाने का लाइसेन्स दिया जा सकता है ?

श्री भोलानाथ—१. आठ।

२. भीलवाड़ा और शाहपुरा के बीच गाड़ियों का आवागमन निम्न प्रकार है:—

—भीलवाड़ा शाहपुरा वाया बनेड़ा—

भीलवाड़ा रवानगी	शाहपुरा पहुंच
(१) ८ बजे प्रातः	११ बजे
(२) २.३० बजे मध्याह्न	५.३० बजे शाम
(३) ४.३० बजे शाम	७.३० बजे शाम

शाहपुरा रवानगी	भीलवाड़ा पहुंच
७.३० बजे प्रातः	१०.३० बजे प्रातः
९.०० बजे प्रातः	१२.०० बजे मध्याह्न
डांक ३.०० बजे मध्याह्न	६.०० बजे शाम (डाक)

भीलवाड़ा शाहपुरा वाया सांगानेर—

भीलवाड़ा रवानगी	शाहपुरा पहुंच
७ बजे सुबह	९.३० बजे सुबह

शाहपुरा रवानगी	भीलवाड़ा पहुंच
३ बजे दोपहर	५.३० शाम

३. हां।

४. नहीं। जब कभी कोई गाड़ी अधिक सवारियां ले जाती हुई पाई गई तो उनका चालान किया गया।

५. बनेड़ा थाना जरूर चालान करता है।

६. नहीं।

७. प्रश्न ही नहीं उठता।

८. नहीं।

श्री प्रभुदयाल—मोटरों के खल्लासी कौन कौन हैं ?

एक सदस्य—रास्ते के स्टापेज का भी समय बता दीजिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Si , it is.... (अश्रव्य)

श्री कस्तूरचन्द—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुल लाइसेन्स कितने दे रखे हैं ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—आठ ।

श्री अध्यक्ष—यह इन्फार्मेशन तो प्राइवेटली ही पूछलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री कस्तूरचन्द—लाइसेन्स जो .. ..

श्री अध्यक्ष—Order ! Question No. 610.

प्रश्न संख्या ६१०

श्री कस्तूरचन्द—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

१. भीलवाड़ा से शाहपुरा जो रोड बनी है क्या उसके दोनों तरफ दरख्त लगाने की स्कीम है ?

२. यदि हां, तो यह काम कब तक शुरू होगा ?

३. अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

४. अगर दरख्त लगाये जायेंगे तो क्या ठेके से लगाये जायें ?

५. अगर ठेके से नहीं, तो क्या सरकारी देख-रेख से लगाये जायेंगे ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—

१. कोई विशे स्कीम नहीं है ।

२. प्रथम प्रश्न के उत्तर की दृष्टि में यह सवाल पैदा नहीं होता ।

३. दरख्त लगाने का कार्य, असली काम पूरा हो जाने के पश्चात् शुरू किया जायगा ।

४. नहीं । साधारणतया यह कार्य ठेके पर नहीं किया जाता है ।

५. सड़क पर रहने वाली सरकारी गैंग ही इस काम को करती है ।

श्री कस्तूरचन्द—क्या सरकार यह बतायेगी कि कौन कौन सी सड़क पर दरख्त लगेंगे ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—नोटिस की आवश्यकता है ।

प्रश्न संख्या ६११

श्री तनसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बाडमेर की हाईस्कूल को इन्टरमिडिएट कॉलेज बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) बाडमेर से नजदीक से नजदीक इन्टर कॉलेज कितना दूर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—(१) फिलहाल नहीं । राजस्थान सरकार की आर्थिक दशा को दृष्टिकोण में रखते हुए अन्य ऐसे मामलों के साथ इस पर भी विचार किया जायगा ।

(२) बाडमेर से नजदीक से नजदीक जोधपुर इंटर कालेज है जो बाडमेर से १३० मील दूर है ।

प्रश्न संख्या ६१२

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१३

श्री अध्यक्ष—श्री संग्रामसिंह ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित —कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६१४

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूसिह !

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६१५

श्री अध्यक्ष—श्री हरिशंकर ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या मंत्री, गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि गावों में एक विशेष जाति के लोग गरीब किसानों के मवेशी चुरा चुरा कर ले जाते हैं और इसके उपलक्ष में कुछ रुपया उनके मालिकों से ऐंठ कर मवेशियों को फिर वापिस लौटा देते हैं ?

(ख) यदि सरकार के समक्ष ऐसी घटनाएं आई तो उनकी बाबत क्या सरकार ने कोई जांच की ?

(ग) उस जांच का क्या नतीजा रहा ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—(क) हां, सरकार को मालूम है कि चोरी करने वाले लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, यद्यपि किसी जाति विशेष के लिए यह नहीं कहा जा सकता है।

(ख) हरेक मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—अब तक जांच में क्या पता लगा है कि किस विशेष जाति का यह काम है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६१६

श्री खेतसिंह—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) जोधपुर से सेतरावा जानेवाली व जोधपुर से शेरगढ़ जानेवाली सड़कों पर मेसर्स सांघी ब्रॉदर्स को कितने परमिट मिले हुए हैं?

(ब) जब कि मेसर्स सांघो ब्रॉदर्स के कारिन्दों का बर्ताव मोटर में बैठने वाली सवारियों के साथ उपयुक्त नहीं है जिसकी कि कई बार शिकायतें भी की गई हैं फिर भी इस परमिट होल्डर को इतने अधिक परमिट क्यों दिये गये हैं?

(स) क्या यह सही है कि मेसर्स सांघी ब्रॉदर्स एक बहुत मालदार फर्म है जिससे जोधपुर ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर व ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर दोनों मिले हुए हैं, जिनकी शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है?

(ड) मेसर्स सांघी ब्रॉदर्स को जोधपुर डिविजन में कुल कितने परमिट मिले हुए हैं?

(ई) क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों को मेसर्स सांघी ब्रॉदर्स फी लाते हैं?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—(अ) दो।

(ब) रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथेरिटी, जोधपुर के पास इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(स) सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है जिससे यह ज्ञात होता है कि ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर व इन्सपेक्टर मेसर्स सांघी ब्रदर्स से मिले हुए हैं। शिकायत जब प्राप्त होगी तो उसकी जांच अवश्य की जायगी।

(ड) दस।

(ई) इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

Page No.26

प्रश्न संख्या ६१७

श्री खेतसिंह—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सही है कि सेतरावा फलौदी रोड पर एक ही परमिट होल्डर को सब परमिट दिये गये हैं ?

(ब) क्या यह सही है कि वह परमिट होल्डर अपनी इच्छानुसार जब व जिस रोज चाहता है मोटर चलाता है वरना सवारियों को वापिस जाना पड़ता है ?

(स) क्या यह सही है कि वह अक्सर सवारियों को रात के १.३० बजे सेतरावा लाकर छोड़ देता है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—(अ) नहीं।

(ब) नहीं।

(स) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली।

प्रश्न संख्या ६१८

श्री अध्यक्ष—श्री संग्रामसिंह !

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६१९

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या मंत्री, गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर शहर में १९५२-५३ में अब तक कितने लोगों में जेब काटने की वारदातें हुई ?

(ख) पुलिसने कितने केसेज कोर्ट में चालान किये और उनमें से कितनों को सजा मिली ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—(क) जयपुर शहर में सन् १९५२-५३ म ४३ वारदातें जेब तराशी की हुई व सन् १९५३ में अब तक ४ वारदातें हुई।

(ख) सन् १९५२ में २५ केसेज का चालान किया गया जिनमें ८ को सजा मिली, और १९५३ में २ केसेज का अदालत में चालान किया गया जिनमें से एक को सजा मिली।

प्रश्न संख्या ६२०

श्री तेजपाल—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान राज्य म, विशेषकर भरतपुर जिले में महसूल की चोरी के कितने अभियोग पकड़ हु ?

[श्री तेजपाल]

(२) इनमें से कितनों को विभागीय सजा दी है ?

(३) कितनों को जुडिशियल के सुपुर्द किया गया है ?

(४) कितनों को करने का नि 'य किया जा चुका है ? इस निर्णय को ए कितने दिन हो गये हैं ? इस देरी का कारण क्या है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—(१) भरतपुर के इलाके में १९१५ अभियोग दर्ज हुए जिनमें ५५७ चोरी महसूल के हुए ।

(२) भरतपुर के चोरी महसूल के ५५७ अभियोगों में से ४८८ का विभागीय निर्णय हुआ । शेष ६९ का निर्णय नहीं हुआ है ।

(३) गत वर्ष के जो अभियोग भरतपुर में निर्णय किये गये उनको विभागीय दंड दिया गया । जुडिशियल में चालान करने का कोई निर्णय किसी अभियोग में नहीं लिया गया ।

(४) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न नम्बर ३ के उत्तर में आ जाता है ।

प्रश्न संख्या ६२१

श्री तेजपाल—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या जयपुर जिले में कस्टम के अभियुक्तों पर चलाये जाने वाले मुकद्दमों के विषय में कोई ऐसा नियम है कि जिन व्यक्तियों या पार्टियों के खिलाफ विभाग मुकदमे चलाना तय करदे और यदि वे मुकदमे साल के अन्दर अदालत में पेश नहीं किये जा सकें तो उनकी कार्यवाही रद्द करदी जाती है ?

(ब) यदि हां, तो क्या यह राजस्थान के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार लागू है ? यदि नहीं तो इस भिन्नता का कारण क्या है ? यह नियम मत्स्य में किस प्रकार लागू है ?

श्री भोलानाथ—(अ) ऐसा कोई नियम नहीं है ।

(ब) राजस्थान में सम्मिलित होने वाली विभिन्न रियासतों में कस्टम का जो कानून प्रचलित था राजस्थान रेग्युलेशन ऑफ कस्टम ड्युटीज ऑर्डिनेन्स, स. ,१९५० के अनुसार वही कानून उस प्रदेश में अब भी लागू रक्खा गया है । मत्स्य कस्टम ऑर्डिनेन्स स. १९४८ जो भूतपूर्व मत्स्य संघ के प्रदेश में उपरोक्त नियम के अन्तर्गत प्रचलित है उसमें भी ऐसी कोई धारा नहीं जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के खिलाफ घटना के एक वर्ष के पश्चात् कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता ।

प्रश्न संख्या ६२२

श्री घासीराम—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) हाई स्कूल तिजारा (अलवर) के पिछले पांच सालों का बजट कितना फी साल

[श्री घासीराम]
रहा है; और कितना खर्च रहा है? इस साल का कितना बजट है और कितना इस साल खर्च किया जायगा?

(ख) बजट से कम खर्च क्यों किया गया है?

(ग) सन् १९५३-५४ के बजट में क्या कॉमर्स और साइन्स क्लास खोलने की सरकार व्यवस्था करेगी?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—(क) हाई स्कूल तिजारे का पिछले साल का बजट निम्न प्रकार से रहा है:—

सन् १९५०—५१	रु० ३२,०९६)
सन् १९५१—५२	रु० ३५,१९६)
सन् १९५२—५३	रु० २७,२४६)

सन् १९४८-४९ व १९४९-५० का बजट हाईस्कूल्स का अलग नहीं था, सारे हाई स्कूलों का एक ही बजट था।

इस वर्ष बजट की पूरी रकम खर्च की जावेगी अलबत्ता वेतन और अलाउन्स के सीगे में कुछ बचत रह सकती है।

(ख) रकम बजट के अनुसार ही खर्च की गई है।

(ग) आगामी वर्ष का बजट प्राप्त होने पर तथा आवश्यकतानुसार फन्ड्स प्राप्त होने पर इस विषय पर विचार किया जावेगा।

प्रश्न संख्या ६२३

श्री **दिलीपसिंह**—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) मेनार (वल्लभनगर तहसील का गांव) की स्कूल जिस स्थान पर लगती है वहां कुल कितने कमरे स्कूल के काम में आते हैं?

(आ) वे कमरे कितने फीट लम्बे, चौड़े व ऊंचे हैं?

(इ) उस स्कूल में ब्लेक बोर्ड कितने हैं और वे किस साइज के हैं?

श्री **नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)**—(अ) मेनार के स्कूल के लिये ३ कमरे काम में आते हैं।

(आ) उनमें से एक कमरा १५$\frac{3}{4}$'×१५$\frac{3}{4}$'×१५$\frac{3}{4}$' है, एक १६$\frac{3}{4}$'×१६$\frac{3}{4}$'×१०' है तथा एक ७$\frac{3}{4}$'×७$\frac{3}{4}$'×१०' है।

(इ) एक ब्लेक बोर्ड है जो २ फीट १० इन्च लम्बा व २ फीट ४ इन्च चौड़ा है।

श्री **दिलीपसिंह**--ब्लेक बोर्ड इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद में पहुंचाया गया या पहले से ही था?

श्री नाथूराम मिर्धा—ब्लेक बोर्ड तो वहां पहले से ही था।

श्री दिलीपसिंह—वहां पर कितने बच्चे पढ़ते हैं ?

श्री अध्यक्ष—This is a different question.

श्री नाथूराम मिर्धा—यह अलग प्रश्न है।

श्री दिलीपसिंह—मैं कमरों के डाइमेन्शन को देखते हुए यह पूछना चाहता हूं कि जब उस स्कूल में १६० लड़के पढ़ते हैं तो क्या वे कमरे लड़कों के लिये ब्लेक होल ऑफ कलकत्ता से कम हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं इस बात को मानता हूं कि लड़कों की संख्या ज्यादा है।

श्री दिलीपसिंह—मेरे पूछने का मतलब यह है कि जहां पर स्कूल चल रहा है वह स्थान डाक बंगला है। वहां पर मुसाफिर कहां ठहरेंगे और बच्चे कहां पढ़ेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा—बच्चे पढ़ेंगे जहां पढ़ते हैं और मुसाफिर ठहरेंगे जहां पहले ठहरते थे।

श्री दिलीपसिंह—कमरे तो वही हैं दूसरे तो हैं नहीं, फिर कहां मुसाफिर ठहरेंगे और कहां लड़के पढ़ेंगे ?

श्री जवानसिंह--दिन को तो वहां बच्चे पढ़ेंगे और रात को मुसाफिर ठहरेंगे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६२४

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या निर्माण विभाग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या चाकसू तहसील में चाकसू कस्बे से कोट खावदा तक फेयर वदर रोड बना हुआ है।

(ख) यदि है, तो यहां पक्की सड़क कब तक बनादी जावेगी ?

(ग) चाकसू तहसील और जयपुर तहसील में कहां कहां १९५२-५३ में नई सड़कें बनाई जावेंगी ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—(क) हां, बनी हुई है।

(ख) इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ग) १९५२-५३ के साल के समाप्त होने में इस माह के ८ ही दिन बाकी रहे हैं, अतः इन दिनों में कोई सड़क नहीं बनाई जा सकती।

प्रश्न संख्या ६२५

श्री महादेवप्रसाद—क्या मंत्री पृथक राजस्व विभाग निम्नांकित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) राजस्थान के बाहर से जूते तथा अन्य चमड़े की चीजें आयात होती हैं, उन पर सरकार क्या कस्टम चार्ज करती है ?

(२) क्या सरकार ऐसी छोटी रोजीवालों के प्रति भी कुछ सहानुभूति रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(३) राजस्थान के छोटे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार इस आयात पर कस्टम अधिक बढ़ायेगी ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—(१) राजस्थान के बाहर से जूते तथा अन्य चमड़े की वस्तुओं के आयात पर कस्टम टैरिफ के आइटम नम्बर १०७ व ३२७ के अनुसार ६ पर्सेन्ट की दर से कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है ।

(२) राजस्थान से जूते अथवा चमड़े की बनी हुई चीजों के निर्यात पर कस्टम्स टैरिफ आईटम नम्बर १०७ व ३२७ के अनुसार ऐसे छोटे धंधों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही कोई कस्टम्स कर कायम नहीं किया गया है । इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की सहानुभूति ऐसी छोटी रोजी वालों के प्रति प्रत्यक्ष है ।

(३) जूते जैसी वस्तुओं के आयात पर पहले से ही ६। परसेन्ट कस्टम्स कर लिया जाता है जबकि निर्यात कर कतई नहीं लिया जाता है। ऐसी सूरत में आयात कर की दर अधिक बढ़ाना या उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना न सिर्फ अनुचित होगा बल्कि अवैधानिक भी होगा ।

श्री संतोषसिंह—क्या सरकार की सहानुभूति जूतों पर ही है या दूसरी चीजों पर भी है ?

श्री हिम्मतसिंह—क्या जूते सस्ते पड़ते हैं या महंगे पड़ते हैं ?

श्री चंदनमल—आपके तो सस्ते ही पड़ते हैं ।

श्री अध्यक्ष—No vollies of questions about shoes.

प्रश्न संख्या ६२६

श्री भैरवलाल काला बादल—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(१) झालावाड़ की खानपुर तहसील की जनता पिछले कई वर्षों से हाई स्कूल की मांग कर रही है ?

(२) यदि हां, तो उनकी मांग पर क्या विचार हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—(१) हां।

(२) राजस्थान सरकार की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए तथा उपयुक्त धन प्राप्त होने पर इस विषय पर अन्य ऐसे मामलों के साथ विचार किया जावेगा। यदि इस ग्राम की प्रजा की ओर से उचित सहायता प्राप्त हो तो इस पर जल्दी विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—Now we come to the questions which were left on the 18th March, 1953. Questions which were to be replied to by the Chief Minister.

प्रश्न संख्या ४७६

श्री तेजसिंह—

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४७७

श्री जयनारायण व्यास—अभी इस प्रश्न का उत्तर आया नहीं, मैं यह देख रहा हूं। The questions have been mixed up.

श्री जसवन्तसिंह—Here, here;

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ४८१

श्री छीतरलाल—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें:—

(क) राजस्थान सरकार के मुलाजिमान का १-४-५० से जो फिक्सेशन किया जाना रक्खा गया है उसके मुताबिक तमाम जगह हो गया है या नहीं?

(ख) अगर हो चुका है तो बून्दी जिले के जकातियान कस्टम, माल के पटवारियान, शफाखाने के कम्पाउन्डर्स, फोरेस्ट के जकातियान व क्लर्कस, पुलिस के क्लर्कस का फिक्सेशन तय नहीं हुआ है?

(ग) अगर इस वक्त किया जा चुका है तो इनको उसके मुताबिक तनख्वाह न मिलने का कारण क्या है?

श्री जयनारायण व्यास—लगभग सबही विभागों में हो गया है। यत्र तत्र कुछ सर्विसेज का बाकी है जो शीघ्र ही समाप्त कराया जा रहा है।

१. बूंदी के कस्टम के नाकेदारों का फिक्सेशन हो चुका है। नये वेतन श्रृंखला में फिक्स किये जाने की कार्यवाही हो रही है। वेतन का बिल अदायगी के लिये भेजा जा चुका है। ट्रेजरी ने कुछ आक्षेप किये हैं इनके निर्माण होने पर अदायगी होगी।

२. बूंदी में ९५ पटवारी हैं जिनमें से ७६ पुराने स्केल ४०-२-६० में हैं और १९ नये स्केल ४०-१-५५ में हैं जो अपने अपने स्केल की तनख्वाह पा रहे हैं इन लोगों के फिक्सेशन की भी आज्ञा जारी हो चुकी है।

३. बूंदी के कम्पाउन्डर्स का फिक्सेशन हो चुका है। नये स्केल के अनुसार वेतन चुका दिये जाने की कार्यवाही हो रही है।

[श्री जयनारायण व्यास]

४. फोरेस्ट के सबॉर्डिनेट एग्जिक्युटिव स्टॉफ (Subordinate Executive Staff.) का फिक्सेशन अभी नहीं हुआ, समय लगेगा। चीफ कंजर्वेटर के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

५. पुलिस विभाग को विभिन्न सर्विसेज का एकीकरण करीब २ समाप्त हो चुका है। मुलाजिमान के फिक्सेशन के कागजात की जांच दफ्तर हिसाब में हो रही है।

श्री छीतरलाल—क्या इसका असर अगले बजट पर नहीं पड़ेगा ?

श्री जयनारायण व्यास—कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे मामलों को ध्यान में रख कर पहले से बजट में गुंजाइश रखी जाती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४८२

श्री संतोषसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार ने जब पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट कायम कर रखा है तो फिर दूसरे हर एक डिपार्टमेन्ट ने अपनी अपनी पब्लिसिटी ब्रांच अलग २ क्यों खोल रखी है ?

(ख) क्या इससे सरकार को हानि नहीं होती है ?

श्री अध्यक्ष—(When the Chief Minister could not come out of his papers for a long time.) What is the difficulty.

श्री जयनारायण व्यास—Some questions were addressed to the Chief Minister and some to the Finance Minister. I have got at the moment only those questions which were addressed to the Chief Minister.

श्री एच. के. व्यास—Is the Chief Minister particularly uncomfortable on this question ?

श्री जयनारायण व्यास—The Chief Minister is always comfortable. No opposition can make him uncomfortable.

श्री जसवन्तसिंह—Sometimes that may.

श्री एच. के. व्यास—Is there any reason for it ?

श्री जयनारायण व्यास—No. It was a question relating to the Publicity Department which might perhaps have been diverted to the Home Department because the Publicity Department is uuder that Department. But I can answer the question very well now.

श्री एच. के. व्यास—That is not the point.

श्री जयनारायण व्यास—पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट जनरल पब्लिसिटी के लिये कायम किया गया है लेकिन अगर अलग २ विभागों के लिये पब्लिसिटी ऑफिसरों की जरूरत हो तो अलग २ पब्लिसिटी ऑफिसरों को कायम करने में सरकार फायदा समझती है। इसमें सरकार को कोई हानि नहीं होती

[श्री जयनारायण व्यास]

क्योंकि प्रकाशन ज्यादा होता है और पब्लिसिटी का जो अफसर अलग अलग विभागों के साथ अटैचमेंट रखता है वहां उस विभाग के काम से आसानी से वाकिफ होता है जो जनरल पब्लिसिटी का ऑफिसर आसानी से नहीं कर सकता है।

प्रश्न संख्या ४८६

श्री एच. के. व्यास—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Who had placed an order for the installation of loudspeaker arrangements in the Rajasthan Legislative Assembly Chamber ?

(b) What has been the cost of installation ?

(c) Were any tenders invited ?

(d) If the answer to the part (c) is in the negative, will the Government state the reasons why it was not done ?

(e) Is the Government aware that the worst type of material has been used ?

(f) Would the Government consider ordering an inquiry into the matter ?

श्री जयनारायण व्यास—The cost of the sound system in the Rajasthan Legislative Assembly Chamber may be approximately shown as under:—

(1)	Provision of wood work for a new ceiling for the whole room, as the height of the room was such that speech could not be heard in the room. The ceiling has been lowered by about 12ft. by providing beams and supports throughout. The cost of this work was about Rs. 5,000	Rs. 5,000
(2)	A special sheeting for the ceiling has cost about Rs. 4,000	Rs. 4,000
(3)	Tranches for all the wires etc. and other works like special stands cost about Rs. 3,000	Rs. 3,000
(4)	The equipment wich included individual microphones, speakers: as also the duplicate amplifier system, special switches etc. cost about Rs. 44,000.	Rs. 44,000

The sanction for installing the equipment was decided upon just a week before the Assembly was started. It was, therefore, not possible to advertise and wait for replies etc. But enquiries were made in Bombay and the equipment taken from the manufacturer's representatives i. e. representatives of the Radio Corporation of America, who are the only people that could supply the equipment immediately from stock. Their prices are all standard ones.

[श्री जयनारायण व्यास]

The special point required in this connection was that the equipment should be such as could be re-used in a new Hall that was to be built at a later date. The equipment includes a specially shielded wire, which is very expensive. As each unit is controlled separately, enormous lengths of this material had to be used.

In comparison, it may be stated that the installation at Delhi is heard to have cost over Rs. 2 lacs. Exact figures will be furnished later. The installation in Madras cost Rs. 1 lac and twenty thousand, so that there is no justification for the statement that the cost was excessive. It was with greatest difficulty that the material was secured in time and the installation completed.

Of course for a man in the street, who looks at an ordinary loudspeaker with an amplifier and microphone it is difficult to realise the amount of work and the amount of equipment that is required in an installation of this type.

श्री एच. के. व्यास—Is the Government aware that the Company is probably classed amongst the best but the material that has been used is the worst that they could produce?

श्री जयनारायण व्यास—I do not agree with the views of my Hon'ble friend. If the Company is best then it cannot be worst except that the Member might have some different opinion about the material.

श्री एच. के. व्यास—Is the Hon'ble Minister aware that the material that has been used is of the lowest class out of the types which the Company produces?

श्री जयनारायण व्यास—It is of the standard class.

श्री जसवन्तसिंह—Sir, In the first session of the Assembly there was an installation of microphones. What defect was detected in that installation that such a heavy expenditure has been incurred on this new installation?

श्री जयनारायण व्यास—यह जो इन्स्टालेशन किया गया था तो एक बात का ध्यान रखा गया था कि अगर एसेम्बली का हॉल यहां से उठा कर दूसरी जगह ले जाया जाय तो वहां भी यह इन्स्टालेशन उपयुक्त हो सके, इसलिये ऐसा इन्स्टालेशन करना जरूरी था जो सब जगह काम में आ सके।

[श्री जयनारायण व्यास]

कीमत के बारे में जो शोरगुल किया जाता है वह ठीक मालूम नहीं पड़ता। और जगहों से जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ है कि देहली के हाउस में इन्स्टालेशन पर २,००,००० रुपये का खर्चा आया है और मद्रास में १,२०,००० रुपयों का खर्चा आया है। तो यह जो मशीनरी है वह कीमती है और इसमें खर्चा ज्यादा लग जाता है। यहां स्टेन्डर्ड खर्चा लगा है तो स्टेन्डर्ड चीज मिली है।

श्री जसवन्तसिंह—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। जब कि हमें यह कहा जाता है कि हमारी माली हालत खराब है तो यह नया इन्स्टालेशन क्यों मंगवाया गया, जब कि पहले जो इन्स्टालेशन करवाया गया था वह सेटिसफेक्ट्री था और नया अनसेटिसफेक्ट्री है।

श्री जयनारायण व्यास—मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। हम ऐसा सामान लगाना जरूरी था जो दूसरी जगह भी काम में आ सके। हमारी माली हालत अच्छी नहीं थी और मुमकिन है अब भी उतनी अच्छी नहीं है कि हम ज्यादा रुपया लगा सकें; पर बहुत से कामों में जरूरत को देखते हुए ज्यादा खर्चा करना ही पड़ता है।

श्री एच. के. व्यास—जब सरकार के ध्यान में पहले सेशन से यह बात चल रही थी तो एक हफ्ते पहले ही ऑर्डर क्यों दिया ?

श्री जयनारायण व्यास— 'Make-Shift arrangement'' था।

श्री एच. के. व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि एक हफ्ते पहले ही ऑर्डर क्यों दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके कागजात एक सप्ताह पहले ही मेच्योर्ड हुए थे इस लिये एक हफ्ते पहले ही ऑर्डर दिया गया।

श्री जसवन्तसिंह—क्या बजट में इसके लिये प्रोविजन रखा गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—प्रोविजन रखना चाहिये था। अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं निश्चित उत्तर दे दूंगा।

श्री एच. के. व्यास—क्या टेन्डर नहीं लिये जाँय ? क्या इसके लिये योजनाबद्ध प्रयत्न किये गये थे ?

श्री जयनारायण व्यास—This is rather an Insinuation than a question.

श्री हरिदेव जोशी—माननीय मुख्य मंत्री ने फरमाया कि हाउस को दूसरी जगह ले जाये जाने की सूरत में भी यह इन्स्टालेशन काम में आ सके इस लिहाज से यह इन्स्टालेशन किया गया है तो क्या किसी अधिक बड़े मकान में बैठ कर हाउस की बैठक करने का विचार है ?

श्री जयनारायण व्यास—गरम स्थान भी हो सकता है।

Page No.36

श्री एच. के. व्यास—ऐसा क्या कारण था कि एक हफ्ते पहिले ही आॅर्डर दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

श्री सन्तोषसिंह—सी. पो. कृष्ण स्वामी द्वारा यह इन्स्टालेशन किया गया है क्या ?

श्री जयनारायण व्यास—इन्स्टालेशन करने वाले व्यक्ति के नाम से मुझे परिचय नहीं है ।

श्री एच. के. व्यास—क्या सरकार मशीनरी के जानकार एक्सपर्ट आदमियों की कमेटी बना जाँच करवाने को तैयार है ?

श्री जयनारायण व्यास—चूंकि अच्छे से अच्छे मशीनरी के एक्सपर्ट आदमियों के द्वारा यह खरीदा गया है अतः इस बारे में जांच करवाने की सरकार कोई आवश्यकता नहीं समझती ।

श्री एच. के. व्यास—इसे सरकार ने खरीदा है या किसी कन्ट्रेक्टर से कन्ट्रेक्ट किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—अगर कन्ट्रेक्टर से कन्ट्रेक्ट करके खरीदा गया है तो भी सरकार ने कीमत दी है और अगर सरकार ने खरीदा है तो भी सरकार ने पैसे दिये हैं। किसके जरिये खरीदा गया है, इसके उत्तर के लिए नोटिस की जरूरत है ।

श्री एच. के. व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि इस इन्स्टालेशन को सरकार ने खरीदा है या इसके लिये कन्ट्रेक्ट किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—अन्डर एक्सपर्ट एड्वाइज खरीदा गया है, यह मैं इस समय बता सकता हूँ। कौन कौन इसके खरीदने में शरीक थे इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री एच. के. व्यास—माननीय अध्यक्ष, लाउडस्पीकर के सम्बन्ध का प्रश्न है और माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह मालूम नहीं है कि यह डिपार्टमेंटल्ली खरीदा गया है या इसका ठेका दिया गया था ।

श्री जयनारायण व्यास—माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है कि यह प्रश्न सरकार के किस डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक रखता है ? जितना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक रखता है उतना ही उत्तर दिया गया और अगर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है तो वह इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से अलग प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, my question is whether the work was done departmentally or by a contract.

श्री जयनारायण व्यास—His question was wrongly addressed. It should have been addressed to the Minister Incharge Electricity. He can give details of the agency employed for the purpose.

Page No.37

श्री एच. के. व्यास—Is the Government unaware yet whether the work was done on a contract basis or a departmental basis ?

श्री जयनारायण व्यास—The Government is aware.......................

श्री अध्यक्ष—This is a completely independent question and in view of the nature of the question that the Member has tabled, this supplementary does not arise. If the Member wants further information he can table another question.

(विराम)

The question-hour is over.

श्री जयनारायण व्यास—Shall I answer the remaining questions tomorrow ?

श्री अध्यक्ष—Their replies will be placed on the Table of the House.

श्री एच. के. व्यास—Mr. Speaker, Sir, The questions were placed on some previous day, but because of the absence of the Chief Minister they were postponed for today. Thus even if the question-hour may be over, I think more time should be allowed and these questions may be answered in the House.

श्री जसवन्तसिंह—You have not been listened to.

श्री अध्यक्ष—Ordinarily we have devoted one full hour that day and there was no time left. Even if these questions were called upon there would have been no time and thus the replies would have been placed on the Table. Now the replies of these will be laid on the Table. Members can see these replies and if they need further information they can table further questions.

(१८ मार्च, १९५३ को मुख्य मंत्री से सम्बन्धित शेष प्रश्नों तथा उनके उत्तरों के हेतु परिशिष्ट २ देखिये)

विधान-कार्य

राजस्थान राज्य सुरक्षा विधेयक

The Chairman of the Select Committee of the Security of the State Bill, 1952, has reported that Shri Indernath Modi having resigned his seat from the Rajasthan Legislative Assembly, a vacancy has occurred in the Select Committee on the Rajasthan Security of the State Bill, 1952, of which he was a Member. This vacancy is hereby reported as required by Rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business for such action as the House may think necessary.

Page No.38

[श्री अध्यक्ष]

So there are 10 Members including the Advocate-General. Is it the will of the house to add one more Member or will it continue to function with the personnel which are at present there ?

(आवाज "May Continue")

श्री अध्यक्ष—I think it is the will of the House. So we need not add one more Member.

राजस्थान कृषि आय-कर विधेयक

Similarly the Chairman of the Select Committee on the Rajasthan Agricultural Income-tax Bill, 1952, has reported that Shri Madan Mohan, Division No. 87, having been declared unseated by the Election Tribunal a vacancy has occurred in the Select Committee on the Rajasthan Agricultural Income-tax Bill, 1952. The vacancy is hereby reported as required by Rule 127 of the Rules of procedure and Conduct of Business for such action as the House may deem necessary.

So, there are 23 Members of this Committee including the Advocate-General. If the House wants to nominate or elect any Member we can do so, otherwise the Committee can function with its present personnel.

(आवाज "कोई आदमी नहीं")

So the Committee should proceed with the personnel which it has already got.

Next. General Discussion on the Budget.

याचिका समिति की बैठक

श्री जवानसिंह—अभी मेरे पास ऑफिस से एक नोटिस आया है जिसमें यह बतलाया गया है कि आज ९.३० बजे पिटिशन कमेटी की मीटिंग होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन की जब बैठक हो रही हो तब ऐसी और किसी सब-कमेटी की बैठक हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष—It was in viw of the fact that the 24th was declared a holiday as Ram Naumi was to be celebrated on the 24th. Now that 23rd has been declared a holiday, so this meeting will perhaps not take place today.

श्री जवानसिंह—I have received the notice just now, Sir.

श्री अध्यक्ष— It must have been late.

श्री जवानसिंह—No, there is no question of the late receipt. It has been received just now.

श्री जसवन्तसिंह—Then what is the position, Sir? Is a meeting going to take place or because of the holiday······

श्री अध्यक्ष—It should ordinarily not take place when the House sits?

त्याग-पत्र दिये मंत्रियों के वक्तव्य

श्री मानसिंह (जमुवा रामगढ़)—ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सदन के अन्दर आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कुछ मिनिस्टरों ने रिजाइन कर दिया है। हाउस यह हक रखता है कि वह मालूम करे कि इसकी क्या वजह है और आज केबिनेट कहां स्टेन्ड करती है और उसकी क्या पोजिशन है? ब्रिटिश पार्लियामेन्ट और अन्य स्थानों पर यह मिसाल मौजूद है कि जिन मिनिस्टरों ने रिजाइन किया है या करते हैं वे हाउस के सामने स्टेटमेन्ट पेश करते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने इस्तीफे दिये हैं वे और माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर कुछ रोशनी डालें। मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !! Yes, Mr. Vyas.

श्री कानसिंह—सरकार को······

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !! Mr. Vyas.

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, दो दिन पहले जब बजट पर बहस चल रही थी उस समय मैंने आम तौर से जो परिस्थिति बजट द्वारा सामने आई थी उस पर कुछ बातों का जिक्र किया। आज मैं इस बजट के अनालिसिस के आधार पर कुछ नतीजे सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बजट के तीन-चार अंग ऐसे हैं जिन्हें मैं अलग अलग डील करना पसन्द करूंगा।

पहला अंग है रेवेन्यु अकाउन्ट का। इसमें सरकार की क्या परिस्थिति है, यह मैं बतलाऊंगा। दूसरा अंग है केपिटल अकाउन्ट के बारे में जो परिस्थिति नजर आती है वह। तीसरा अंग जिसका जिक्र मन्त्रीजी ने अपने भाषण में भी किया है, वह है वेज् एंड मीन्स (ways and means) का सरकारी बजट की पोजीशन अर्थात् वेज एन्ड मीन्स की स्थिति का अन्दाज बजट में दिखाया गया है।

जहां तक केपिटल अकाउन्ट्स का प्रश्न है मुझे ज्यादा कहने की गुंजायश रही नहीं इसलिये कि करीब करीब सारा एक्सपेन्डिचर केन्द्रीय सरकार द्वारा आये हुए कर्जे के आधार पर होता है। बजट के आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि केपिटल एक्सपेन्डिचर कर्ज से कहीं ज्यादा पहुचता है। इसलिये केपिटल अकाउन्टस के बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता इस समय प्रतीत नहीं होती।

जहां तक रेवेन्यू अकाउन्ट्स का प्रश्न है इस साल के बजट में १९४४ लाख रुपयों की आमदनी का अन्दाज लगाया गया है। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह आमदनी किन किन मदों से हो रही है और यह किस प्रकार की आमदनी है? इन १९४४ लाख

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रुपयों में से ६१ लाख रुपये केन्द्र की ग्रान्ट इन एड हैं। इसके अलावा २२ लाख रुपये हालांकि वे अलग मद में दिखाये गये हैं, लेकिन वे, पाम गुड़ इन्डस्ट्री के लिये जो इमदाद मिल रही है वह शामिल करली गई है और सेन्ट्रल रोड्स फन्ड में से जो पैसा ट्रांसफर किया गया है वे ५७ लाख रुपये भी शामिल कर लिये गये हैं। इस प्रकार १.४ करोड़ रुपया केन्द्र से इमदाद के रूप में मिल रहा है। इसे रेवेन्यु अकाउन्ट्स में डालना न बुद्धिमानी है और न वाजिब है। इसलिये इसे अलग रखना चाहिये। अब जो बाकी बची हुई १८ करोड़ रुपयों की आमदनी है उसमें से डाइरेक्ट टेक्सेशन से कितना है और इन्डाईरेक्ट टेक्सेशन से कितना है, यह देखना है। कितना पैसा सरकार पैदा करती है यह बुनियादी प्रश्न नहीं है लेकिन किस तरह से पैसा यह जमा करती है यह बुनियादी प्रश्न है। आप इस पर पूरी तरह से गौर करेंगे तो देखेंगे कि इनकम टैक्स के २ करोड़ रुपये, माइन्स के ५० लाख, ट्रिब्यूट के ३२ लाख रुपये: इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा ३ करोड़ को छोड़कर बाकी कोई आमदनी डाइरेक्ट टेक्सेशन से नहीं हो रही है। १८ करोड़ में से केवल ३ करोड़ की आमदनी डाइरेक्ट टेक्सेशन से हो रही है। बाकी सभी आमदनी इन्डाईरेक्ट टेक्सेशन से हो रही है। मिसाल के तौर पर बता दूं कि सेंट्रल एक्साइज की ७५ लाख और स्टेट एक्साइज की २ करोड़ ७० लाख रुपये की आमदनी, सॉल्ट, वाटर टैक्स आदि की करीब १० करोड़ की आमदनी बिल्कुल ही इन्डाइरेक्ट टेक्सेशन द्वारा होती है जिसका बोझा प्रत्येक नागरिक के ऊपर पड़ता है।

यानि इसका बोझा प्रत्येक नर-नारी, प्रत्येक नागरिक पर पड़ रहा है चाहे उसकी हैसियत देने की हो या न हो। इस प्रकार दस करोड़ की आमदनी का बोझा लोगों पर पड़ रहा है।

जहां तक लेन्ड रेवेन्यू का प्रश्न है इसकी सारी की सारी आमदनी पौने तीन करोड़ रुपया गिनी गई है और इस बार अन्दाजा लगाया गया है कि जागीरें खत्म कर दी जायगी, जागीरों के रिजम्पशन से आमदनी बढ़ेगी और हर्जाने की रकम काट कर देने के बाद भी इस आमदनी में इजाफा होगा और इस प्रकार ३॥-४ करोड़ रुपयों की आमदनी लैन्ड रेवेन्यु से होगी। इस आमदनी का बोझा भी आम तौर पर साधारण स्तर के लोगों पर पड़ा है। इस प्रकार राजस्थान सरकार के बजट की खासियत यह है कि इस वर्ष १९४८ लाख रुपयों की जो आमदनी होगी उसमें से सेन्टर की मदद को छोड़ कर १८ करोड़ रुपया वसूल होगा और उनमें से तीन करोड़ केवल डाइरेक्ट टेक्सेशन से होगा और बाकी, कुछ मिस्लेनियस आमद को छोडकर, १३-१४ करोड़ की आमदनी इन्डाइरेक्ट टेक्सेशन से होगी अर्थात् ७५ पर्सेन्ट आमदनी इन्डाइरेक्ट टेक्सेशन से होगी। यह माना हुआ सिद्धान्त है, माननीय अध्यक्ष, कि जिस स्टेट में, जिस रियासत में स्टेट की आमदनी इन्डाइरेक्ट टेक्सेशन से ज्यादा होती है, जिस स्टेट के अन्दर इन्डाइरेक्ट टेक्सेशन का ढांचा है, वह प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं समझी जा सकती है किन्तु वह तो ऐसी स्टेट समझी जाती है कि जो खर्चे का बोझा, जिनसे लेना चाहती है उन्हीं पर नहीं डालती है लेकिन सरसरी तौर से हर एक आदमी पर खर्च का बोझा डालती है। हर एक आदमी पर १० रुपया पर केपिटा बोझा पड़ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा फाइनेन्स कमीशन को जो मेमोरेन्डम पेश किया गया था उसमें यह दर्ज किया गया था कि राजस्थान के अन्दर ७२ प्रतिशत इस प्रकार से टेक्सेशन की आमदनी है और इस बजट में उसकी तादाद बढ़ाकर ७५ प्रतिशत कर दी गई है। यह तो राजस्थान बजट की कोई तरक्की नहीं है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कई इन्डाइरेक्ट टेक्सेज का बोझा और ज्यादा बढ़ा है ; जो अच्छी चीज नहीं है। दूसरी दूसरी प्रोग्रसिव स्टेट्स में ७५ प्रतिशत डाइरेक्ट टेक्सेज हैं और २५ प्रतिशत इन्डाइरेक्ट टेक्टसेज हैं। किन्तु इसके विपरीत राजस्थान में २५ फीसदी डाइरेक्ट टेक्टसेज हैं और ७५ प्रतिशत इन्डाइरेक्ट टेक्सेज हैं। अर्थात् "राजस्थान इज स्टेंडिंग आन इट्स हेड" अर्थात् ७५ प्रतिशत इन्डाइरेक्ट टेक्सेज से अपनी आमदनी कर रहा है। यह पहली खासियत है जिसका सारांश यह निकलता है कि "This Budget is a Budget only for pleasing a layman"। यह सामान्य बात आदमी समझता हो या नहीं किन्तु उसकी जेब से, इन्डाइरेक्ट तरीके से वस्तुओं पर टेक्स लगा कर, साल भर तक राजस्थान की आमदनी के लिये, पैसा निकाला गया है ; राजस्थान की आमदनी का जरिया निकाला गया है। इस प्रकार सामान्य आदमी पर बोझा डाला गया है जो राजस्थान सरकार के आंकड़ों से ही प्रगट होता है। तो फाइनेन्स कमीशन को जो मेमोरेन्डम दिया गया था और उसमें जो ७२ प्रतिशत इन्डाइरेक्ट टेक्सेज की आमदनी बताई गई थी वह अब ७५ प्रतिशत हो गई है। राजस्थान ने यह तरक्की की है।

अब इस प्रकार का जो खर्चा है उसका अनेलेसिस करने का प्रयत्न करूंगा। मैं किसी भी स्टेट के 'खर्च' को लेकर दो अंगों में विभाजित करके देखता हूं और मेरा ख्याल है कि हरएक समझदार व्यक्ति को इस प्रकार देखना भी चाहिए। एक अंग यह है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या दमनकारी कार्य जो शासन के अंग हैं, उन पर कितना खर्च होता है ? दूसरा सामाजिक कार्य यानि पब्लिक को राहत पहुंचाने वाले कार्य; पब्लिक की एमिनिटीज पर कितना खर्च होता है ? अगर इस बजट में खर्च की ओर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि राजप्रमुख के अलाउन्स के १४ लाख रुपये और प्रिवी पर्स के ३४ लाख रुपये हैं। तो करीब ५० लाख का सिर्फ राज प्रमुख पर है। इसके अलावा ३८ लाख का और खर्चा है इन्ट्रेस्ट चार्जेज का, अर्थात् सरकार ब्याज के रूप में दे रही है। यह खर्चा भी उसी में आवेगा जिसे हम कह सकते हैं कि कोई आवश्यक खर्चा नहीं है। यह तो गलत फाइनेन्शियल पॉलिसी का खर्चा है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर डेढ करोड़ और पुलिस पर तीन करोड़ खर्च किया जा रहा है। जेल और दूसरे दूसरे इस प्रकार के विभागों को मिला कर उन पर जो खर्चा हो रहा है वह या तो सरकार के प्रशासन के ढांचे को कायम रखने के लिये या दमनकारी अंगों को कायम रखने के लिये ही किया जा रहा है। पब्लिक की राहत के लिये केवल तीन अंगों के लिये खर्च किया जाना जरूरी है। वे तीन अंग हैं.... (१) एजुकेशन, (२) मेडिकल, (३) पब्लिक हेल्थ। एजुकेशन पर दो करोड़ ५१ लाख, मेडिकल पर १ करोड़ १७ लाख और पब्लिक हेल्थ पर ४५ लाख रुपया रखा गया है। तो इस प्रकार का यह बजट-खर्चा किया जा रहा है। माननीय फाइनेन्स मन्त्रीजी ने इस बार अपनी बजट स्पीच में काफी जोर दिया है कि राजस्थान सरकार बहुत प्रोग्रेसिव सरकार है क्योंकि एजुकेशन का उसने लगातार खर्च बढ़ाया है और इतना ज्यादा खर्चा एजुकेशन पर कर रही है कि कहने के लिये राजस्थान सरकार एक निर्माणकारी राज्य की ओर बढ़ रही है। एजुकेशन में जो खर्चा रखा गया है वह भी लोगों को एक तरह से भुलावे में डालने के दृष्टिकोण से रखा गया है। राजस्थान की यह खासियत रही है कि बहुत बड़े क्षेत्रों में शिक्षा का इन्तजाम था, कुछ इलाकों के अन्दर शासन करने वाले जागीरदारों की ओर से यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इन्तजाम था। कई प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्स थीं जिन्होंने कई वर्षों तक काम किया। अगर उन इलाकों में उन इन्स्टीट्यूशन्स को सरकार को लेना पड़ा और उनके लेने में सरकार को जो खर्चा करना पड़ा तो यह कायदे की बात है कि सरकार का खर्चा तो बढ़ा किन्तु सवाल यह है कि लोगों को राहत मिली या नहीं। फाइनेन्स कमीशन को राजस्थान सरकार द्वारा जो मेमोरेन्डम दिया गया था उसका पेज नम्बर १० पेराग्राफ नम्बर २२ में आपको पेश करना चाहता हूं। माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर और मुख्य मिनिस्टर के भाषण के जवाब में कहा गया है कि—

"Prima facie it would appear that the per capita expenditure on education, if not comparable with the scale of expenditure in State like Bombay, Madras, Mysore and Saurasthra, does not shown off poorly in comparison with the scale of expenditure in States like Madhya Pradesh and the Punjab and is even better then in Bihar and Orrisa. In Rajasthan, expenditure on primary education is not, as in the case of other States, shared between the State Government and the Local authorities. It is borne entirely by the Government. If the element of expenditure incurred in other States by local Bodies is cut out, the per capita expenditure would drop down to about 1.20 rupees......."

अर्थात् दूसरो रियासतों के मुकाबले में राजस्थान की हालत का अन्दाजा बताते हुए हम यह नहीं भूल जाना चाहिये कि उन रियासतों में म्युनिसिपेलिटियां, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और स्थानीय सस्थाएं बहुतसा खर्चा कर रही हैं जो राजस्थान में नहीं होता और इसलिये नहीं होता है कि इन म्युनिसिपेलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की आमदनी के जरियों को सरकार ने अपने हाथों में लेलिया है। शिक्षा पर बढ़ा-चढ़ा कर खर्चा नहीं हो रहा है। शिक्षा पर फाइनेन्स कमीशन को जो मेमोरेन्डम दिया गया है वह पेज नम्बर पांच पर है औय वह इस प्रकार है.........

"Out of a total 24 lakhs of children of school going age, approximately 3.43 lakhs or 1: % attend school. The corresponding percentages in the neighbouring State of the Punjab and Uttar Pradesh are approximately 24 and 45; in Mysore it is 40. There is only one primary school for every 33 sq. miles of the area in the State."

तो उनका यह बयान इस बात को साबित करता ह कि एजुकेशन पर जो खर्च की बात है वह होरिजन्टल बात है। दूसरो इन्स्टीट्यूशन्स तो शिक्षा के लिये रो रही हैं, उन्होंने काम बन्द कर दिया क्योंकि सरकार ने अपने पास सब खर्चा रख लिया है। आम लोगों को शिक्षा से फायदा हो, यह इस बजट से प्रतीत नहीं होता। तो जो में मुख्य बात कह रहा था अब मैं उस पर आ जाऊं।

बजट में जो ४ करोड़ रुपया रखा गया है उनका ताल्लुक जन-सेवा के कार्यों से है और बाकी का जितना खर्चा रखा गया है उसका ताल्लुक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या दमन के कार्यों से है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मुख्य मन्त्रीजी और वित्त मन्त्रीजी ने फरमाया अपने भाषण में कि जब राजस्थान बना था तब इस इरादे से राजस्थान का निर्माण किया गया था कि अगर पूरे के पूरे प्रदेश में एक ही मन्त्री मण्डल होगा और एक ही सेक्रेटेरियेट होगा तो प्रशासनिक खर्चा कम होगा। पर आज यह कहते हैं कि यह सोचना गलत था।

मेरा कहना है सोचना गलत नहीं था। खर्च को बढ़ा चढ़ा कर आज परिस्थिति ऐसी ही पैदा करदी गई है। परिस्थिति पैदा करना हमारी गलती है।

इसी प्रकार जहां तक खर्च का सवाल है यह बजट ७५ प्रतिशत आमदनी का बोझा आम लोगों पर डालता है, वहां खर्च का केवल २५ प्रतिशत आम लोगों के राहत के कार्यों में लगाता है यह सरकार।

खर्च में भी मुख्य खर्च शासनीय और अहलकार विभाग पर किया जा रहा है। मैं दो-चार छोटी-छोटी मिसालें बताऊंगा कि कितना डिस्प्रोपोर्शनेट बटवारा किया गया है।

मैं आपको फारेस्ट की मिसाल दूं। जिसकी मद से ४० लाख की आमदनी है और खर्च है उसका २१.५ लाख। यही एक चोच जिन्दा मिसाल है हमारे टॉप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन की। जिस पद पर केवल नेचुरल रिसोर्सेज हों नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस मद में आमदनी है ४० लाख और उस आमदनी को पैदा करने के लिये जो ढांचा खड़ा किया गया है उस ढांचे का खर्चा है २१.५ लाख। अगर इसको भी टॉप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहा जावेगा तो किसे कहा जाय और यह क्यों होता है इसकी भी मिसाल दे दूं।

चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फारेस्ट के बारे में बहुत से प्रश्न उठे थे इस सदन में। उसके विषय पर मोशन और कट मोशन का जब वक्त आवेगा तो विस्तार से कहूंगा। इस समय तो इतना ही कहना चाहता हूं कि उस अकेले कन्जर्वेटर पर ३३ हजार का खर्चा है। उसके बाकी के सारे स्टॉफ, चपरासी आदि का खर्चा ३० हजार का भी नहीं है। पूरे के पूरे एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा एक तरफ और इनका खर्चा एक तरफ; तब भी इनका अकेले का खर्चा ज्यादा पड़ता है। यह दूसरी मिसाल है टॉप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन की।

इसी तरह से देखें तो माइन्स का विभाग भी है। मैं इस समय इस विभाग की तफसील में नहीं जाऊंगा लेकिन सिर्फ इसी प्रकार के आंकड़े इसके बारे में बताऊंगा। ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आमदनी का बड़ा जरिया यह विभाग हो सकता है। लेकिन इसकी आमदनी भी करीब ४५ लाख है और इस आमदनी को प्राप्त करने के लिये विभागीय खर्चा १० लाख रुपया है। हालत दरअसल यह है कि जो हमारी आमदनी के जरिये हैं उन्हें हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और इस्तमाल करने के सिलसिले में ढांचा जो बना कर हमने रख रक्खा है वह इतना टॉप हेवी है कि पूरा का पूरा खर्चा यही ढांचा खा जाता है और स्टेट की रेवेन्यु को नुकसान होता है।

आप मन्त्रियों की सेलेरीज़ की तरफ भी जरा गौर करें। २ लाख ११ हजार की आइटम इसमें रक्खी गई है। यह अभी तक नहीं बताया गया है कि क्या मन्त्रियों की संख्या बढ़ाई जावेगी या नहीं।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैं तो यह मान कर चलता हूं कि तादाद बढ़ाने के बारे में कोई फैसला न हुआ है और न ऐसा करने के कोई कारण हैं। तो फिर यह तनख्वाह का खर्चा बढ़ाने का क्या कारण है। क्या यह बताने की कृपा करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब कि अपनी तनख्वाह बढ़ाने का निर्णय केबीनेट में तो नहीं ले लिया है और इसके बाद सदन के सामने लाने का इरादा तो नहीं है ? अगर तनख्वाह बढ़ाने का इस तरह से कोई इरादा है तो मैं कहूंगा यह भी कि इस बात को नजोर है कि सारा का सारा खर्चा प्रशासनिक रूप में किया जाता है। यह बजट की बहुत बड़ी कमजोरी है।

यहां तक कि लेन्ड रेवेन्यु के बारे में भी यही बात है। ४ करोड़ इस मद से आमदनी है और इस चार करोड़ को इकट्ठा करने के लिये प्रशासनिक रूप में १ करोड़ खर्च कर दिया गया है।

अब मैं सिर्फ दो चीजें और कहना चाहूंगा:

एक तो यह कि अगर हमारे बजट का यही स्वरूप है तो क्या ऐसा ही स्वरूप इस बजट का हो सकता है ? क्या राजस्थान की ऐसी ही स्थिति है कि इस बजट के सिवाय और कोई चारा नहीं है ?

मैं कहुंगा नहीं। इसके सिवाय भी चारा है हमारे सामने। पर उसके लिये आवश्यक रास्ते और तरीके अख्तियार नहीं किये जाते इसीलिये ऐसा दकियानूसी बजट हमारे सामने आ रहा है।

दूसरी बात मैं कहूंगा इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के बारे में। यह जो बिजली देने की चीज है इसमें बताया गया है आमदनी भी नहीं है तो घाटा भी नहीं है; ऐसा दिखाया गया है। लेकिन यह हकीकत नहीं है। ६ लाख के करीब पैसा दिया जा रहा है उसके इन्टरेस्ट का। वह इन्टरेस्ट का रुपया भी इसमें से अगर वसूल नहीं होता तो क्या कारण है इस बात का ? कोई भी बिजनैस जानने वाला व्यक्ति यह महसूस करेगा कि यह ऐसा धन्धा है कि जिसमें मांग सैटिस्फैक्टरी नहीं हो रही है पर फिर भी यह धन्धा घाटे में क्यों चल रहा है। जिस धन्धे में खरीददार न हो, ग्राहक न हो उसके घाटे का तो अनुमान समझ में आ सकता है। उसके लिये तो कारण हो सकता है लेकिन उस धन्धे में जिसमें मांगने वाले ग्राहक और खरीददार बहुत हैं और उन सबकी मांग को पूरा नहीं कर सकते और जहां की मांग कभी भी सटिस्फैक्टरी नहीं होती, फिर भी वह घाटे में जाता है तो मैं कहूंगा इसके बारे में सरकार ने कभी छानबीन भी करने की कोशिश की है ? क्या सरकार के हमारे मन्त्री महोदय ने यह कभी जानने का प्रयत्न किया है कि इससे आमदनी क्यों नहीं होती ?

अनाप शनाप खर्चा हो रहा है। मेरा यह कहना है कि इसमें जनरल वैस्ट (General waste.) हो रहा है। दूसरा मेरा यह भी कहना है कि इस बारे में बड़ी बड़ी शिकायतें आई हैं सरकार के पास ; पर सरकार आंख मूंद कर बैठी है। इसकी बीसों मिसालें मैं कट मोशन के समय दूंगा। लोग कॉलेजों में जाते हैं, अपना काम-धन्धा करते हैं, घन्टा आधा घन्टा वहां काम करते हैं पर उनकी तनख्वाह पूरी की पूरी बिजली घर के पेटे उठ रही है। खरीददारों, स्टोर्स आदि के मामलों में बड़े बड़े घोटाले चलते हैं। यहां तक कि कोल के कन्जम्पशन के मामले में भी छानबीन करने की बड़ी भारी

Page No.45

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

गुंजाइश है। यह नहीं होने से आमदनी का एक बड़ा भारी भाग दूसरों की जेबों में चला जा रहा है। हमारी जो आमदनी बढ़नी चाहिये वह नहीं बढ़ती।

इसी तरह माइन्स के विषय में है। यहां पर बड़ी बड़ी खानें हैं। हमारे प्रान्त में भीडल की खानें हैं तथा सोडियम, सगमरमर, आदि कई खनिज पदार्थ यहां निकलते हैं। पर मैं पूछता हूं उसमें से ४०-५० लाख को आमदनी ही हो और उस छोटी सी आमदनी को भी बटोरने में २१.५ लाख रुपया हम खर्च कर दें! कोई देख भाल नहीं आपकी, कोई योजना नहीं है आपकी। यह सारी की सारी आमदनी सरकार की होनी चाहिये। पूरी देख भाल न होने के कारण और किसी अच्छी योजना के अभाव में वह यों ही बरबाद हो रही है। हमारी आमदनी के बड़े बड़े जरिये इस तरह से बरबाद किये जा रहे हैं।

इसी तरह हमारे यहां के केमिकल्स के लिये, ऊन के लिए, हड्डियों के लिये और ऐसे ही अन्य डियर प्रोडक्ट्स (dear products) के पनपाने की योजनाएं क्या इस बजट में हैं? मैं कहता हूं कोई नहीं है। ये हैं सही तरीके हमारे बजट को ठीक तरह से बनाने के, पर इसके बारे में कोई योजनाएँ नहीं, कोई विचार करने वाला नहीं।

ट्रान्सपोर्ट विभाग भी आमदनी का एक अच्छा जरिया होना चाहिये। पर इसमें भी इसी प्रकार की धांधली हो रही है।

अन्त में मैं कहूंगा कि जो सबसे बड़ा जरिया हमारी आमदनी का हो सकता है वह है वे जमीन जो (जरिया) जागीरी प्रथा के मातहत आज पड़ी हैं। अगर ये जमीनें जागीरी प्रथा के मातहत न रहें तो जो आमदनी आज भूमि से ३ करोड़ की होती है वह ४ गुना और ५ गुना तक हो सकती है। आधी राहत भी अगर लगान आदि में आप दे दें तो भी दुगनी तो हो ही सकती है। पर कम्पेन्सेशन और दूसरी दूसरी चीजें जोड़ कर इस आमदनी का भी सफाया करने का इरादा है। इसके बारे में कहा कुछ नहीं जा सकता। जो रिसोर्सेज़ हैं राजस्थान की आमदनी के वे बरबाद किये जा रहे हैं।

दूसरी और भी जो चीज है वह है जिसका जिक्र इस सदन में दो दिन पहले हुआ था और जिसका नाम रखा है Pre April 1950 livility (प्री एप्रिल, १९५० लाइबेलिटी)

यह १९५० के अप्रेल के पहले की जो लाइबेलिटीज हैं उनके मद में २६ लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। इसमें २६ लाख ५७ हजार रुपया दर्ज किया गया ह ...

श्री अध्यक्ष--You will conclud.

श्री एच. के. व्यास--I am Concluding. I want two minutes. I have only two points.

(विराम)

[श्री एच. के. व्यास]

तो मैं अर्ज कर रहा था कि यह जो अप्रेल ५० के पहले की लाइबेलिटीज है वे २६ लाख रुपये की हैं। आखिर है क्या यह चीज, इस बात पर गौर कीजिये। अप्रेल सन् ५० के पहले क्या हमारे यहां बजट नहीं बनते थे? अलग अलग रियासतों के बजट नहीं बनते थे: क्या उसके बाद में ही बाकायदा बजट बनाने का काम शुरू हुआ? क्या यह अच्छा नहीं था कि जितनी पहले की एसेट्स (Assets) या लाइबेलिटीज थीं उनका तखमीना बनाकर दर्ज किया जाता? न तो इस प्रकार किया गया है और न यह हो रहा है। लाइबेलिटीज हर साल द्रोपदी के चीर की तरह बढ़ती जा रही हैं। हर साल २५ लाख रुपया, ५० लाख रुपया लाइबेलिटीज पर खर्च करना पड़ता है। इस पर हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा यह कहीं भी नहीं दिया गया है।

दूसरी ओर धान खरीदने की स्कीमें। सिविल सप्लाईज के तहत करोड़ों रुपयों की पूंजी लगाई गई थी। उन करोड़ों रुपये की पूंजी का क्या हुआ? इसका हिसाब कन्सोलिडेट तरीके से नहीं रखा गया। इसके लिए कहा जा रहा है कि हमें ५० लाख रुपये धान बेचने से मिल जायगा। लेकिन कितनी पूंजी इसमें लगी हुई है, कितना सामान खरीदा गया, वर्किंग एक्स्पेन्सेज क्या परसेन्ट हुआ, उसके हिसाब से कितनी आमदनी होनी चाहिये, कितना अनाज सड़ जाने से नुकसान हुआ, कितना हिसाब किताब न रखने की वजह से सिविल सप्लाइज विभाग में बाकी है, यह नहीं बताया गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिविल सप्लाईज विभाग द्वारा जो अलग अलग परमिट के ठेके किये हुए थे। अगर उन ठेकों का हिसाब वसूल किया जाय तो आपको पता लगेगा कि करोड़ों रुपयों का पैसा बाकी है? यह पैसा हमारी सरकार की ढिलाई की वजह से या भ्रष्टाचार की वजह से वसूल नहीं हो रहा है। १९५० की लाइबेलिटीज के आंकड़े द्रौपदी के चीर की तरह हमारे सामने आये। इससे पहले क्या पूंजी बाकी है, उसको नहीं बताया गया है। यह एक बार तय हो जाना चाहिये कि लाइबेलिटीज के इस मद में कितनी पूंजी बाकी है। यह तय नहीं होना बजट में बहुत बड़ी कमी की ओर इशारा करती है।

अंत में मैं उन विभागों की ओर इशारा करना चाहता हूं जिन्हें मैं निगलेक्टड विभाग समझता हूं। मैंने अब तक आपको बतलाया है कि बजट में किन किन मदों में कमी की जा सकती है। अब मैं कुछ उन महकमों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिन पर खर्चा बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसे लेबर डिपार्टमेन्ट वहां न तो पूरा स्टॉफ है और न इन्तजाम ही है। राजस्थान ही हिन्दुस्तान में एक ऐसी स्टेट है जहां इन्डेक्स लेबर केल्कूलेट करने का इन्तजाम नहीं। राजस्थान ही एक ऐसा हिस्सा है जहां वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन कमिश्नर अभी अभी कुछ जगह कायम किये गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि लेबर विभाग के बारे में बहुत कुछ खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है। एक विभाग और है जहां पर भी खर्चा बढ़ाने की आवश्यकता है। वह है कम वेतन पाने वाले मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ाना, जिनको अबतक भी चालीस पचास रुपया प्रतिमास मिलता है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन बोलना नहीं चाहता था फिर भी मेरा नाम पुकार कर मुझे बोलने के लिये कहा गया। मैं पांच मिनट का समय और चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपको १५ मिनट ही देने चाहिये थे किन्तु आपने ३० मिनट ले लिये।

श्री एच. के. व्यास—Now not more than two minutes. मैं यह बात अर्ज कर रहा था कि छोटी तनख्वाह पाने वाले मुलाजिमों के वेतन बढ़ाने के लिये ज्यादा खर्च की आवश्यकता है। यह बजट जनता को लूटने वाला और बड़े बड़े लोगों पर ज्यादा खर्च करने वाला बजट है जो कि ठीक नहीं है। इसे ठीक किया जाना चाहिये।

(पुनः समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री चन्दनमल वैद—माननीय अध्यक्ष, इसके पहले कि मैं बजट की अच्छाइयों और खूबियों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करूं और नीति संबंधी कुछ सुझाव माननीय सदस्यों के समक्ष रखूं मैं सारे हिन्दुस्तान में फैली हुई एक प्रवृति की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आर्ट फोर आर्ट्स सेक (कला कला के लिए है) जैसी एक प्रवृति चली थी। आज उसी के अनुसार हमारे साथियों ने एक नया नारा चलाया कि विरोध विरोध के लिए है। इस नीति में हमारे साम्यवादी भाई बड़े पारंगत है। इस बजट में जहां आज शिक्षा पर पौने दो गुना से भी ज्यादा खर्च हो रहा है और पुलिस पर खर्चा इस वास्ते बढ़ाया गया है कि राजस्थान में फैली हुई अशान्ति और अव्यवस्था को दूर कर दिया जाय। राजस्थान में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए इस विभाग के लिए ज्यादा खर्च करना जरूरी है। उन भाई में ये खूबियां नहीं देखीं और केवल इस बात को ध्यान में रखकर कि विरोध विरोध के लिये करना चाहिये, विरोध किया। इसका कारण यह भी है कि वे यह बात मानकर चलते हैं कि हमें प्रजातन्त्र का विरोध करना है और वह विरोध प्रजातन्त्र के इस महान् भवन में भी आकर करना है, और बाहर भी। बाहर-अन्दर सभी जगह जन्तन्त्र का विरोध करना उन्होंने अपनी नीति बनाली है क्योंकि वे यह जानते हैं कि जिस भूमि पर प्रजातन्त्र का वृक्ष पनप जायेगा वहां साम्यवाद नहीं पनप सकता उन्हें तो साम्यवाद को पनपाना है इसलिये वे इस सदन के अन्दर भी प्रजातन्त्र का विरोध करना चाहते हैं और कर रहे हैं . . . . .

श्री एच. के. व्यास—On a point of order, sir, has the hon'ble member nothing to say about budget?

श्री चन्दनमल वैद—I am coming to the budget, before that I will just deal with this tendency.

(अपना भाषण जारी रखते हुए) माननीय सदस्य बहुत तिलमिला रहे है। वे हमारे लिये बहुत कुछ अक्सर कहते रहते हैं लेकिन हम लोग तो तिलमिला नहीं उठते। उनके लिये जब मैं दो-चार खरी

[श्री चन्दनमल वैद]

तथा सच बात कह रहा हूं तो उनका तिलमिलाना वाजिब नहीं तीत होता। मैं माननीय सदस्य की उस न्डेन्सी की ओर इशारा कर रहा हूं कि माननीय सदस्य ने यह अपना नारा बना लिया है कि विरोध विरोध के लिए किया जाना चाहिये। इसी काम को पूरा करने के लिये वे यह नीति अपना रहे हैं कि जनता के अभावों व अभियोगों को जहां कहीं भी, मौका-बेमौका उभाड़ा जाय, और बातों को बढ़ा चढ़ाकर सदन के सामने रखा जाय। यह इस वास्ते नहीं कि अभाव व अभियोग से शान्ति हो बल्कि इस वास्ते कि जनता में ज्यादा असंतोष फैले। जनता के घावों को इस वास्ते नहीं दिखाते कि उनपर मरहम लगाई जाय बल्कि इस वास्ते कि अगुली लगाकर उनको और बढाया जाय। जनता के अभाव और अभियोगों की आग को वे शान्त नहीं करना चाहते बल्कि उस पर पंखा झलकर और बढाना चाहते हैं। वे यह जानते हैं कि जब अभाव-अभियोगों की आग को उभारा जायगा तो जनता में असंतोष, अव्यवस्था तथा अशान्ति फैलेगी और इनके साथ साथ अराजकता भी फैलेगी और उनकी मान्यता है कि उस अराजकता रूपी कीचड़ में कमल रूपी साम्यवाद पैदा होगा और फैलेगा। जो इस प्रकार कीचड़ से कमल पैदा करना चाहते हैं उनको करने दिया जाय। किन्तु मैं उधर बैठे हुए सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे बजट की खूबियों और अच्छाईयों की ओर ध्यान दें। कुछ लोग कीचड़ पैदा करने में इस तरह से लगे हुए हैं और वे कमल पैदा करने के लिये कीचड़ पैदा करना जरूरी समझते हैं। उनको अपनी बेकार कोशिश करने दीजिए। अब मैं आपके सामने कुछ सुझाव पश करना चाहता हूं। एक मेरा सुझाव यह है कि १ अप्रेल, १९५५ से आप इन्टर स्टेट ड्यूटीज़ को हटा कर उसकी जगह सेल्स टैक्स लगाना चाहते हैं। इस नीति के सिलसिले में मैं थोडे से सुझाव देना चाहता हूं। १ अप्रेल, १९५५ से आप इन्टर स्टेट ड्यूटी को हटाकर, जिसकी आमदनी करीब चार करोड रुपया होती है वह आमदनी प सेल्स टैक्स लगाकर करना चाहते हैं; तो मेरा विश्वास है कि सेल्स टैक्स के लगाने से ज्यादा से ज्यादा जो आमदनी होगी वह १ करोड की होगी। दूसरी स्टेटों में जहां सेल्स टैक्स लगाया गया है वहां १९४८ से सेल्स टैक्स लगाया गया है। उनकी आमदनी के भी जो आंकड़े हैं वे यदि आप देखेंगे तो आपको यह मालूम होगा। आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(१)	आसाम में १९४८ में सेल्स टैक्स लगा और पर केपिटा आमदनी जो इस टैक्स से होती है वह	.५४९
(२)	बिहार में सेल्स टैक्स १९४४ से लगा और पर केपिटा जो आमदनी होती है वह	.६२२
(३)	मध्य प्रदेश में सन् १९४७ से सेल्स टैक्स लगा देने के बावजूद भी वहां की आमदनी इस टैक्स से जो पर केपिटा होती है. वह	.६१०
	और उड़ीसा में १९४५ से यह टैक्स लगा देने के बावजूद भी वहां पर पर केपिटा जो आमदनी होती है वह	.४७९

[श्री चन्दनमल वैद]

इस प्रकार सेल्स टैक्स पूरी तौर पर लगा देने के बावजूद भी आमदनी, मैं समझता हूं, पर केपिटा (per Capita) १ प्रतिशत से ज्यादा नहीं। इस टैक्स से जो आमदनी होगी वह एक करोड़ होगी और कस्टम की जो आमदनी हमारी आयगी वह ४ करोड़ है। तब इस आर्थिक अवस्था में जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे यहां आर्थिक तंगी है तो इसको देखते हुए मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से इस बात की रिक्वेस्ट करें कि अगले ५ सालों के लिये वह हमें अनुमति देदे कि जो इन्टर स्टेट ड्यूटीज अभी हैं उनको कायम रखें और सेल्स टैक्स नहीं लगायें। इसके १ २ कारण और हैं जो मैं आपको बतलाऊंगा। इन्टर स्टेट ड्यूटीज जो हैं वह जनता पर भार हो चुकी हैं, फिर भी जनता उनको मानती है। उनको हटाकर दूसरा टैक्स लगाने पर उनको भार महसूस होगा। इससे उनको कोई विशेष तकलीफ नहीं हो रही है। अगर आपको उसके कुछ मद ज्यादा महसूस होते हों तो उनको कम कर दिया जाय। जैसे पशुओं के आवागमन पर इससे लोग राहत महसूस करेंगे और आमदनी ४ करोड़ के बजाय ३ करोड़ ही होगी लेकिन उसके बजाय सेल्स टैक्स से जो आमदनी होगी वह १ करोड होगी, तो भी २ करोड की आमदनी ज्यादा होगी। अतएव इस आर्थिक तंगी के वक्त हमें हमारी आमदनी में इस प्रकार कमी नहीं करनी चाहिये। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से प्रार्थना करें कि इन्टर स्टेट ड्यूटीज अभी ५ साल के लिए और रहने देने की अनुमति देदें।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इशारा किया है कि २-३ साल के के बाद प्रारंभिक शिक्षा का जो बोझ है वह लोकल बोर्डीज यानी नगरपालिकाएं सम्हाल लेंगी; ऐसी उनकी उम्मीद है। लेकिन नगरपालिकाओं के पास अभी जो काम हैं स्वास्थ्य, सफाई और रोशनी का उनमें भी वे फैल हो रही हैं: तो कैसे हम आशा कर सकते हैं कि आगे आनेवाली नई जिम्मेवारियां वे सम्हालेंगी ? जो ड्यूटीज उनके पास होंगी उनमें वे कैसे कामयाब होंगी ? इसके लिये मैं सुझाव दूंगा। उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। उसको सुधारने के लिये गवर्नमेन्ट यह कदम उठाये कि उनके हल्के में जो जमीन है उसे उनको बेचने का अधिकार दे दिया जाय और उससे जो आमदनी होता है वह उनको लेने का अधिकार दे दिया जाय। अभी सरकार ने यह रवैया बना रखा है कि उसको बेचने से जो आमदनी होती है वह राजस्थान सरकार ले लेती है। वह गलत है। उनको अभी की जिम्मेवारियां पूरी सम्हालने के लिए तथा आगे जो अन्य जिम्मेवारियां आप दे रहे हैं उनको सम्हालने के लिये जो जमीन उनके हलके में बच दी जाती है, उनका पट्टा ग्रान्ट करने का अधिकार नगरपालिकाओं को दे देना चाहिय, उनकी कीमतें उनको दे देनी चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे जिम्मेदारियां नहीं सम्हाल सकेंगे।

मैं अब बजट की कुछ खूबियां और अच्छाइयां जो हैं उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह खुशी की बात है कि निराशा का वातावरण चला गया है और आशा का वातावरण आया है। जब बजट सदन में पेश हुआ उसके पहले सारे राजस्थान में निराशा छाई हुई थी कि हमारा बजट घाटे का है, किसी लोक कल्याणकारी व जनकल्याणकारी काम में पैसा नहीं लग रहा है, पर हम निराशा से आशा के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से हमने अगर काम किया तो वह दिन दूर नहीं है कि हम आशा के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ जायं।

Page No.50

[श्री चन्दनमल वैद]

शिक्षा के क्षेत्र में मेरे मित्रों ने यह कहा कि विशेष बढ़ोतरी नहीं की; लेकिन मैं कुछ आंकड़ों की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब सारी स्टेट्स इन्टिग्रेट हुई थीं तो कुल १६० लाख रुपये शिक्षा के काम में खर्च किये जाते थे। आज उनकी जगह २९१ लाख रुपये शिक्षा में खर्च किये जाते हैं। थोड़ा सा मेरे मित्र हिसाब में तेज हों और हिसाब लगाकर देखें तो मालूम होगा कि शिक्षा के काम में ८२ प्रतिशत वृद्धि हुई है। अगर वे इसको कम मानते हैं तो एक दम शत-प्रतिशत वृद्धि करना किसी स्टेट के लिए मुमकिन नहीं है। इसको हम संतोषजनक मानते हैं। अगर यह वृद्धि कायम रखी गई तो यह माना जा सकता है कि आने वाले सालों में शिक्षा के विषय में काफी प्रगति कर लेंगे। जब सारी स्टेट्स इन्टिग्रेट हुई थीं तो १६० लाख रुपये शिक्षा के काम में व्यय किये जाते थे। तब हमारा बजट, सारी स्टेटों का बजट कुल १६........ (समय-समाप्ति सूचक घंटी)

My friends have been given 50--60 minutes and I am being given only 10 miniutes.

श्री अध्यक्ष--15 minutes will be given to you.

श्री चन्दनमल वैद--उस समय सारी स्टेट्स का बजट १६१५ लाख था। इस हिसाब से हम देखते हैं कि १० प्रतिशत शिक्षा के काम में व्यय किये जाते थे, और आज सारा बजट १९४४ लाख का है तो शिक्षा में २९१ लाख व्यय किये जाते हैं। इस तरह १५ प्रतिशत शिक्षा के काम पर खर्च किये जा रहे हैं।

दूसरी मद जिसकी तरफ हमारे साथियों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है वह है पुलिस। अगर हम पुलिस के पिछले साल के कामों पर ध्यान दें तो यह मानना पड़ेगा कि यह व्यय जो है वह जरूरी ही नहीं किन्तु अत्यन्त आवश्यक है। ८० डाकुओं को मारना और १६०० डाकुओं को गिरफ्तार करना मामूली बात नहीं है। पिछले साल बजट की बहस के संबंध में इस बात की तरफ सदन के दोनों तरफ के लोगों की तरफ से यही ध्यान दिलाया गया था और कहा गया था और इस बात का आश्वासन चाहा था कि इस पर चाहे कितना ही खर्च किया जाय, अशान्ति और अव्यवस्था पर काबू करना चाहिये। तो इस पर काबू किया जा चुका है। इस बात के लिए होम मिनिस्टर साहब की सराहना की जायगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी के इस कथन के बावजूद भी कि पुलिस पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है दूसरी स्टेटों में पुलिस पर खर्च के जो आंकड़े हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इनको देखने से मालूम हो जायगा कि हम पुलिस पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं।

(१) वेस्ट बंगाल में १४.७१ पर्सेन्ट कुल खर्च का पुलिस पर खर्च किया जाता है।

(२) बम्बई में १५.५९ पर्सेन्ट कुल खर्च का पुलिस बजट पर खर्च किया जाता है।

(३) पंजाब में १५.९१ पर्सेन्ट पुलिस पर खर्च किया जारहा है।

(४) मध्य भारत में १४.१२ पर्सेन्ट पुलिस पर खर्च किया जारहा है।

(५) राजस्थान में १५.८ पर्सेन्ट पुलिस पर खर्च किया जायेगा।

[श्री चन्दनमल वैद]

इन स्टेटों के खर्चे को देखते हुये मैं समझता हूं कि हमारा पुलिस पर खर्च बहुत ज्यादा नहीं है। अगर पर केपिटा खर्च देखें यानि प्रति व्यक्ति दूसरी स्टेटों का पुलिस पर खर्च देखें तो हमको मानना पड़ेगा कि राजस्थान में परकेपिटा पुलिस पर खर्च कम हो रहा है।

(१) वेस्ट बंगाल में २.४ रुपया प्रति व्यक्ति इस पर खर्च किया जा रहा है।

(२) बम्बई में २.८ रु० खर्च किया जा रहा है।

(३) पंजाब में इस पर २.२ रु०।

(४) मध्य भारत में २. रु०।

(५) राजस्थान में २.०० रु०।

तो अगर दूसरी स्टेटों के आंकडे अपने यहां के आंकड़ों से मिलायें तो हमको यह मालूम होगा कि इतना सराहनीय और सुन्दर काम करने के बावजूद भी हम उस मद पर विशेष खर्चा नहीं कर रहे हैं। इतना ही खर्च कर रहे हैं जितना कि जरूरी था और हमारी स्थिति को देखते हुए जरूरी है।

इसके बाद पिछले साल हमारी सरकार ने सराहनीय कार्य किये हैं। उनकी तरफ ध्यान देना ज ी है। एक तो पचवर्षीय योजना में चम्बल वेली (Valley) प्रोजेक्ट का इन्क्लूड करवा लेना। इससे राजस्थान की बहबूदी में जो सहयोग मिलेगा वह बहुत ज्यादा होगा। और हमें बजट की आलोचना करते समय इस बात को नहीं भूलना चाहिये। दूसरी बात है कि फाईनेन्स कमीशन के सामने जो रिपोर्ट हमने पेश की थी उस रिपोर्ट के कारण हमें पौने तीन करोड़ रुपये सेन्टर से जो सालाना ज्यादा मिलेंगे उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये।

सारी बातों को देखते हुए, मैं, हिन्दुस्तान के दूसरी स्टेटों के चालू साल के बजटों को देखता हूं और बजट के मामले में अपने आपको थोड़ा बहुत जानकार समझता आ यह मानता हूं कि इस स्थिति में, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, इससे अच्छा सुन्दर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। यह सबसे अच्छा और सुन्दर बजट वर्तमान परिस्थितियों में है।

श्री **मोहब्बतसिंह**—माननीय अध्यक्ष, हमारे सामने माननीय चीफ मिनिस्टर ने राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया है। श्री चीफ मिनिस्टर ने बड़ी होशियारी से बजट के आंकड़े हमारे सामने रखे हैं और उन्होंने ऐसा बजट बनाया है जिसे उधर-इधर देखा जाए तो मालूम होगा कि आय और व्यय दोनों बराबर हैं। १९ करोड ४४ लाख आय के आंकडे हैं। चीफ मिनिस्टर का जो बजट पर भाषण हुआ है उसमें उन्होंने भूतपूर्व वित्त मंत्री की प्रशंसा की है। जहां तक शिष्टाचार का सम्बन्ध है मैं मान सकता हूं कि चीफ मिनिस्टर ने जो हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री की प्रशंसा की है वह ठीक है। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उससे भी बढा चढाकर भूतपूर्व फाइनेन्स मिनिस्टर की जो प्रशंसा की है इसके लिये मैं कहूंगा कि एक तरफ तो चीफ मिनिस्टर ने उनकी शंसा के पुल बांधे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने उन्हें फेल्योर (Failure) समझ कर फाइनेन्स का पोर्ट फोलियो अपने खुद के हाथ में लिया है। यह कर्टसी (Courtsey) नहीं तो आप सको क्या मानेंगे।

[श्री मोहब्बतसिंह]

श्री चीफ मिनिस्टर ने बजट पेश करके हरा-भरा और सर सब्ज बाग हमारे सामने बताया है। लेकिन यदि हम गम्भीरतापूर्वक इस बजट पर विचार करें तो हमें मालुम होता है कि इसमें असली तथ्यों को छिपाया गया है और तोड़ मरोड़ कर ऐसा बजट रखा गया है जो एक साधारण व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकता। बजट सीधा सादा होना चाहिये था जो हर किसी के समझ में आसानी से आजाय। मगर उसे इतना बड़ा और कॉम्प्लीकेटेड बना दिया है कि आसानी से समझ में नहीं आ सकता। राजस्थान के जो आमदनी के साधन हैं वे ४-५ हैं जैसे फारेस्ट, माइनिंग, कस्टम एन्ड एक्साइज, ट्रान्सपोर्ट आदि। फारेस्ट में कई कारणों से आमदनी में बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती है। लेकिन आप देखेंगे कि फोरेस्ट की आमदनी गई साल एस्टीमेटेड इन्कम से भी कुछ कम ही हुई। यह इसलिये कम हुई कि ठेकों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, जो हमारे आय को बढ़ा सकते हैं; इस पर कोई ध्यान नही दिया गया। मेरे साथी श्री भैरूसिंहजी ने एक प्रश्न मधुमक्खियों की इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन देने का किया था। लेकिन उसका भी कोई जिक्र बजट में नहीं है। इससे भी हमारी सरकार को आमदनी में सहायता मिल सकती है। इसके अलावा और भी ठेके जंगलात में, जंगली उपज के होते हैं वे ठीक तौर से नीलाम नहीं होते। जैसे अभी ९ ठेके सिरोही में नीलाम होने को थे मगर वे नहीं हुए और सिर्फ दो ही नीलाम किये गये। अगर ९ ठेके नीलाम हो जाते तो काफी रुपया सरकार को मिलता।

इसके अलावा कस्टम और एक्साइज के लिये सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि आर्थिक संकट के कारण शराब की बिक्री कम हुई। लेकिन वास्तविक बात यह नहीं है। इसके अन्दर जो ठेकेदारी का सिस्टम है वह गलत है। ठेकेदार पानी मिलाकर शराब बेचते हैं। ठेकेदारों का पानी भी शराब में मिलकर उनके लिये आ जाता है तो शराब तो कैसे नहीं ला सकती है।

इसके अलावा हमारी आय जो रेवेन्यू से होती है उसमें भी ऐसे आइटम हैं जिनमें से आमदनी की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि १९२३ में सिरोही के राज्य का सिरोही के जागीरदारों के साथ एग्रीमेन्ट हुआ था और उसकी अवहेलना अब की जा रही है। इसलिये इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। जागीरदार यह समझते हैं कि मौजूदा बदलती हुई परिस्थितियों में उन्हें बदलना पड़ेगा। मगर फिर भी हम पर सरकार की तरफ से इतने जुल्म क्यों होते हैं। जिस प्रकार जोधपुर, बीकानेर, जयपुर आदि में लगान वसूली का हाल था वह हाल सिरोही का नहीं था क्योंकि सिरोही एक छोटी रियासत थी और जागीरदार अपनी अपनी आमदनी का २-३ हिस्सा व ३-४ हिस्सा तक सरकार को देती थी। १९२३ में जागीरदारों के साथ एग्रीमेंट हुआ उसमें यह था कि जिस जागीरदार के जितनी इनकम होगी उसका ३/४ जागीरदार देगा लेकिन अब वह परिस्थिति नहीं रही। वह परिस्थिति बदल गई। अब किसानों के लिये १।६ हासिल हो गया है? तो आप विचार करेंगे कि जागीरदार ३/४ कैसे दे सकता है, यह अन्याय पूर्ण मांग नहीं तो क्या। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर आदि में रेख-चाकरी के हिसाब से रकम ली जाती थी। यानि एक लाख के पीछे वे २०० या ३०० रुपये देते थे। यह स्थिति सिरोही में नहीं थी। माननीय अध्यक्ष, क्या चीफ मिनिस्टर इस पर गौर करेंगे? जब १।६ हिस्सा काश्तकारों से लिया जाता है

[श्री मोहब्बतसिंह]
तो फिर हम क्या चोरी करके ज्यादा रकम सरकार को देंगे, क्या हम डाके डालेंगे । यदि यह अनुचित नहीं तो फिर क्या है ? आप खुद इस पर गौर फरमावें ?

इसके अलावा जो बजट हमारे सामने पेश किया है वह दलगत भावना से बनाया गया है; जो दलगत भावना से परे होना चाहिये था। यह उस भावना से बना है कि जहां से नोन कॉंग्रेस केन्डिडेट आते हैं वहां पर कोई सार्वजनिक कार्य नहीं किया जाता और जहां से कॉंग्रेस केन्डिडेट आते हैं वहां पर बजट में खर्च की काफी गुंजाइश रखी जाती है। दुर्भाग्यवश जोधपुर से बहुत कम कॉंग्रेस के सदस्य आये हैं इसलिये वहां पर खर्च नहीं किया जा रहा है । मेरे मित्र श्री मोटारामजी चौधरी की यही शिकायत है कि उनकी कॉंस्टीट्यूएन्सी पर भी कोई खर्च नहीं होता है । उनको भी यही महसूस होता है कि जोधपुर से कॉंग्रेस सदस्य बहुत कम आये हैं और गैर कॉंग्रेसी सदस्य ज्यादा हैं इसलिये वहां पर ज्यादा खर्च नहीं होता । जयपुर, अलवर से कांग्रेस के सदस्य ज्यादा आए हैं इसलिये उन इलाकों पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है ।

(श्री हिम्मतसिंह, सभापति, पदासीन)

इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि यह राजस्थान का बजट जो हमारे सामने पेश किया गया है वह राजस्थान का बजट नहीं बल्कि कांग्रेस की पार्टी का बजट है ।

मैं अब पुलिस पर जो खर्च हो रहा है उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। यह सही है कि पुलिस ने कई डाकू पकडे हैं लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कितना रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है और मैं यह समझता हूं कि वह इसलिये बढ़ाया जा रहा है कि जनतन्त्र की आवाज को दबाया जावे ।

इसके अलावा जब हम लोग आम जनता की तकलीफों के लिये कहते हैं, जिनको मिटाना आवश्यक होता है तो कहा जाता है कि बजट में प्रोविजन नहीं है । जैसे सिरोही के टाउन हॉल की छत टूट रही है इसके लिये कई प्रार्थना-पत्र भेजे गये मगर शिक्षा मंत्रीजी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है । वहां पर (सिरोही) होस्पिटल में एक्सरे की मशीन जनता ने मंगाई है लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो रहा है । इसके अलावा वहां के होस्पिटल में राहत देने वाली गाड़ी को भी वहां नहीं रखा गया । क्या उसकी भी वहां पर आवश्यकता नहीं है ?

श्री हिम्मतसिंह (चेयरमेन)—आप प्रिन्सिपल्स पर ही बोलें ।

श्री मोहब्बतसिंह—इसलिये यह एक ऊंचे स्तर का बजट नहीं है क्योंकि जहां कहीं से इलेक्शन में कॉंग्रेस केन्डिडेट्स नहीं आये हैं वहां के लिये बजट में कुछ नहीं रखा गया है । इसलिये मैंने इस बजट को नीचे स्तर का बजट कहा है ।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—इस साल जो बजट पेश किया गया है इसमें एक तो खिसारा नहीं दिखाया गया ये बड़ी खुशी की बात है और एक जुबान भी इसमें आसान इस्तेमाल की गई है । चीफ मिनिस्टर साहब इस बजट को बनाने के लिए काबिले मुबारकबाद हैं। पर इसमें बाज चीजें ऐसी हैं जिनकी कमी महसूस की जाती है ।

Page No.54

[श्री मोहम्मद इब्राहीम]

कस्टम के मुतल्लिक इसमें बहुत बड़ी खामी है। बिरतानवी हुकूमत के वक्त हिन्द में जो गुलामी की अलामत थी उससे ज्यादा रियासती हिन्द में कस्टम और जमा, इस गरज से रखी कि इससे अन्दाज रहे कि क्या क्या कस्टम रियासतों में रायज हैं और क्या क्या जुल्म किये जाते हैं। और वहां बरतानवी हिन्द में एक काश्तकार अपनी सरसों वगैरा चीजों को बेचता है और कोई कस्टम नहीं देना पड़ता। आपको मालूम होना चाहिये कि वहां जमीन का लगान चार आने फी बीघा, छै आना बीघा और दस आना बीघा हद से ज्यादा है; वहां कस्टम नहीं। बीस मन गेहूं वहां फी बीघा पड़ता है पर इसके लिए रेवेन्यू क्या देनी पड़ती है चार आना बीघा, आठ आना बीघा। जब वहां का एक आदमी, रियासतों का एक आदमी रियासतों की हद में दाखिल हो तो उसे मालूम हो कि यहां रियासतों में छै मन बीघा अनाज होता है तो काफी समझा जाता है पर इसके लिए उसे दो रुपया, ढाई रुपया, तीन रुपया बीघा तक देना पड़ता है। रियासत के काश्तकार की पैदावार का कस्टम भी ज्यादा है। सरसों की पैदावार पर ढाई रुपया फी मन कस्टम ली जाती है। बड़े अफसोस की बात है कि किसान अपने आपको अब भी पहले से ज्यादा जकड़बन्दी महसूस करता है जब कि पहले इस तरह की रिश्वतखोरी यहां नहीं थी। आज यह चीज बहुत बढ़ी हुई है। कस्टम के मामले में बहुत बड़ी कमी बजट में है। इसमें कस्टम में बहुत कुछ कमी की उम्मीद थी मगर अफसोस कि कस्टम में जैसी उम्मीद थी वैसी कमी नहीं की गई। यह जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिये।

इसके अलावा पुलिस के लिये बहुत बड़ी रकम का हिस्सा मकसूस किया गया है। पुलिस पर जितना रुपया खर्च किया जाता है उसको देखते हुए पुलिस ही एक ऐसा महकमा है जो राजस्थान में काबू में नहीं आया है और इसके मुलाजिम बराबर बढ रहे हैं। और आज तक मिनिस्टरों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं इसके लिए एक मिसाल पेश करूं कि पुलिस किस तरह रिश्वत खाती है, मजालिम करती है और पब्लिक को परेशान करती है। कबायली लोग पुलिस पर पैसा खर्च नहीं करते, पठानों में कोई पुलिस नहीं है, कबायली लोग ही पुलिस की बजाय काम करते हैं। पर यहां पर पुलिस के लिए इतना रुपया खर्च किया जाता है और पुलिस जितना फायदा करती है उससे कहीं ज्यादा नुकसान करती है। मेरा इलाका राजस्थान का ही एक हिस्सा है। शायद मिनिस्टर लोग भूले हुए हैं कि वह राजस्थान में है कि नहीं। मौजा घुगोर त० कामां वहां एक ऊंट दिन में जबरदस्ती डाके से लेजाया जाता है, पुलिस पीछे जाती है, न मुलजिम पकड़ा जाता है और न ऊंट ही पकड़ा जाता है। मैंने अफसरों से कहा तो उन्होंने कहा कि मुलजिम और ऊंट सब आ जावेंगे। थानेदार जाता है। वाकया है। मुलजिम पकड़ा जाता है पर ऊंट नहीं आता है। उल्टा ऊंट वाले को मुलजिम बनाया जाता है। दूसरे दिन गोलमाल करके मुलजिम को छोड़ दिया जाता है। थाना टपूकड़ा अलवर में गोकशी का झूठा केस पुलिस ने बनाया गाय को आप ऊंची समझते हैं। हम भी उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं, उसका गोबर खाद के काम आता है, उसके बछडे हल में चलते हैं। हम इतनी मुहब्बत रखते हैं गाय से कि जब मेव आबाद थे तो एक एक मेव के पास सौ-सौ, पचास-पचास गायें थी। आज जो गोरक्षा का नारा लगाते हैं व मोटरों में फिरते हैं, मोटर रखते हैं मगर गाय एक भी नहीं रखते। मालूम नहीं कि गाय किस तरह रक्खी

Page No.55

[श्री मोहम्मद इब्राहीम]

जाती है और किस तरह पाली जाती है । जब कोई गाय मौत से मर जाती है तो हमारे बच्चे दो-दो, तीन-तीन दिन तक रोटी नहीं खाते । जब गाय बुड्ढी हो जाय, बिमार हो जाय तो कौन उसको खाना पसन्द करेगा? उससे बीमारी फैल जाती है। हम गोकुशी बन्द होने के पक्ष में हैं। (करतलध्वनि)

पर गोकुशी का झूठा केस बनाकर बहुत ही शोर किया गया और गौ की खाल को लेकर, यह कसाइयों से भी बढकर पुलिस है, ऐसे आदमी के घर में रखती है जो तीन मील दूर गांव से काम करता है, जिसके घर न ताला है। और गांव की फसल को नुक्सान करके लोगों को जबर्दस्ती बुलाकर २५ आदमियों को गिरफ्तार किया जाता है। उनके साथ सख्त से सख्त तशद्दुद किया जाता है, मारपीट की जाती है, लोगों के तार मेरे पास और घासीराम के पास पहुंचते हैं। हम होम मिनिस्टर और डी. आई. जी. पी. को तार देते हैं। उन लोगों की १३ तारीख से २१ तारीख तक पिटाई होती है, औरतों की बेइज्जती की जाती है।

जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दौरा करते हैं तो पुलिस वाले इन्तजाम करते हैं। हम खुद यह चाहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की शान बढे मगर पुलिस के हाथों इन्तजाम न होना चाहिये। थानेदार और जिस पुलिस इन्सपेक्टर साहब ने मोजा पथरेडी में मेवों पर तशद्दुद किया था वही चीफ मिनिस्टर साहब के जल्से के लिये चन्दा करते हैं और वही पुलिसवाले पुलिस के दलालों को चीफ मिनिस्टर साहब से मिलाते हैं।

चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे दूसरे मिनिस्टर साहबान बहुत अच्छे हैं पर जब वे दौरे में जाते हैं तो उनके साथ पुलिस की गारद रहती है । डी. एस. पी. साथ में होता है । पुलिस के थानदार होते हैं। क्या यही गांधी जी के फोलोअर हैं ? सो सो साल की गुलामी में रही हुई पब्लिक से क्या मिनिस्टर साहब यह उम्मीद करते हैं कि पुलिस के कप्तानों और तहसीलदारों के सामने उनकी शिकायत करने की हिम्मत कर सकते ह । पुलिस के खिलाफ कुछ कह सकते हैं ?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, बाईस-तेईस लाख आदमियों की तरफ से दुख-दर्द बयान कर रहा हूं। मुझे बोलने के लिये थोडा टाइम और दिया जावे मैं साल भर में बोल रहा हूं। कस्टोडियन का एक महकमा जो हिन्दुस्तान में खालिस एक फिरके के लिये बनाया गया है वह हिन्दुस्तान के आईन के और कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ है । कस्टोडियन की ज्यादतियां दिन पर दिन बढ रही हैं। मिनिस्टरों ने ध्यान नहीं दिया। मुसलमानों को कस्टोडियन महकमा इतना परेशान कर रहा है कि कोई खाता-पीता ऐसा मुसलमान नहीं जिस पर कि कस्टोडियन महकमे का कोई न कोई केस नहीं कायम हो, और इससे परेशान नहीं हो रहा हो ? क्या कस्टोडियन महकमा आजाद हिन्दुस्तान में कायम रहना चाहिये? पर इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मुसलमान किस तरह से कस्टोडियन से हैरान व परेशान व बरबाद हो रहे हैं । इस चीज को कोई तसलीम नहीं करता लेकिन जब इस पर अमल होता है तो तसलीम करना पड़ता है । खुला सक्युलर तो यह होता है कि मुसलमानों की जमीन जायदाद वापिस कर देनी चाहिये

Page No.56

[श्री मोहम्मद इब्राहीम]

लेकिन होता यह है कि एक पैसे की भी जमीन जायदाद वापिस नहीं की जाती । राजस्थान एक सेक्युलर स्टेट नहीं है। कहने को तो यह कहा जाता लेकिन हकीकत में यह एक सेक्यूलर स्टेट नहीं है, एक फिरके की स्टेट है । पहले मुसलमान को राज्यों में नौकर रखा जाता था । २२ स्टेटों में अच्छे अच्छे ओहदों पर मुसलमान नौकर थे । पर आज राजस्थान सरकार के जितने सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री और असिस्टेन्ट सेक्रेट्री हैं उनमें से एक भी मुसलमान इन ओहदों पर नहीं है। इतने हेड्स ऑफ डिपार्टमेन्ट्स हैं पर उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। इतने कमिश्नर हैं पर उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। २५ जिलों के कलेक्टरों में से एक भी मुसलमान नहीं है । २५ जिलों के पुलिस कप्तानों में से एक भी कप्तान मुसलमान नहीं है। आई.जी.पी., डी.आ.ई.जी.पी. में से एक भी मुसलमान नहीं है । यह फिरके वारियत नहीं तो क्या है। आप यह तो नहीं कह सकते कि मुसलमान काबिल नहीं हैं । वे काबिल नहीं हैं तो क्या आज ही काबिल नहीं हैं, पहले काबिल थे ।

श्री कानसिंह—It is a Secular State.

श्री मोहम्मद इब्राहीम—(भाषण जारी रखते हुए) यही हाल जबान का है । सन् ४८ तक उर्दू जबान इधर के हिस्से की रियासतों में राज्य की जुबान थी । जयपुर, टोंक, धोलपुर आदि में सारा काम काज उर्दू जबान में होता था । पर आज उर्दू का नामोनिशान नहीं है । जिस उर्दू को लोग आसानी से समझ लेते थे उसकी जगह न समझी जाने वाली हिन्दी को दिया जा रहा है । यह सरासर जुल्म नहीं तो क्या है, मुसलमानों पर, महात्मा गांधी के फॉलोअर्स ही आज इस तरह की सख्ती कर रहे हैं । महात्मा गांधीजी ने फरमाया था कि हिन्दुस्तानी जुबान काम में ली जानी चाहिये चाहे रसमुलखत उर्दू हो या हिन्दी । भारत सरकार ने जिन १४ जबानों को मान्यता दी है उनमें से उर्दू भी एक है । ऐसी सूरत में उर्दू को कोई जगह नहीं देना गैर इन्साफी है ।

श्री भैरूंसिंह—ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर ! यह बजट स्पीच दे रहे है या उर्दू को पोशीदा कर रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय सदस्य को कहने का हक है ।

श्री चेयरमेन (हिम्मतसिंह)—(श्री इब्राहीम को संकेत करके) आपका समय हो गया है ।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—कम से कम अपने इलाके का मामला बयान करने के लिये पांच मिनट तो और दीजिये ।

श्री चेयरमेन—श्री इब्राहीम को संकेत आप बैठ जाइये, आपका समय हो गया है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट आप लोगों के सामने रखा गया है और उसके जो आंकडे पब्लिक के सामने बताये गये हैं वे आंकड़े यदि पब्लिक के सामने न बतला

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

कर अपने आप ही इस बजट को मंजूर कर लिया जाता तो ज्यादा अच्छा मालूम होता क्योंकि जो आंकडे आज पब्लिक के सामने या मेम्बरान के सामने रखे गये हैं उनमें जो खर्चा दिखलाया गया है वह वास्तविक रूप में न दिखलाया जाकर मनमाने ढंग से दिखाया गया है। इस बजट को हमारे सामने रखकर हमारी जो राय पूछी गई है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसी स्थिति में मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जो रकम राजस्थान गवर्नमेन्ट खर्च करती है तथा दूसरे लोगों को दी जाती है उसके पूरे आंकडे नहीं बतलाकर यों ही खर्च कर लिया जाता है।

तीन करोड़ रुपये शासनिक खर्चे के लिये जो बताये गये हैं, विशेषतः खर्च ट्रान्सफर्स में राजस्थान गवर्नमेन्ट का होता है। ऐसा सुनने में आया है कि एक साल में एक एक कलेक्टर की दस-तीन बार, एक एक नाजिम की छः सात बार और एक एक तहसीलदार की दस-दस बार ट्रान्सफर की जाती है। तो इसका यदि अन्दाजा लगाया जाय और सिफारिश मानकर ट्रान्सफर्स नहीं किये जायं तो करीब २५ लाख रुपया सालाना राजस्थान गवर्नमेन्ट का बच सकता है।

दूसरी बात यह है कि कस्टम्स की करीब ३ करोड़ ५० लाख रुपये की इनकम बतलाई गई है लेकिन राजस्थान गवर्नमेन्ट ने अपने पहले बजट में यह बतलाया था कि कस्टम्स पांच साल में हटाया जायगा लेकिन इस साल राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार से इन्कम टेक्स का शेयर प्राप्त हो जाने पर भी उसने कस्टम्स ड्यूटी में से एक पता भी नहीं हटाया है, यह बड़े दुःख का विषय है। कस्टम्स भी नहीं उठाया गया है और सेल्सटेक्स भी लगाया जा रहा है। राजस्थान गवर्नमेन्ट यह नहीं सोचती कि दिनोंदिन पब्लिक पर टेक्स तो बढ़ाया जाता है पर पब्लिक के फायदे के कोई काम नहीं किये जाते ?

तीसरी बात यह है कि खर्चा जो किया जाता है वह मनमाने ढंग से किया जाता है। मिनिस्टरों के खर्च में २ लाख ११ हजार रुपये बताये गये हैं। लेकिन यह खर्चा केवल तनख्वाह का खर्चा बतलाया गया है। इसमें दूसरा खर्चा शामिल नहीं है। करीब १३ लाख रुपया, १३ लाख नहीं १३ हजार रुपया बिजली और पानी के खर्च के लिये बतलाया गया है। २० हजार रुपया टेलीफोन के लिये बतलाया गया है और पेट्रोल और पुलिस जो मिनिस्टरों के साथ दौरे पर जाती है, उसका खर्चा कितना होता है यह नहीं बतलाया गया है। पुलिस जब उनके साथ दौरे में जाती है और उनके मकान पर जो पुलिस की गार्ड पहरा देती है उसका कितना खर्चा होता है यह नहीं बतलाया गया है। यदि अंदाजा लगाया जाय तो मोटरों का खर्चा जो पिछले बजट में सवा लाख रुपये का था उसे घटाकर इस बजट में ३ हजार कैसे कर दिया गया है ? इस बारे में क्या हम यह मानकर चलें कि मिनिस्टर साहबान खुद की मोटर रखें और पट्रोल का खर्चा खुद अपनी जब से करेंगे और २५०) रु. माहवार मोटर अलाउन्स के लेंगे और मोटर विभाग का अन्य कोई खर्चा मिनिस्टरों की मोटरों पर नहीं होगा ?

पांचवीं बात यह है कि एग्रीकल्चर विभाग के बारे में जो खर्चा बताया गया है वह ३२ लाख रुपये हैं जो एग्रीकल्चर के ऑफिस आदि का खर्चा है। राजस्थान गवर्नमेन्ट इस विभाग पर जो खर्चा

Page No.58

[श्री भक्तिलाल मोदी]

कर रही है वह बेकार है और अपने आदमियों को रुपये दिलवाने के सिवाय और कोई उपयोग नहीं होता। इस विभाग ने आज तक क्या करके दिखलाया यह कुछ नहीं बतलाया गया। इस विभाग की ४ लाख रुपया सालाना की इन्कम बताई गई है वह मच्छी मारने के ठेके की है या कुछ बगीचों के ठके से है। इस ३२ लाख के खर्चे को राजस्थान गवर्नमेन्ट कम कर सकती है। इस डिपार्टमेन्ट की उपयोगिता सिर्फ अपने आदमियों को कुछ रुपये दिलवाने के सिवाय कुछ नहीं है। इस खर्चे को गवर्नमेन्ट एकदम कम कर सकती है।

छठी बात जो मुझे आपको बहुत दुख के साथ कहनी पडती है वह यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सेक्रेट्री तथा दूसरे लोगों के लिये, जो इलेक्शन किशनगढ में श्री जयनारायणजी व्यास का हुआ उसमें सरकारी मोटरें काम में ली गई और उनमें ६,७०० रुपयों का खर्चा था।

(विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनिट में ही समाप्त कर देता हूं।

सातवीं बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि किशनगढ इलेक्शन में श्री हीरालाल पाटनी, जिन्होंने श्री जयनारायणजी व्यास की मदद की थी, उनमें दो लाख रुपया गवर्नमेन्ट मांगती है उसकी वसूली न करके श्री पाटनी के जो ७२ हजार रुपये राजस्थान सरकार की तरफ बाकी निकलते हैं वह रुपया गवर्नमेन्ट की ओर से उनको दिया गया है, उसका क्या कारण है? यह राजस्थान गवर्नमेन्ट बतावे?

इसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि शाहपुरा से निजामत हटाकर कोटपुतली करदी गई है। कारण सही तौर पर, दूना खर्चा निजामत पर होता है। नाजिम साहब के जाने आने का अधिक खर्चा सरकार को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसकी ओर ध्यान नहीं रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब को क्वेश्चन पूछने पर भी और सारी रिपोर्टें आने पर भी निजामत को हटा दिया गया। यह शाहपुरा की डेढ़ लाख की जनता के साथ अविश्वास किया गया है। कोटपुतली एरिया में ४० हजार जनता है और शाहपुरा एरिया में डेढ़ लाख जनता है, जनता की ओर न देखकर केवल मेरे माननीय मित्र की तरफ देखकर निजामत को शाहपुरा से उठा दिया गया, जो अच्छा काम नहीं किया गया।

("शेम-शेम" की आवाज विरोधी पक्ष की ओर से)

एक बात और है वह यह है कि श्री भरूलाल जी गैलड़ा को पचास हजार रुपया की रकम सेंक्शन की गई है। वह पचास हजार रुपया उन्हें अभी दिया नहीं गया है। परन्तु जो मिनिस्टर इस तरह की सेन्क्शन करते हैं उन्हें यह भी पता नहीं है कि पचास हजार रुपये की रकम किस तरीके व मद में दी जाय। फाइनेन्स मिनिस्टर का इन्कार करने का नोट लगा है। तो इस तरह से एक-एक आदमी को पचास हजार रुपया की सेन्क्शन कर देना न्यायपूर्ण चीज नहीं है। जो बजट बनाया गया है वह सही नहीं है।

Page No.59

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—पचास हजार रुपया किस मद से दिया गया है, यह बता दिया जाय तो अच्छा हो।

(श्री मुक्तिलाल मोदी द्वारा इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री बी. एन. जोशी—मैं वर्तमान बजट पर अपने विचार प्रगट करने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं यह बजट जो सरकार ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह अर्थ-शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार और आज की परिस्थितियों के अनुसार सही और ठीक बजट है। बजट हमेशा बाजार को कन्ट्रोल करने तथा आर्थिक स्थिति को स्टेबिल करने के लिये एक बड़ा सामान है, ऐसा अर्थ शास्त्र ने माना है। जब प्रान्त में इन्फ्लेशन हो तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, चीजों के भावों को, जो लगातार बढ़ते और घटते रहते हैं उन्हें नियन्त्रित करने के लिये और मार्केट में मनी का जो सर्क्युलेशन है उसको चेक करने के लिये बजट अच्छा साधन होता है। टेक्सेशन के रूप में ज्यादा रुपया सरकार लेती है तो मार्केट में फालतू रुपया नहीं होगा और भावों में गिरावट पैदा हो जायगी और इन्फ्लेशन को मदद मिलेगी। जब डिफ्लेशन आता है तो भावों में गिरावट आ जाती है और उस समय योग्य फाइनन्स मिनिस्टर को चाहिये कि वह घाटे का बजट पेश करे जिससे सरकार की ओर से ज्यों ज्यों ज्यादा खर्चा होगा तो आम जनता को राहत पहुंचेगी।

वार के जमाने में इन्फ्लेशन हो गया था सारे भाव बढ़ते चले जा रहे थे और एक जमाना वह था कि जब १० मेट्रिकुलेट्स की जगह होती थी तो ७ ही मिलते थे। वार के जमाने में मनी ज्यादा थी, भाव बढ़ते चले गये। आज बाजार का ट्रन्ड रुक गया है। लड़ाई के जमाने में जो मनी कमाया था वह या तो मकानात में इन्वेस्ट कर दिया गया या कुछ और तरीके से इन्वेस्ट कर दिया गया; इस खयाल से भी कि डिफ्लेशन आने वाला है, बेरोजगारी शुरू हो गई है। इन्फ्लेशन का ट्रेन्ड रुक चुका हो, डिफ्लेशन को खतरा आने वाला हो तो ऐसी परिस्थिति में बजट न इन्फ्लेशन का हो और न डिफ्लेशन का हो, न कीमतें बढ़ने पावे और न घटने ही पावे। सन् १९३० और ३२ में बेकारी शुरू हो गई थी, और उसका आज भी पीछा नहीं छूटा है। अतः अर्थ शास्त्र के नियमानुसार बलेन्स्ड बजट होना चाहिए और जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट रखा है। मैं आपको यह कहूं कि यह बजट अर्थ शास्त्र के नियमों के अनुसार और आज की परिस्थितियों के अनुसार साफ और ठीक है और इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

दूसरी बात जो आपको बतलाना चाहता हूं वह यह है कि प्रान्त की आर्थिक स्थिति में जो खतरा पैदा होता है वह फाईनेन्शियल पॉलिसी के द्वारा ही होता है। भारत सरकार से १॥ करोड़ रुपया लिए बिना हमारे मुलाजिमों को तनख्वाह देना मुश्किल होगया था और सोचा जा रहा था कि क्या राजस्थान सरकार का काम ठीक प्रकार से चल सकेगा या नहीं? खतरा इस रूप में था कि मेडिकल आदि राष्ट्र-निर्माण के कार्यों को चालू रख सकेंगे या नहीं? इन परिस्थितियों में भी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, माननीय मुख्य मंत्री जी ने राष्ट्रनिर्माण के कार्यों में शिक्षा, मेडिकल, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आदि में पिछले साल के मुकाबले और राजस्थान में सम्मिलित होने वाली रियासतों के बजट के टोटल के मुकाबले में भी सबसे ज्यादा प्रोविजन रखा है। यह वेलफयर स्टेट का एक प्रगतिशील बजट है। इस बजट में ४१ लाख रुपया एजुकेशन के लिए, पिछले साल सन् १९५२-५३ के मुकाबले में, अधिक रखा गया है

[श्री डी. एन. जोशी]

और राजस्थान सम्मिलित होने वाली राजाशाही रियासतों के एकीकरण के पश्चात् उनके सम्मिलित बजटकी राशि से १ करोड ३१ लाख रुपया ज्यादा है । इसी तरह से ९ लाख रुपया मेडिकल में सन् १९५२-५३ से अ कि क है । में आपको फेमिन रिलीफ के बारे में बताऊं । राजस्थान की खेती बादलों की महरबानी पर मुनस्सर है । अक्सर यह होता है कि इस डिविजन में व ी हुई, उस डिविजन में वर्षा नहीं हुई। खे ी वहां को चौपट हो जाती है, जहां बरसात नहीं होती है और किसान बरबाद हो जाता है .पिछले साल मिन रिलीफ में जो रुपया रखा गया था उससे बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ८० लाख रुपया दूसरी मद से खर्च किया गया । फेमिन रिलीफ में इस साल इन्क्रीज्ड प्रोविजन रखा गया है और इसलिये में इस बजट का स्वागत करता हू । यह एक अच्छा कदम है और सही निशान है ।

कोऑपरेटिव के लिए भी इन्क्रीज्ड प्रोवीजन रक्खा गया है इस बजट में । इससे ज्यादा अच्छी बात कोई हो नहीं सकती थी । आज की जिन परिस्थितियों में रहकर, अपनी जिन सीमाओं का ध्यान रखकर, इस सरकार ने जो कुछ किया है यह भी हमें सोचना चाहिये ।

मेरे माननीय मित्र श्री एच. के. व्यास ने कहा है कि राजस्थान का एकीकरण इस आशा से किया गया था कि प्रशासन का खर्चा भी कम होगा, पर वह नहीं हुआ । इसके बारे में में यह भी कहदूं कि यह तो उनका स्लोगन (slogan) है, सस्ती वाहवाही वे चाहते हैं । राजस्थान के इन्टीग्रेशन का खर्चा अगर पुराने राजाशाही सरकारों के मुकाबले में हुआ है तो वह हुआ है मोर्डनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Modernisation of Administration) और राज्य कर्मचारियों की तनख्वाओं के बढ़ाने से । आप एक तरफ तो मांग करते हैं कि कर्मचारियों की तनख्वायें बढ़ाई जायं और दूसरी तरफ ऐसी शिकायतें करते हैं । छोटे कर्मचारियों के पे स्केल (pay scale) में इजाफा हुआ है और में समझता हूं कि कोई भी समझदार, जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता है ।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि पुलिस पर ज्यादा खर्चा किया गया है । में समझता हूं कि पुलिस का जहां तक सवाल है उसके साथ जन सुरक्षा का प्रश्न पड़ा हुआ है । सरकार से उम्मीद यह की जाती है कि चोरियां, डाके आदि रोके जायं और खास कर जोधपुर डिविजन के इलाकों में जब अरक्षा की सी स्थिति पैदा हो गई है वहां नॉर्मल स्थिति आनी चाहिये। इसके लिए पुलिस की ज्यादा जरूरत है और ज्यादा सुरक्षात्मक साधन उसे मुहइया करने की आवश्यकता है। इसका परिणाम होगा ही कि खर्चे में कुछ वृद्धि हो । एक तरफ सुरक्षा की बात करनी और दूसरी तरफ खर्च की शिकायत भी करनी; ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं । इस सदन के दोनों पक्षों ने एक स्वर से यहां यह मांग की थी कि खर्चे की परवाह नहीं, पर यह डाकेजनी बन्द होनी ही चाहिये। यदि आप इस गवर्नमेन्ट की रिपोर्ट देखें,

Page No.61

[श्री बी. एन. जोशी]

तो वह वाकई प्रशंसनीय है। प्रान्त में व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसको निभाने में किसी खर्चे की शिकायत करना समझदारी की बात नहीं है ।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक माननीय सदस्य ने कहा कि ट्रान्सफर्स के बारे में ज्यादा खर्चा हुआ; कलेक्टर, तहसीलदार आदि लोगों के काफी ट्रान्सफर्स किये गये जिसमें काफी रुपया सरकार का बरबाद हुआ। यह कहने वाले सदस्य वही हैं जो कभी इस ओर बैठा करते थे। जब इस तरह के कोई व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं तो यह भी कहना मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि मैं यह भी खुलासा कर दूं कि जो सदस्य कुछ समय पहले इधर बैठा करते थे उनके बारे में यह मशहूर था कि कलेक्टरों, तहसीलदारों, पटवारियों आदि का तबादला कराने के लिए वे मन्त्रियों को काफी परेशान करने वाले थे।

श्री **मुकिलाल मोदी**—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे बारे में ये जो कुछ कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं ।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी**—This is unauthorized interruption, Sir.

(विराम)

जागीरों के मामले में कहा जाता है। इसके बारे में मैं कहूं कि हमारे लिये विधान बना है और हमें हमारे बनाये हुए विधान को मानना अनिवार्य है । इस विधान के मातहत बहुत कुछ हक हाईकोर्ट को मिले हैं। सरकार ने जागीरी समाप्ति कानून बनाया और उस पर हाईकोर्ट में रिट पेश की गई है। अब अगर सरकार इसमें इन्टरफियर करती है तो सरकार का वह कार्य कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट (Contempt of court) में आता है। सरकार ने अपनी नीति शुरू से स्पष्ट घोषित कर रखी है कि वह जागीरें बर्दाश्त नहीं करेगी। यह स्पष्ट घोषणा हजारों मरतबा कर चुकी है। लेकिन फिर भी आज हाईकोर्ट के सामने रिट मौजूद है। इसके बाद ही जागीरों का अबोलिशन होने वाला है। इसके बारे में सरकार को दोष देना ठीक नहीं है।

एक बात यह भी कही गई कि लेबर विभाग में खर्च बहुत है। पूरा स्टॉफ भी नहीं है।

राजस्थान में इन्डस्ट्रीज इन्फेन्सी स्टेट (शैशवावस्था) में है। अच्छे अच्छे मिल केवल अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। सात-आठ मिलें हैं।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—फर्स्ट क्लास मिल तो एक भी नहीं है।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी**—फर्स्ट क्लास मिल तो एक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में बंगाल, यू. पी., बम्बई आदि दूसरे उन्नत प्रान्तों से हमारे यहां के लेबर विभाग का मुकाबला करना समझदारी की बात नहीं है। जितनी कम हमारी समस्याएं हैं उस हिसाब से हमारा स्टॉफ भी है। लेबर की समस्याएं हमारी इन्डस्ट्रीज के साथ २ बढ़ेंगी। तो उसी हिसाब से इस विभाग को भी बढ़ाया जावेगा। इसके लिए इस समय चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

[श्री विश्वम्भर नाथ जोशी]

इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

कर्नल श्री दिलीपसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रधान (मुख्य) मंत्रीजी ने इस मजलिस के सामने पेश किया है, पिछले सालों के बजटों से तो बहुत अच्छा है। इन्सान ऐसी चीज है कि जो खुदा की बनाई चीजों में भी नुक्स निकालने से बाज नहीं आता तो इस मनुष्य निर्मित बजट में तो जितने नुक्स कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है। (करतल ध्वनि)

कहने का मतलब यह है कि इसमें भी गल्तियां हो सकती हैं। पर मैं इन पर कुछ न कह कर दो-चार खास २ बातों पर सुझाव पेश करना चाहता हूं, जिन पर मैं चाहता हूं। दोनों तरफ के सदस्य गौर करने की कृपा करेंगे।

पहली अर्ज करने का मतलब यह है कि फाइव इयर प्लॉन के बारे में प्रधान (मुख्य) मंत्रीजी ने बताया था कि इतनी मदद केन्द्रीय सरकार से मिली है और इतना हमें करना है। मेरा सुझाव है कि इसमें ऐसे आदमी काम करने वाले रक्खे जावें जो लगन और इमानदारी से इस काम को पूरा करें और सरकार का एक पैसा भी बरबाद न होने दें तथा और लोगों की पॉकेट में वह पैसा न जाने दें। इसके अभाव में यह प्लान नहीं चलने वाली है और अगर यह प्लान फेल हो जावेगी तो यह गवर्नमेन्ट भी नहीं रहने वाली है और न मेरी तरफ बैठी वाली पार्टी ही रहेगी; कोई तीसरी ही पार्टी आवेगी।

इसलिये मेरा सुझाव, अर्ज करने का यह है कि पंचवर्षीय प्लॉन में ऐसे आदमी रखे जायें ताकि रुपयों में गड़बड़ी न हो। जैसा कि राजस्थान के निर्माण होने पर चौदह करोड़ रुपयों की जो सिक्यूरिटियाँ थीं उनका हाल जो हुआ उसी प्रकार इन रुपयों का भी हाल न हो।

इसके बाद मेरा अर्ज करने का मतलब है कि फाइव इयर प्लॉन के अंदर थोड़ी सी जो अड़चन मालूम हो रही है वह इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देने का प्रश्न है उस संबंध में मैं यह कह दूं कि इसमें सिर्फ जयपुर को तरजीह दी गई है, पुरानी रियासतों की केपिटल (राजधानियों) का इस बारे में कुछ खयाल नहीं किया गया। इससे वे डेजर्ट हो जायेंगी। दूसरी रियासतों के केपिटलों में जो व्यापारी लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, उनका व्यापार दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अगर पुरानी राजधानियों के लिए बिजली की या और कोई अन्य योजना रखी गई तो कुछ दिनों बाद ये राजधानियाँ एक खण्डहर के रूप में दिखाई देंगी।

दूसरा सवाल मेरा अर्ज करने का यह है कि पुलिस में खर्चा ज्यादा क्यों बढ़ाया गया। पुलिस के खर्चे को बढ़ाने के संबंध में मुझे एक शेर याद आ गया जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय बहुत प्रचलित हो गया था। वह शेर यह है :—

अजब माजरा है हजरते जंग भी,
फतह ब्रिटिश की होती है कदम जरमन का बढ़ता है।

Page No.63

[कर्नल श्री दिलीपसिंह]

ठीक यही हाल पुलिस का है। पुलिस डकैतियाँ वगैरह की खोज निकाल कर डाकुओं को पकड़ती रहती हैं और दूसरी तरफ और डाकू पैदा हो जाते हैं। इसके लिये मेरा सुझाव यह कि पुलिस फर्सेस के अंदर नवजवान एक्स स्टेट फोर्सेज के आदमियों का रखा जायगा तो इसमें काफी सुधार हो सकता है। यह जाहिर हो चुका है कि आर. ए. सी. में बटालियन कमान्ड जब आर्मी अफसरों को मिली है तो बहुत फायदा होता जा रहा है। डकैतों वगैरह को पकड़ने में पुलिस के टेक्टिक्स काम में नहीं आ सकते, पुलिस तो स्थानीय चोरियों का पता लगाना, सी.आई.डी. का काम करना, इनमें होशियार हो सकते हैं। डकैतों को पकड़ना, बोर्डर पर हमला न होने देना इनसे रक्षा आर्मी ही कर सकती है। जब बोर्डर पर आर्मी थी उस समय इतनी डकैतियां नहीं हुईं थीं जितनी कि आज हो रही हैं। जब से आर. ए. सी. वहां आई है जिसमें बहुत से यानी ९० पर्सेन्ट सिविलियन रखे गये हैं उनसे ज्यादा अच्छा यह होता कि उनकी जगह एक्स सोल्जर्स लिये जाते। वे ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते थे। एक तरफ जहां ये बेकार फिर रहे हैं उनको भी काम मिल जाता और हमारे बोर्डर की अच्छी हिफाजत भी हो सकती।

तीसरी बात जो अर्ज करना है वह यह है कि इस बजट में एक्स-सोल्जर्स (ex.-soldiers) के रिसेटलमेण्टके लिए कोई सवाल नहीं रखा गया है। गये साल के बजट में भी भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिए कोई रुपया नहीं रखा गया था और न आयन्दा साल के लिये रखा गया है। इस बारे में मैंने गत वर्ष भी अर्ज किया था और आज भी कर रहा हूं कि इसके बसाने के लिए कुछ काम अवश्य किया जाना चाहिये। राजप्रमुख ने भी अपने भाषण में, जब वे खेरवाड़ा पधारे थे, कहा था कि एक्स-सोल्जर्स बसाने के लिये योजनाएं बनाई जा रही हैं और नवम्बर में जब कमाण्डर इन चीफ उदयपुर पधारे थे उस समय उन्होंने कमिश्नर साहब से पूछा कि कितने एक्स-सोल्जर्स को सेटल्ड किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक। इसलिये मेरा आपसे अर्ज करना है कि उदयपुर डिविजन में ८०-९० हजार एक्स-सोल्जर्स बैठे हुए हैं उनको सेटल्ड किया जाय; नहीं तो वही होगा जैसा कि अकबर के शेर में मैं पहले कह चुका हूं।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। वह यह है कि पहले स्टेटों में जब फोर्सेज थीं तो उनके बच्चों को शिक्षा फ्री दी जाती थी। उनके लिये फ्री एजुकेशन की स्कूलें बनी हुई थीं। जब से स्टेटों की फोर्स का एबॉलीशन हो गया उनके बच्चों को फ्री तालीम नहीं मिल रही है। जिनके पास पैसा नहीं वे दूसरे स्कूलों में अपने बच्चों को भेज भी नहीं सकते। इसलिये मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि जो इमदाद उनके बच्चों को स्टेटों के जमाने में मिलती थी वह मिलनी चाहिए। गये साल में भी कुछ रुपया इस कार्य के लिये नहीं रखा गया, इस साल भी नाम नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा और मेरी इस्तदुआ है कि वे महरबानी करके एक्स सोल्जर्स के बच्चों के लिए पढ़ाई की फीस माफ कर दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शिक्षा के अभाव में ये बच्चे नये डकैतों के रूप में तैयार होंगे। मगर वे डकैत नहीं होंगे तो कोई दूसरी जमात होगी उसमें शामिल हो जायगे तो कोई ताज्जुब नहीं। मेरा तो अर्ज करने का फर्ज था जो मैंने किया, अब करना न करना आपकी मरजी।

[कर्नल श्री दिलीपसिंह]

अब मैं फेमीन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। फेमीन के बारे में काफी बहस हो चुकी है, काफी सवालात भी पूछे गये थे; उनके उत्तर भी दिये गये। जवाबों में यह भी कहा गया था कि उदयपुर डिविजन में बहुत इमदाद दी गई। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि उदयपुर डिविजन के कुछ इलाकों को ही मदद दी गई; जैसे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि को। उदयपुर डिवीजन में ये शामिल होने से यह कहा गया कि उदयपुर डिविजन को काफी सहायता दी गई। लेकिन खास उदयपुर में लसाडियों में कुछ इमदाद की गई। इन इलाकों के सिवाय भी फेमीन इफेक्टेड एरिया हैं, उन जगहों को भी मदद दी जानी चाहिये। यह ध्यान नहीं रखा जाना चाहिये कि यह फलां व्यक्ति की कॉन्स्टीटयुएन्सी है, फलां की नहीं है. इसलिये इमदाद न दी जाय। इसलिये मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि फेमीन के लिये काफी मदद दी जाय। बाकी बजट पहले से काफी ठीक है उसे पास किया जाय।

श्री मोतीचन्द खजान्ची—माननीब उपाध्यक्ष महोदय, सन् ५३-५४ के इस बजट के विषय में अनेक सदस्यों ने अपने आलोचनात्मक और समालोचनात्मक दृष्टिकोणों को रखा है और उनके विचारों को, जहां तक मैं समझ पाया हूं कुछ सदस्यों ने प्रशंसात्मक, कुछ सदस्यों ने विरोधात्मक रूप से कार्य किया है। बजट में हमें जो आशायें थीं और निराशायें थीं उनको दूर करने में यह बजट कहां तक सफल हुआ है और जिन निराशाओं के अन्धकारमय वातावरण में हम बहुत दिनों से यह सोच रहे थे कि हमारा आगामी बजट हमारे लिये क्या लायेगा, उसमें जनता के लिये क्या खर्च किया जायेगा तथा हमारी विकास योजनाओं के विषय में क्या रखा जायगा, न जाने कितने घाटे का बजट होगा। इस विचार से हम सोच रहे थे कि इन सारी परिस्थितियों में हम सारा प्रशासनिक खर्चा पूरा कर सकते हैं अथवा नहीं; किन्तु बजट को देखते हुए तो कम से कम समझ में आ सकता है कि हमारा जो बजट है वह सन्तुलित है। इसमें न घाटा दिखाया गया है न नफा। विशेष रूप से इस प्रकार के सन्तुलित बजट जो हैं वे बहुत कम होते हैं। किसी प्रान्त अथवा राष्ट्र में इस प्रकार के सन्तुलित बजट, जिनमे एक पैसे का घाटा या एक पैसे का नफा भी नहीं हो नहीं दिखाया जाता है; लेकिन फिर भी वह प्रयत्न किया गया है जो सराहनीय है।

बजट की कुछ मोटी २ मदों के बारे में, जो कुछ अनुचित अवश्य प्रतीत होती हैं और इस बजट की शोभा के अन्दर कुछ छींटे से उसमें मालूम होते हैं, उन्हें मैं अपने दृष्टिकोण से रख देना चाहता हूं।

फोरेस्ट के अंतर्गत जनरल डाइरेक्शन्स के अंदर चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट की तनख्वाह के ३,००० रु. और समस्त स्टाफ जिसमें कि २० अन्य कर्मचारी हैं उनके लिये २०,०५६ रु. हैं इतना बड़ा आपस में जो फर्क है अवांछनीय है। उन २० कर्मचारियों में जिनमें सेक्रेटरी और पी. ए. वगैरह सब सम्मिलित हैं और छोटे से छोटे कर्मचारी भी आ जाते हैं। इस प्रकार चीफ कन्जर्वेटर को ३,००० रु. जो दिये जाते हैं और दूसरी तरफ सारे ओफिस का खर्चा २०,०५६ रु यह कुछ ध्यान देने योग्य बात अवश्य है। इसमें से अनावश्यक खर्चा कम करके बाकी रुपय का उपयोग फोरेस्ट के अन्य दूसरे कार्यों में किया जा सकता था। फोरेस्ट के लिए ट्रेनिंग स्कूल का होना अत्यन्त आवश्यक है, फोरेस्ट के लिए गार्ड्स को ट्रेनिंग अत्यन्त आवश्यक है, लेकिन इस विचार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

Page No.65

[श्री मोतीचन्द खजांची]

अब मोटर वेहीकल्स के हेड में देखिये। ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर पर २१,६०० रु० का खर्चा और अन्य ऑफिसर तथा आफिस के अन्य २८ कर्मचारियों पर २३,४२३ रुपये हैं।

इसी प्रकार से अन्य विभागों में एन्टी स्मगिंलग भी है। इस फोर्स की शक्ति ५४७ के करीब है और अगर इसके 'एन्टी' शब्द को हटा दिया जाय तो कोई बुराई नहीं होगी। इसका खर्चा ६,५७,००० रुपये है। यह रुपयों का स्मगिंलग हो रहा है। इस एन्टी स्मगिंलग फोर्स ने कभी भी राजस्थान का कोई भी विशेष कार्य नहीं किया है। जहां तक अनेक प्रकार के स्मगिंलग का प्रश्न है, हमारे यहां वनस्पति घी (वेजीटेबल घी) उसी तरह आ रहा है, पाकिस्तान को उसी प्रकार से कपड़ा जा रहा है, लेकिन एन्टी स्मगिंलग फोर्स, (५४७ व्यक्तियों की वह फौज) न जाने क्या करती है? माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने, ५२-५३ में जो ८,१८,००० रु० थे उनमें ढ लाख रुपयों की कमी की है। वह शायद इसी दृष्टिकोण को रख कर की है, क्योंकि यह इतना उपयोगी विभाग नहीं है।

बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के ५ ऑफिसरों पर ६४,९४०) रु० खर्च आते हैं, तथा सारे कर्मचारियों पर ६५,८९५) रु० इस प्रकार का जो इतना फर्क है वह किसी भी प्रजातान्त्रिक सरकार के लिये शोभास्पद नहीं है।

अकेले एकाउन्ट्स ऑफिसर के लिए २३,५८०) रु० खर्च किये जाते हैं और स्टाफ के लिए २२,५५०) रु०।

अनेक मदों में से उद्योग-विकास को सर्वथा उपेक्षित किया गया है। जहां तक उद्योग-विकास का प्रश्न है, घरेलू उद्योग धन्धों के लिए १,८३,१००) रु० रखे गये हैं, और दूसरे भारी उद्योगों के विकास के लिए किसी प्रकार की राशि निश्चित नहीं की गई है।

हमारी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमें जो कुछ भी विकास करना है उसमें हम दूसरे रूप में तो करते हैं लेकिन उद्योग-विकास की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। किसी भी प्रान्त या राष्ट्र का उद्योग-विकास नहीं हो तो उस राष्ट्र के लिए उन्नति होना अत्यन्त नामुमकिन है। आर्थिक सहायता, जहां तक दूसरे उद्योग धन्धों को पनपाने के लिये दी जाती है उसके लिए यहां पर कोई ऐसी योजना नहीं है। यहां पर एक इन्डस्ट्रियल एडवाइजरी कौन्सिल की स्थापना की गई थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं कि कब इसकी मीटिंगें होंगी तथा वह यहां के उद्योग धन्धों पर विचार करेंगे। उद्योग धन्धों को न किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है और न ३, ३ वर्ष तक किसी प्रकार का फैसला ही किया जाता है कि किस व्यक्ति को कहां कैसा उद्योग चलाने के लिए इजाजत व कहां किस प्रकार की सहायता देनी या नहीं।

इसी प्रकार सहकारी योजनाओं में भी सरकार उतनी सक्रिय नहीं रही है।

निर्माण संबन्धी कार्यों में नाना प्रकार से विभिन्न डिविजनों में बहुत कुछ खर्च किया गया है। पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार से मिली हुई धनराशि का व्यय किया गया है और उसकी योजनाएं बना ली गई हैं जिसके अन्तर्गत एक-दो विशेष डिविजनों के अन्दर ही व्यय किया जायगा (५ वर्ष तक के

Page No.66

[श्री मोतीचन्द खजांची]

लिए.) लेकिन कई डिविजनों को बिल्कुल उपेक्षणीय दृष्टिकोण से देखा गया है, तथा उन्हें बिल्कुल अलग रखा गया है।

हैड १९ में १३,१९,५००) रु० व्यय किये जायेंगे। यह राशि भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के अन्दर प्रदान की गई है। इस राशि में मुख्य रूप से उदयपुर और जयपुर डिविजन को स्थान मिला है, अन्य डिविजनों को कोई स्थान नहीं दिया गया है।

हैड ५०, सिविल वर्क्स, नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज के लिए राजस्थान को १३,९६,७२०) रुपये इस वर्ष मिलेंगे, लेकिन उस राशि को सिर्फ जयपुर और उदयपुर डिविजन में ही व्यय करने का है। इस प्रकार की राशि को एक या दो विशेष डिविजनों के अन्दर रखा है। इनके अतिरिक्त दूसरे डिविज ों को सर्वथा उपेक्षणीय दृष्टिकोण से देखा गया है। यह शोभास्पद नहीं है।

हैड ५०-ए, सिविल वर्क्स केपिटल आउटले में से यह खर्च किया जायगा। इस साल का खर्चा ५० लाख रुपये और ५२-५३ में १९ लाख रुपये खर्च किये गये। बीकानेर को इसमें से साढे नो लाख रुपये दिये गये। यह साढ़े नो लाख रुपये वही ५२-५३ के पुराने रुपये हैं। बीकानेर से गंगानगर तक बनाई जाने वाली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस रोड पर दस लाख रुपये रखे गये थे, लेकिन दूसरे अन्य कार्यों में जितना रुपया रखा गया था वह खर्च कर दिया गया, लेकिन बीकानेर की इस सड़क पर १० लाख रुपये में से ५०,०००) रु० खर्च किये गये और उन्हीं ५२-५३ के रुपयों को वापिस ५३-५४ में रख कर दिलाया जा रहा है कि बीकानेर में सड़कों की उन्नति करना चाहते हैं, और उसके लिये हम इतना दे रहे हैं, और असल में ये रुपये वे हैं जो गत वर्ष खर्च नहीं किये गये थे।

("शेम, शेम" की आवाज विरोधी दल की ओर से)

हैड ६८, कन्स्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन, नेविगेशन, एम्बेंकमेन्ट एन्ड ड्रेनेज वर्क्स। पंचवर्षीय-योजना में जो न्यू वर्क्स शुरू किये गये हैं, (पुराने जो काम हैं उनको मैं छोड़ देता हूं) इसमें उनका खर्चा करना आवश्यक है। उनमें ५,०४,८१,०००) रुपये खर्च होंगे। उन कार्यों के लिये इस वर्ष ४५ लाख रुपये रखे गये हैं, लेकिन बीकानेर के लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया है। भारत सरकार से १७ करोड़ रुपया ५ वर्षों में हमें मिलने वाला है। उसमें से इस योजनाओं के लिए ५ करोड़ और कुछ लाख रुपया खर्च के हेतु रक्खा गया है। उस राशि में से इन नये कामों को शुरू कर दिया गया है तथा यह राशि इन्हीं कामों में खत्म हो जायगी, इसलिये दूसरे कामों में लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बीकानेर को इसमें से एक पैसा भी नहीं मिला। इस प्रकार से बहुत से डिविजनों को उपेक्षणीय दृष्टिकोण से देखा गया है।

हैड ५०, सिविल वर्क्स में भारत सरकार की ओर से कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट से मिलने वाली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान को उनके ग्रेडिंग के लिये १,७०,०००) रु० खर्च करने के लिये दिया गया है। यह तो सर्व विदित है कि राजस्थान अपने इस उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है, और यहां पर ऊन बहुत अच्छी होती है, और बीकानेर डिविजन में ज्यादा उत्पादन इसका होता है। बीकानेर न की सबसे बड़ी मन्डी है। वहां से प्रतिवर्ष करीब ७० लाख पोंड ऊन निर्यात होती है, लेकिन ऊन की

[श्री मोतीचन्द खजांची]

ग्रेडिंग के लिये लेब्रोरेट्री और रिसर्च इन्स्टीट्यूशन जो बानये जायंगे वह जयपुर के अन्दर बनायें जायंगे। उस लेबोरेट्री में ५०,०००) रु० और रिसर्च इन्स्टीट्यूशन में १५,०००) रु० लगेंगे। इसकी आवश्यकता विशेष रूप से बीकानेर के लिए है, क्योंकि जयपुर ऊन की मन्डी नहीं है, और जब इसके लिए लेबोरेट्री और रिसर्च इन्स्टीट्यूशन कायम हो तो यह देखना होगा कि कौनसी उपयुक्त मंडी है और उन लोगों की सुविधा के लिए कैसा उपयुक्त स्थान रहेगा और लोगों को कहां तक सुविधा होगी ?

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री कानसिंह—मैं अपने समय में से २ मिनिट देता हूं।

श्री मोतीचन्द खजांची (अपना भाषण जारी रखते हुए)—मैं यह कहने जा रहा था कि इस प्रकार से बजट को यदि देखा जाय तो उसमें कुछ डिविजनों की उपेक्षा की गई है। लेकिन जहां तक बजट संतुलित होने का प्रश्न है, और जहां तक मैं देख पाया हूं कि इसका असर बुरा तो नहीं पड़ेगा वहां तक जरूर संतोष होता है और अगर यह कहदूं कि इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि जो हमारी आशायें थीं अर्थात् बजट घाटे का रहेगा, ५३–५४ के इस वर्ष में हम आर्थिक संकट में पड़ जायंगे, तो उसका बिल्कुल निराकरण हो चुका है और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी जो हैं अवश्य बधाई के पात्र हैं।

श्री कानसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में मेरे पूर्ववक्ताओं ने बहुत सी बातों पर बहुत कुछ कह दिया है और उन्हीं बातों को दोहरा कर मैं सदन का समय न लेकर केवल एक–दो बातों पर ही कुछ कहना चाहता हूं। बजट के अनेक मदों में जो आमदनी का तखमीना लगाया गया है उसमें यह तो दिखा दिया गया है कि खर्च और आमदनी बराबर हो जावेगी लेकिन मैं इस तखमीने को सही सही मानने में हिचकिचाहट करता हूं क्योंकि इन मदों में सब से बड़ा लैन्ड रेवेन्यु का ही मद है जो आमदनी का मद है। इसमें आमदनी इस साल ४२१.०४ लाख दिखाई गई है लेकिन बजट के एक्स्प्लेनेटरी मेमोरेन्डम को देखने से मालूम होता है कि १९५३–५४ में रेट्स ओन सेसेज के खाने में ८.३९ आमदनी दिखाई गई है। यह मद ऐसा है जिसका असर कुछ इस बजट पर पड़ने वाला है। अभी इसी अधिवेशन में हम नया कानून पंचायत का बनाने जा रहे हैं जो जल्दी ही पास होने वाला है। इस कानून की तहत में पंचायतों को कोर्ट फीस व जुर्माने आदि से कुछ कर वसूल होंगे और उनका असर हमारी रेवेन्यु पर बड़ा भारी पड़ेगा। इस हिसाब से कितना रुपया पंचायत में मुन्तकिल होकर चला जावेगा इसका खयाल कहीं भी इस तकमीन बजट में नहीं किया गया है।

इसके अलावा जब हम स्टेट एक्साइज की तरफ आते हैं तो इसमें भी हमारे पास रिवाइज्ड एस्टीमेट १९५२–५३ और उसके साथ बजट एस्टीमेट का जो तकमीना है उसको देखें तो हमें मालूम होता है कि ४३ लाख का घाटा था। पिछले साल ४५ लाख का घाटा आम तौर से था। इस साल रिवाइज्ड एस्टीमेट और बजट एस्टीमेट के अनुसार २५ लाख की आमदनी बेशी दिखाई गई है लेकिन आयन्दा साल में २५ लाख की आमदनी हो सकेगी। पिछले साल एक्साइज रेवेन्यू में ४५ लाख का घाटा आता है और ऐसी कौनसी

[श्री कानसिंह]

बात है कि अब इस साल २५ लाख का फायदा हो जावेगा । इसलिये मेरे खयाल से ऐसे फीगर्स (आंकड़े) किसी तरह से ठीक नहीं जा सकते ।

हमारा बजट तो बिल्कुल बेलेंस्ड है । यदि इसकी गहराई में जावें तो आपको साफ जाहिर होता है कि कितनी कितनी लीपा पोती की गई है । मैं यह नहीं कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर को या फाईनेन्स मिनिस्टर को इसके लिये क्यों बधाई दी जाए । इसके अलावा बजट में मेमोरेन्डम के पेज २९ पर स्टेट एक्साइज की तहत में २३ नम्बर पर यह लिखा है—"Fines, Confiscation and Miscellaneous:—Monies realised (a) as composition amounts from the licensees and (b) by the disposal of confiscated goods under the Rajasthan Excise Act, Opium Act and Dangerous Drugs Act are credited to this head" मैं यह मानता हूं कि इस मद में सरकार को बहुत आमदनी होती है । बहुत से मामलों में जुर्माना किया जाता है । कई केसेज् में माल जब्त कर लिया जाता है तो सही यह तो लिख दिया कि स्टेट एक्साइज के खाने में दो करोड़ ७० लाख की आमदनी है मगर इसमें फाइन्स आदि का कोई खाना नहीं दिया गया । मुझे मालूम हुआ है कि यह तो सेव से रह गया है । सेव से नहीं रहा है तो माननीय चीफ मिनिस्टर इस पर दृष्टि डालेंगे । इसी प्रकार हमारे दूसरे मित्र ने कहा जैसे फोरेस्ट, इसमें इस साल ४० लाख की आमदनी दिखाई गई है । ५२-५३ में एस्टीमेटेड इनकम ४५ लाख की थी और रिवाइज्ड एस्टीमेट में ४० लाख हुआ । अतः ५ लाख ७० हजार का घाटा था । पिछले साल ५ लाख ७० हजार का घाटा और फिर इस साल रिवाइज्ड एस्टीमेट के बराबर आमदनी दिखाई गई है तो फिर इस साल भी घाटा था तो वह इस साल कैसे पूरा हो सकता है । ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो सकती है तो ४० लाख । जो पिछले साल हुई, वही हो सकती है । उससे ज्यादा कैसे हो सकती है । या तो ऐसा ही हो सकता है कि फोरेस्ट में बहुत मिसमेनेजमेन्ट है जिसके ठीक करने से आमदनी बढ़ जायेगी । इसलिये सरकार को चाहिये कि एक्साइज और फोरेस्ट में बहुत सतर्कता से काम करे ।

इसके अलावा पूर्व वक्ताओं ने बीकानेर के बारे में काफी कहा है और इसके बारे में हमारे विरोधी दल के मित्रों ने काफी कहा है इसलिये बीकानेर पर मुझे विशेष कहने की जरूरत नहीं है । लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि फाइनेन्स ने जो हम को कहा है कि हम बहुत कुछ टैक्सेज कम करने वाले हैं, इन्टर स्टेट ट्रान्जेट ड्यूटी खतम होने वाली है और इसके अलावा और भी छोटी छोटी सेसेज हमने हटा दी हैं । लेकिन जब हम बजट पेश करते समय दिये गये भाषण को पढ़ते हैं तो वह लागे उठाने का प्रश्न तो दूर रहा हमारे सामने टैक्सेज और लागों को और भविष्य में ग्लूमी (निराशा जनक) पिक्चर पेश करता है । सेटलमेंट रेट्स और वाटर रेट्स में इजाफा देखते हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मुझे दो मिनट और कहना है । यह वाटर रेट और सेटलमेन्ट रेट मुख्यतः बीकानेर पर ही ज्यादा लागू होंगी, ऐसी मेरी धारणा व मान्यता है । सरकार का कहना है कि वाटर रेट्स पंजाब में ज्यादा है, मुझे इसमें संदेह है, पंजाब की जमीन अच्छी है, वहां की हालत अच्छी है । बीकानेर डिविजन की

[श्री कानसिंह]

हालत तो वैसी नहीं है जैसी पंजाब की है। फिर निराधार कारणों पर ये लागें अथवा कर क्यों थोपे जा रहे हैं।

श्री गुरुदयालसिंह—पंजाब में किस जगह पर वाटर रेट ज्यादा हैं।

श्री कानसिंह—प्रोक्योरमेन्ट लाग भी हमको बरदास्त करनी पड़ेगी, जिसका भी बजट में वर्णन है। सेल्स टैक्स बढ़ने वाला है। कस्टम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के आदेशानुसार हटाया जा रहा है और सेल्स टैक्स बढ़ाने वाला है और सेल्स टैक्स लागू किया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और इसके अलावा साथ २ एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स भी हम पर आने वाला है। यही नहीं, बीकानेर डिविजन में तो एक और लाग है जो अन्य स्थानों में नहीं है। वह है एन्टर-टेनमेंट टैक्स वह बीकानेर में लिया जाता है अन्य स्थानों में नहीं लिया जता है।

बजट में जो रुपया खर्च के लिये रक्खा जाता है उसमें से बीकानेर को रुपया कतई नहीं दिया जाता है और न इस साल बीकानेर के लिये किसी काम के लिये रक्खा गया है। जहां टैक्स लगाने का सवाल आता है वहां बीकानेर को सबसे आगे रक्खा जाता है। इसलिये मैं वित्त मंत्रीजी से सविनय कहूंगा कि सब डिविजन्स को अनुपात से बराबर रकम दी जाय और समान रूप से टैक्सेज रक्खे जांय।

श्री रघुराजसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसलिये बधाई देता हूं कि बजाय घाटे के इस साल बराबर का बजट पेश किया गया है। बहतर यह होता कि बजट में गुंजायश बताई जाती। गुंजायश नहीं बताई गई तो कम से कम यही अच्छा है कि बराबर का बजट पेश किया गया। पर इसकी खूबी तभी मानी जायगी कि इस चालू साल की तरह सप्लीमेन्ट्री ग्रांट्स का मौका आगे पेश नहीं आवे, वरना वह घाटे के बराबर समझा जावेगा। चालू वर्ष में एक करोड़ का घाटा होने के उपरान्त भी, ४,८०,०००) और १,१६,००,०००) की ग्रांट्स मंजूर कराई गई हैं, तो आम तौर पर यह नियम के विरुद्ध है। कोई खास वजह होने पर ही ऐसी मांगें पेश होनी चाहियें।

इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में जो आम तौर से राहत मिलती है उससे शहरी जनता को ही इसका लाभ होता है, ग्रामीण जनता को बहुत कम लाभ होता है, ग्रामीण जनता की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। उचित तो यह है कि ग्रामीण जनता को ज्यादा लाभ पहुंचाया जाय और ज्यादा ध्यान दिया जाय।

एक दूसरी बात यह भी देखी गई है कि जितने फायदे, जितनी इमदाद राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार से मिलती है और जितनी भी योजनायें सरकार की ओर से काम पर रखी गई हैं, उनका लाभ जयपुर और उदयपुर डिविजन को ही मिल रहा है, जैसा कि पहले वाले वक्ताओं ने कहा।

[श्री रघुराजसिंह]

पर उन्होंने ज्यादातर बातें बीकानेर डिविजन के बारे में ही रखीं। मैं कोटा डिविजन के बारे में कुछ बातें अर्ज कर देना चाहता हूं। कोटा डिविजन को भी ऐसी कोई खास चीज नहीं मिली है, बमुकाबले जयपुर और उदयपुर के। अर्ज करने का मतलब मेरा यह है कि वास्तव में सब डिविजनों को बराबर प्रॉपोर्शन में रकमें मिलनी चाहिये।

भ्रष्टाचार रोकने के लिये एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट रखा गया और उससे कोई खास नतीजा हासिल नहीं हुआ है। इतने बड़े विशाल राजस्थान में साल भर में अगर १०-१२ केस पकड़ लिये गये तो इससे कोई फायदा नहीं। इसके लिये तभी उपयुक्त बातें हो सकती हैं जब कि एम. एल. एज़. और दूसरे भले आदमियों को लेकर उनके बताये हुए सुझावों पर सरकार एक्शन ले और जांच करे। इसीसे जो कुछ हो रहा है उस भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। खास कर फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उतना शायद और किसी डिपार्टमेन्ट में नहीं हो रहा होगा। इस पर मैं कट मोशन के वक्त प्रकाश डालूंगा। रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट में भी अफसरों द्वारा काम की देखभाल अच्छी तरह नहीं होती जिससे पटवारी जैसा चाहें वैसा काम कर सकते हैं। देख भाल नहीं होने से पटवारी लोग मनमाने काम करते हैं और बहुत सा काम चढ़ा हुआ पड़ा रहता है। सरकारी रकम पहले परभारी जमा होती थी। किन्तु, अब पटवारियों को सरकार ने वसूली के भी अधिकार दे दिये हैं; अतः वे लोग सरकारी रकम को दबा कर बैठ जाते हैं और बाद में जाकर जब रेवेन्यु ऑफिसरों को मालूम होता है तो फिर वह रकम उनसे निकलवाई जाती है। आज ऐसे कई केसेज़ चल रहे हैं।

और जगह के पटवारियों के बारे में तो विशेष कुछ अर्ज नहीं कर सकता लेकिन फोर्मर कोटा स्टेट में बटवारे का फैसला खातों की जांच-पड़ताल के बाद किया जाता है। खातों की जांच-पड़ताल किया जाना लाजमी था। अतः कानूनगो और रेकर्ड्स ऑफिसर नियत समय पर इन खातों की जांच-पड़ताल करते थे। इससे कागजात समय पर तैयार किये जाते हैं और कोई किस्म की गड़बड़ी नहीं होती थी। पर अब चार-चार साल से खाते बन रहे हैं, पैमाइश की जा रही है: जिससे वक्त पर लगान वसूल नहीं होता और गवर्नमेन्ट को हानि हो रही है। अगर माननीय मंत्रीजी इसकी जांच करने की कोशिश करेंगे तो उनको कई उदाहरण मिल जावेंगे। लैंड रेकर्ड्स डिपार्टमेन्ट है उसमें नीचे के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तोड़ दिये गये हैं पर ऊपर के अफसरों का जो खर्चा रखा गया है वह फालतू है। अगर इसे रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट के अन्डर में रख दिया जाए तो सरकार का काफी खर्चा बच सकता है।

आमदनी को बढ़ाने के लिये गवर्नमेन्ट को लाजमी है कि अगर नये बन्ध नहीं बनाए तो कम से कम पुराने बन्ध जो हैं उनकी रिपेयर्स तो कराए। यह काम लाजमी है। जब से राजस्थान बना इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

पंचायतों के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि पंचायतों का इन्तजाम बहुत खराब है जिससे जनता में असंतोष है और सभी पंचायतों से आम तौर से असंतुष्ट हैं। खास करके समय समाप्त हो जाने पर भी चुनाव नहीं होते हैं। इससे पुराने सरपन्च मनमाने कार्य करते हैं और पुरानी पंचायतों के मेम्बर समझते

[श्री रघुराजसिंह]

हैं कि हमारा समय खतम हो गया तो.वे वक्त पर आते नहीं हैं और कोरम नहीं होने से कोई मामला तय नहीं होकर पड़ा रहता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जहां चुनाव ड्यू हों वहां शीघ्र ही चुनाव हो जाने चाहियें।

शिक्षा के विषय में यह बात है कि बहुतसी जगहों से कॉलेज, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स आदि की मांग की जाती है। यह ठीक है कि जैसी गवर्नमेन्ट को सहूलियत हो उसके माफिक इन मांगों को पूरा करना चाहिये। लेकिन सबसे अधिक आवश्यक चीज शिक्षा के विषय में जो है वह यह कि प्राइमरी एज्युकेशन कम्पल्सरी होनी चाहिये, इससे गांवों के लोगों को विशेष फायदा होगा। इसके अलावा टेक्नीकल एज्युकेशन का भी अधिक ध्यान रखना चाहिये। इससे लोगों के लिये कमाने का जरिया हो जाता है। उनको नौकरी के लिये दर-दर मारा-मारा फिर कर मुंह नहीं ताकना पड़ता।

पुलिस डिपार्टमेन्ट की प्रशंसा की गई है। मैं समझता हूं वह ठीक होगी। किसी खास बोर्डर पर उनका काम अच्छा होगा। लेकिन मध्यभारत और राजस्थान का बोर्डर जहां मिलता है वहां तो पुलिस का खास अच्छा काम नहीं है, पुलिस ने अपनी कोई कारगुजारी नहीं दिखाई है। कोटा डिविजन में तीन-चार साल से एक मशहूर डाकू उपद्रव कर रहा है। उसकी पार्टी के एक भी आदमी को पुलिस वाले नहीं पकड़ सके हैं। इस डाकू का उपद्रव मेरी कांस्टीटयूएन्सी में है इसलिये मैंने यह भी सुना है कि वह मोटर में बैठकर पुलिसवालों के सामने से निकलता है पर पुलिसवाले उसे नहीं पकड़ सकते। या तो वह पुलिस वालों को रिश्वत देता है या वे लोग और किसी कारण से उससे डरते हैं, इस कारण से वे उसे नहीं पकड़ सकते।

सरकार को जिस चीज के लिये सबसे अधिक ध्यान देना चाहिये वह है अन्न और वस्त्र। ये सस्ते और अच्छे मिलें। इसी में सबका फायदा है। कोटा डिस्ट्रिक्ट में गेहूं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन गेहूं और चनों को वहां से बाहर भेजना प्रारम्भ कर दिया। इससे वहां पर इन चीजों की कमी आगई और नतीजा यह हुआ कि कीमतें इतनी बढ़ गईं कि वे ब्लेक मार्केटिंग को भी मात करने लगीं। सरकार की मंशा है कि काश्तकारों को राहत पहुंचाई जाय। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन इससे काश्तकारों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। काश्तकारों को फायदा फसल पर भाव बढ़ने से हो सकता है। लेकिन फसल पर भाव इतना गिरा दिया जाता है कि उनको सस्ते भाव से अनाज बेचना पड़ता है। जैसे चना २०) रु. मन भी बिका है लेकिन इस वक्त इसका भाव ११) रु. मन हो गया है।

मेडिकल रिलीफ के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि विशेष कर शहरों में और खासकर राजधानी में अधिक सुविधा का ध्यान दिया जाता है। कोटा के महाराव भीमसिंह होस्पिटल के बारे में श्रीमन् राजप्रमुख महोदय के भाषण में भी जिक्र आया था और इसका शिलान्यास डाक्टर काटजू साहब द्वारा होने पर भी आज तक उसका कोई काम शुरू नहीं हुआ है। जब तक ट्रेवलिंग डिस्पेन्सरीज का बन्दोबस्त नहीं किया जायगा तब तक अधिकांश लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। वेटरिनरी ट्रेवलिंग अस्पतालों का भी खास इन्तजाम होना चाहिये।

[श्री रघुराजसिंह]

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्टरों के कारों पर १ लाख ५ हजार के बजाय ३ हजार रुपये खर्च होना बजट में दिखाया गया है। वैसे तो यह बात प्रशसंनीय है, लेकिन यह प्रेक्टीकेबल नहीं मालूम होती। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या कार-अलाउन्स ही लिया जायगा; या क्या किया जायगा क्योंकि ३ हजार रुपयों में तो एक गाड़ी भी मेनटेन नहीं की जा सकती। टी. बी. सील्स के टिकिट वॉलन्टियरिली बेचने का आदेश गवर्नमेन्ट की तरफ से है परन्तु शफाखाने में इन टिकिटों को नहीं खरीदनेवालों को दवाई नहीं मिल सकती। वारां में टिकिट नहीं लेने के कारण एक ट्रक का चालान कर दिया गया था। क्या गवर्नमेन्ट इस बात को जांच करके उचित आदेश देगी?

ट्रान्सफर्स के ऊपर भी बहुत अधिक खर्च होता है। एक अफसर को एक स्थान पर दो-चार महीने से अधिक नहीं रखा जाता और जिसकी सिफारिशें होती हैं उनकी ट्रान्सफर हो जाने पर भी वह रोकदी जाती हैं। कोटा के कलेक्टर का ट्रान्सफर हो गया था पर वे अभी तक नहीं गये और इस कोशिश में हैं कि उनकी ट्रान्सफर रुक जाय। इस तरह की जो गलत बातें हो रही हैं उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेना चाहिये। मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन क्योंकि समय अधिक नहीं है इसलिये मैं बैठ जाता हूं।

श्री **सोहनलाल भटनागर**—उपाध्यक्ष महोदय, बजट की अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद कोई भी महानुभाव बता सकता है कि इस में खास चार बातें हैं। सब से पहली बात तो यह है कि कुछ पहले जो वित्त की स्थिति खराब हो गई थी उसका निराकरण इस बजट से हो गया है। द्वितीय बात यह है कि इस विषम परिस्थिति को ठीक करने में यह उम्मीद थी कि नये टैक्सों द्वारा सरकार अपनी कमी पूर्ति करेगी लेकिन वह चीज इस बजट में नहीं देख पड़ती। कुछ वाटर-टैक्स बढ़ाने का प्रॉपोजल है या लैंड इम्प्रूव करने के लिये टैक्स का जिक्र इस बजट में है। इसके सिवाय कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यह कोई बड़ी वस्तु नहीं है। जब कि जमीन खाली पड़ी है और उसका इम्प्रूवमेन्ट किया जाने वाला है जिससे काश्तकारों को कई गुना फायदा होगा तो उस फायदे में से कुछ हिस्सा राज्य वसूल करले तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह बेजा बात है।

तीसरी बात जो इस बजट से मालूम पड़ती है वह यह है कि इस बजट का बहुत कुछ भाग भारत सरकार पर निर्भर रहता है। हमें यह मानना होगा कि इस फेडरल स्ट्रक्चर (Structure) में बहुत से विषय सेन्टर के पास होते हैं और उनसे मदद प्राप्त करनी होती है। वह दिन दिन हम अधिक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सारे वित्त का ढांचा केन्द्रीय सरकार पर आश्रित है, तो मैं नहीं कह सकता कि हमारे राज्य का शासन केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना कैसे चल सकता है? लेकिन इसके साथ ही साथ हमें भी बहुत सोचना चाहिये। कई महानुभाव ऐसे हैं जो छोटा टैक्स लगा दिये जाने पर भी उसका ऑपोजिशन करेंगे। कई महानुभाव अनेक खर्चे के अभाव-अभियोग पेश करते हैं और जब उनकी पूर्ति नहीं होती तो कुछ शिकायत करते हैं। वे ग्रामीण जनता को भड़काते हैं। सदन के कई सदस्यों का मत है कि वे सरकार को कम से कम दें और उससे अधिक से अधिक लें। यह बात सदस्यों के लिये उपयुक्त नहीं है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत काफी खर्चा बढ़ रहा है। जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तब बहुत कुछ उम्मीद थी और उसका खास बेसिस यह था कि जितने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट अलग अलग हैं वे सब एक जगह हो जायेंगे और इससे खर्चा कम होगा, लेकिन उस आशा के विपरीत प्रतिवर्ष खर्च बढ़ रहा है।

श्री मानसिंह (जमुआरामगढ़)—जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो क्या जेब में हाथ डालना उचित हैं ?

श्री हरदेव जोशी—क्या पेन्ट में हाथ डाल कर बोलना पार्लियामेन्टरी है ?

श्री सोहनलाल भटनागर—सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे को कम करने का है। इसके लिये कुछ संभव हो सकता है। जिनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं उनकी तनख्वाहों में कमी की जाय और साथ ही इस सदन के कई सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं कि आवागमन का खर्चा कम किया जाय। मैं भी इस राय से सहमत हूं। फेमिन रिलीफ के बारे में यह आक्षेप लगाया गया है कि उदयपुर डिविजन में इस मद पर अधिक खर्चा किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि उदयपुर डिविजन में फेमिन रिलीफ पर जो खर्च किया गया है वह केवल भील एरिया में किया गया है। उस क्षेत्र में दो तीन वर्षों से लगातार अकाल पड़ रहा है, गत वर्ष अधिक वर्षा से कोई फसल नहीं हुई थी। इसलिये भीलों की स्थिति और भी बिगड़ गई थी। उनके पास खाने को दाना भी नहीं रहा और लोगों को बहुत तकलीफ होने लगी। इसलिये वहां रिलीफ कार्य विशेष रूप से शुरू किया गया।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के सामने बराबर यह कहा जाता है कि उदयपुर डिविजन में फैमिन पर काफी खर्च किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए, इस क्षेत्र के अकाल की हालत को देखते हुए और इस प्रदेश के औचित्य को देखते हुए, जितना इस प्रदेश में खर्च किया जा रहा है वह काफी कम है।

मैं इस बजट को देखते हुए इस सदन के सामने एक बात और प्रस्तुत करूंगा। जयसमुद्र से डेवेलपमेन्ट की बड़ी बड़ी स्कीमें हो सकती हैं। गत वर्ष भी मने इस कार्य के लिए रकम बजट में रखने के लिए निवेदन किया था किन्तु कोई रकम नहीं रखी गई। माननीय इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने फिर भी ६० हजार रुपये की रकम अलॉट की। सवा दो लाख रुपया और इस वर्ष रखा है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं। दूसरी बात जो मैंने निवेदन की थी वह यह थी कि उदयपुर डिविजन में माइनिंग का काफी स्कोप है किन्तु न तो जियोलॉजिकल सर्वे ही हुआ है और न ही पूर्णरूप से फायदा उठाया गया है। साथ ही गत वर्ष जब श्रीमन् राजप्रमुख का भाषण हुआ था उसमें भी बताया गया था कि माइनिंग इन्जिनियरिंग कॉलेज खोलने की स्कीम है किन्तु न तो उस स्कीम को पूरा किया गया है और न ही इस वर्ष के अभिभाषण में उसका कोई उल्लेख है। इस वर्ष के बजट में इस ओर ध्यान कोई नहीं दिया गया। अतः मैं अर्थ मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

श्री बेलजी भाई—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के सिलसिले में दो-चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। बजट के आय-व्यय के सम्बन्ध में बताया गया है कि आय १९४४ लाख होगी और व्यय भी उतना ही। हमारा तो यह विचार था कि हमारे पहाड़ी इलाके में जहां किसान बसते ह, भील लोग रहते हैं उनकी बहतरी के लिये उनके बीच में ज्यादा पैसा खर्च होगा क्योंकि उनके पास न तो तालाब हैं, न कुए हैं और न ही जमीनें हैं। बजट देखने से

[श्री बेलजी भाई]

हमारे देखने में आया कि ४ करोड़ रुपया शिक्षा और गरीब प्रदेश की बहतरी के लिये खर्च किये जावेंगे, दूसरी सारी रकम सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च की जायगी । बांसवाड़ा के अन्दर तीन साल से बराबर अकाल पड़ रहा है । लोगबाग दाने-दाने के लिये तरस रहे हैं। सरकार की तरफ से जितनी रकम दी गई है, वह ऐसे हिस्सों में खर्च की गई है जहां पर धनवान लोग बसते हैं, जिनके पास कुए व तालाव हैं । जिनके पास जमीन नहीं है और न कुआ है उन लोगों के बीच में एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सरकार ने गरीबों की चिन्ता न करके मालदारों को ही राहत पहुंचाने की कोशिश की है । जिन लोगों के पास खाने को नहीं था, उन लोगों को कुए निकालने के लिये तकावी नहीं मिली । केवल जिन लोगों की हालत ठीक थी उनको ही रुपया दिया गया और जिनकी हालत ठीक नहीं थी और भूखे और नंगे थे उनको कुछ भी नहीं दिया गया ।

शिक्षा के लिए जो स्कूलें खोली गई हैं बडे २ लोगों के लिये खोली गई । बेकवर्ड एरिया में लोगों के लिये कोई स्कूलें नहीं खोली गई। माननीय उपाध्यक्ष, अगर इस तरह से सरकार का काम चलता रहेगा तो यह सरकार आगे कैसे बढ़ेगी ? जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों के पास खाने को नहीं है, जो लोग शिक्षित हैं पर जिनके बल पर सरकार कायम है उन लोगों बीच में यदि पैसा लगाया जाय तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ सकता है और यह गरीब जनता भी आगे बढ़ सकती है, किन्तु यदि ज्यादा मालदारों को और अधिक मालदार बनाया गया, गरीब पिसता ही चला गया तो इस तरह से तो काम चलेगा नहीं और यह बात न्यायसंगत भी नहीं है । मैंने शिक्षा के विषय में गये साल कहा था कि हमारे गांव के अन्दर लड़कों को पढ़ाने का इन्तजाम नहीं है । पहले साल ४० लडकों के पढ़ने की तादात थी किन्तु अब कोई व्यवस्था नहीं होने से स्कूल भी वहां नहीं चल रहा है । इसके लिये हमने कई बार बांसवाड़ा में दरख्वास्तें की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । वहां के कई लड़के मध्य भारत में चले गये और गरीब लड़के आज भी मारे २ फिर रहे हैं । वे तीन-चार क्लास पढ़े हुए थे । अकाल के कारण इधर-उधर भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को भी नहीं है, ऐसी हालत में वे पैसा देकर और मास्टर रख कर किस प्रकार पढ़ सकते हैं । सरकार इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है ।

जहां पर तालाब बांधे गए थे ठेके देकर, उन तालाबों पर मिट्टी डला दी गई थी । वे तालाब पुराने बन्धे हुए थे, अतः उन पर मिट्टी डला दी गई । इसका नतीजा यह हुआ कि बरसात के आते ही वह मिट्टी साफ हो गई । और सरकार ने जो रकम इन पर खर्च की वह बेकार हो गई । एक तालाब पडोली में बंधाया गया था । बरसात के आते ही उसकी मिट्टी साफ हो गई और जो पैसा सरकार ने खर्च किया वह बेकार हो गया । अगर इन तालाबों को पक्का बंधवाया जाय तो सरकार को भी नुकसान नहीं होगा और पब्लिक को भी कोई नुकसान नहीं होगा । इसके साथ ही साथ में एक बात और कहूंगा कि जिन मजदूरों ने वहां काम किया उनको तीन तीन हफ्ते तक मजदूरी नहीं दी गई । वे आज भी शिकायतें करते हैं ।

फावड़ा कुदाली की उनकी डेढ़-डेढ़ महीने की मजूरी बाकी है। जगह जगह पक्षपात किया गया है। जो रुपया सरकार के नाम से इनसे लिया गया उससे दूसरे ही लोग फायदा उठा रहे हैं । गरीबों को कोई फायदा नहीं मिलता ।

[श्री बेलजी भाई]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जितनी रकम खर्च की जा रही है बांसवाड़ा में, वह करीब १५ लाख है । इस साल की योजना में भी उन हिस्सों में जहां मालदार लोग, पटेल, ब्राह्मण और दूसरे लोग जिनके बीच में तालाब-कुवा है, उनके लिए मन्जूर की गई है । यह रकम मालदारों के वास्ते दी गई है । गरीब भीलों का एरिया जैसे कुशलगढ़ एरिया, बांसवाड़ा का पूर्वी एरिया जो जहां आदिवासियों का निवास है, घाटोल में भील एरिया है, जहां न कुए हैं, न और कुछ है और जहां के लोग आधे-आधे दाने के लिए तरसते हैं ऐसी जगहों पर काम नहीं जारी किया गया । वहां के लोग आज भी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं !

गडी में जहां पंडित, ब्राह्मण आदि अच्छे लोग रहते हैं वहां उनके बीच में पांच साल की योजना के लिए काम रक्खा गया है, जहां तालाब हैं, कुए हैं । तो इस तरह से तो गरीब ज्यादा गरीब बनेंगे और मालदार ज्यादा मालदार होते जावेंगे। तो यह सरकार आगे कैसे बढ़ेगी यह हमारी समझ में नहीं आता।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—दो मिनट ।

श्री बेलजी भाई--(जारी)—हमारे बांसवाड़ा में गरीब अधिक हैं । यहां कोई ऐसा कारखाना नहीं है जहां वे मजदूरी करके अपना पेट पाल सकें। इस क्षेत्र में सरकार कोई ऐसा धंधा खोल देतो बड़ा लाभकारी होगा । रुई का या और किसी दूसरे तरह का कोई काम सरकार अवश्य खोले तो जितने मध्यम वर्ग के लोग वहां हैं उनका पालन-पोषण हो सकता है ।

श्री मोटाराम—माननीय उपाध्यक्षजी, जो बजट मुख्य मंत्रीजी ने इस हाउस के सामने पेश किया है उस पर अधिक नहीं कह कर मैं जिस क्षेत्र से आया हुआ हूं, वहां की जैसी हालत है आपके सामने रखना चाहता हूं ।

मारवाड़ के जिस हल्के से मैं आया हूं वहां पुलिस के लिए जो बजट में रकम रक्खी है उसके बारे में माननीय सदस्य कहते हैं कि यह रकम बहुत ज्यादा है । तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी कराना चाहता हूं कि मारवाड़ इलाके में सबसे ज्यादा डकैतियां और चोरियां बढ़ती जा रही हैं । इस वास्ते सरकार ने मारवाड़ पुलिस के लिए जो बजट रक्खा है उससे भी ज्यादा रखने की जरूरत है ।

राजस्थान में मारवाड़ के इलाके में यानि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां यानि मारवाड़ में तीन महीने के अन्दर ७ डकैतियां एक एक परगने में हुई हैं । इस तरह से मारवाड़ इलाके में सब से ज्यादा हरकतें हुई हैं। यानि बाढ़मेर और पाली जिलों में सबसे ज्यादा हरकतें हुई हैं। इसलिए सरकार को पुलिस को ज्यादा से ज्यादा मदद देने की जरूरत है ।

इसके साथ ही बाढ़मेर जिले में जिस जगह से म आया हूं और उसमें भी सिवाना क्षेत्र में कई सालों से कोई सरकार ने काश्तकारों के लिए मदद नहीं की यानि पहले बाड़मेर जिला में और सिवाना क्षेत्र में एक ही माला बांध है और छप्पन के पानी को इस बांध में मिलाया है ।

[श्री मोटाराम]

यानि इस तरफ अगर सरकार पूरी तवज्जह देतो हजारों बीघा की फसल ज्यादा हो सकती है। पर इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बाड़मेर क्षेत्र में बेरों और कुओं की इफरात नहीं है और वह पाकिस्तान की सरहद पर ही है। इस वास्ते सरकार को उधर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है।

मारवाड़ में सब से ज्यादा काश्तकारों पर बोझ पड़ा है जिनका सेटिलमेन्ट कर रखा है। मारवाड़ में आज से पहले जो खालसा के गांव थे उनमें चाही जमीन का डेढ़ रुपया से ज्यादा नहीं था। वहां चार रुपया दो आने कर दिया गया है और सरकार वहां मकान और बैल कुर्क करके वसूल करती है। मैं हाउस की जानकारी कराना चाहता हूं कि राजस्थान में सेटिलमेन्ट की रेट से किसान बड़ा दुखी होगा।

(विरोधी दल की ओर से करतल ध्वनि)

इस वास्ते प्रार्थना करता हूं कि आजादी के इस जमाने में अगर सरकार ज्यादा टैक्स किसानों पर लगाती है तो यह रास्ता किसानों को डुबाने का है। (करतल ध्वनि, तथा "हियर, हियर" की ध्वनि) मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इस सेटिलमेन्ट की रेट को कुछ कम किया जावे। इस रेट से तो किसानों की हालत गिर जावेगी पहले से भी यानि ज्यादा गिरने वाली है। यानि मारवाड़ में सबसे अधिक दुखी किसान है यानि किसान एकीकरण होने के बाद में बुरी तरह से मर गया है।

(हियर हियर की ध्वनियें)

इसका कारण यह है कि मारवाड़ के इलाके में सरकारी कर्मचारी जागीरदारों से मिले हुए हैं ("हियर हियर" की ध्वनियें) और इस वास्ते हजारों किसानों को बेदखल किया है और सरकारी कर्मचारी और जागीरदार अपना गुट बांध करके काश्तकारों के खिलाफ काम करते हैं ("हियर हियर" की ध्वनियें) यानि मारवाड़ के इलाके में सबसे ज्यादा किसानों को तकलीफ देने वाले ये सरकारी कर्मचारी और जागीरदार हैं। मैं हाउस को कहना चाहता हूं कि राजस्थान में मारवाड़ के इलाके में लाखों-करोड़ों रुपया रिश्वत के ये सरकारी कर्मचारी जागीदारों से मिलकर लेते हैं। यानि मारवाड़ में किसान को अपनी रक्षा के लिए पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस रुपये एकीकरण होने के बाद पंचपदरा, पाली, बाढ़मेर आदि परगनों में बंधे हुए हैं। पुलिस को कोई सहानुभूति किसान के साथ नहीं है। यह सरकार को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिये। (करतल ध्वनि) यह पिछले दो सालों से है। यह हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो सरकार जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई प्रबन्ध करे। यानि मारवाड़ इलाके में किसानों की स्थिति पर सरकार का पूरा ध्यान नहीं गया है और जिस क्षेत्र से मैं आया हुआ हूं और जो सरहद का इलाका है उस पर सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साथ यह अन्याय किया गया है। मंत्री महोदय जाते हैं अपने-अपने इलाके में और वहां लाखों रुपया खर्च करते हैं और हमारे एरिया में एक पाई भी नहीं खरची है। ("हियर हियर" ध्वनियें)

[श्री मोटाराम]

हमारे इलाके में बेरों की बहुत ही कमी है और जमीन बहुत ज्यादा है, मगर काश्तकारों के पास रुपया नहीं है। लाखों-करोड़ों बीघा जमीन, सरकार अगर मदद करे तो वे काश्त कर सकते हैं पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह हाउस को जानकारी कराना चाहता हूं कि जो लाखों रुपया मारवाड़ में टिड्डी दलको खत्म करने के लिए खर्च किया गया है उससे किसानों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उस काम के लिए हजार-आठ सौ रुपये की तनख्वाह वाले अफसर रखे गये जिनके लिये काश्तकारों को खाने, रहने आदि का इन्तजाम करना पड़ता था। उनके लिए ढोलिया हम लोग बिछाने के लिए देते थे।

("शेम, शेम" की ध्वनियें)

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी कराना चाहूंगा कि अगर टिड्डी दल को खत्म करना है तो ये हजार-हजार या आठ सौ रुपये के अफसरों के द्वारा यह कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए तो ३०,३० ४०-४० रुपये के आदमी रखिये, किसानों को रखिये: तभी टिड्डी दल का खात्मा हो सकता है और किसानों को फायदा मिल सकता है। हजार-हजार रुपये पाने वालों ने एक टिड्डी नहीं मारी हम लोगों ने, काश्तकारों से मिलकर लाखों टिड्डियों का नाश किया। उनके खाने पीने का प्रबन्ध करना पड़ा, आप जांच करवायेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांव गांव में इसी प्रकार उन अफसरों के लिए किया गया। सरकारी अफसर किसानों के बहुत खिलाफ हैं। वे किसानों को हर तरह से दबाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मारफत मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी जो किसानों के पीछे पड़े हुए हैं उनको जरूर सुधारने की कोशिश करें।

सरकार से अन्त में मेरी यही प्रार्थना है कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के जो काश्तकार हैं उनको उन्नत करने का प्रबन्ध करें।

श्री **मानसिंह महार (जमुवा-रामगढ़)**--उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने राजस्थान के अगले वर्ष का बजट बड़े ही कलात्मक तरीके पर हमारे मुख्य मंत्री ने हमारे सामने रखा। उसके लिये मेरे कुछ मित्रों ने यह कहा है कि आलोचना आलोचना के लिए की जाती है। तो उसको खुश करने के लिए कह दूं कि मुख्य मंत्रीजी इस कलापूर्ण तरीके के लिए इस सदन के द्वारा धन्यवाद के पात्र जरूर हैं। यह मैं मानता हूं कि कलापूर्ण तरीके से मुख्य मंत्री जी ने १० करोड़ या कुछ रुपया जो पुरानी रियासतों की तरफ से आया हुआ है उसे इधर उधर छिपे तरीके से राजस्थान की आमदनी में मिलाकर अगले वर्ष के बजट को बेलेन्स बजट बता दिया है। अफसोस इस बात का है कि अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष जब कस्टम की आय छोड़ देंगे उससे होने वाली जो करीब ३ करोड़ रुपया है उसका जो नुकसान हो जायगा उसमें हमारी बचत पूरी हो जायगी। उस समय मुख्य मंत्री किस कलाबाजी का परिचय देंगे, वह देखने की बात रह जायगी। इस समय मुझे केवल यह कहना है कि यह बजट बड़ा स्टिरियोटाइप बजट है। इसमें कोई नई बात नहीं है, वही पुरानी नौकरशाही, राजाशाही जमाने का बजट है। यह बजट एक ऐसे आदमी का बनाया हुआ बजट है जिन्होंने उस राजाशाही या नौकरशाही में अपनी जिन्दगी गुजार दी हो। इसलिए बजट

[श्री, मानसिंह महार]

में वे बातें मौजूद हैं जो उस समय में हुआ करती थीं। कॉंग्रेस के सिद्धान्त को अपनाने वाले कॉंग्रेस के पुजारी मुख्यमंत्री जी, सदन के सामने इस प्रकार का बजट प्रस्तुत करते हैं जिसमें सब से मुख्य आमदनी शराब से है। मैं यह कहता हूं कि मुख्य मंत्री को उनके साथी धन्यवाद भले ही दें किन्तु मैं सही मायने में महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुसार चलने वाला आदमी हूं इसलिए उन्हें हर्गिज धन्यवाद नहीं दूंगा। यह इस प्रकार का बजट कॉंग्रेस पार्टी के ऊपर कलंक है, यह मैं कहूंगा। पिछले अधिवेशन में मैंने यह कहा था कि जागीरदारों के शराब के अधिकार सरकार ने ले लिये हैं, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र अवश्य है किन्तु इसके साथ साथ अगर इस साल कम्पलीट प्रोहीबिशन किया होता तो हम उसका स्वागत करते।

(एक आवाज, "नहीं करेंगे")

लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह एक ऐसा बजट है जिसके अन्दर जनता को पानी मिली हुई शराब से इतना पैसा बजट में आता है और जिसका मुख्य अंग बजट की शराबखोरी है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पहली चीज है जिस पर हम इस बजट का हर्गिज स्वागत नहीं कर सकते।

दूसरी बात उपाध्यक्ष जी, यह है कि इस बजट के अन्दर कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सरकार ने किसी प्रकार की राहत देने की कोशिश नहीं की। कम वेतन पाने वाले कर्मचारी; जैसे चपरासी, पटवारी, अध्यापक इनके ग्रेड्स में किसी प्रकार का इन्क्रीमेन्ट नहीं किया गया। राजस्थान सरकार के लिये यह कोई शोभा की बात नहीं। वे आज के जमाने में कम तनख्वाह वालों को उसी स्तर पर रखना चाहते हैं और फिर हमारे मुख्य मंत्री जी यह फरमाते हैं हम तो वेलफेयर स्टेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या उनका वेलफेयर स्टेट्स की तरफ बढ़ने का यही तरीका है। क्या यही मेरे मित्रों के वेलफेयर स्टेट्स के आदर्श हैं। तो मैं यह कहूंगा जो वेलफेयर स्टेट्स का आदर्श माननीय मंत्री महोदय की निगाह में है वह बहुत नीचा स्तर का है। इसलिए अगर इस बजट को वेलफेयर स्टेट का बजट हमारे मंत्री महोदय बनाना चाहते हैं तो वे अपने २ विभागों में जितने कर्मचारी हैं और जिनके वेतन १००) रुपये से कम हैं उनकी तनख्वाह कम से कम वे १००) रुपया माहवार करदे इस प्रकार की यदि कोई रिवोल्यूशनरी योजना हमारे सामने हमारे अर्थ मंत्री महोदय रखते तो हम उसका हृदय से स्वागत करते और हम उन माननीय मंत्री को धन्यवाद देते और इस प्रकार के बजट को यह सदन सर्व सम्मति से पास करता। लेकिन दुःख इस बात का है कि यह कहने के बावजूद भी उन गरीबों की ओर सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इनकी ओर ध्यान देना तो दूर रहा। यह हालत हो रही है कि जो पटवारी आज से २० वर्ष पहले से नौकर हो गये हैं उनको अभी तक ३०) रुपये का ही वेतन मिलता है और आज जो नया पटवारी नियुक्त होता है उसकी तनख्वाह मुकर्रर की जाती है पैंतालीस रुपया माहवार। यह है वेलफेयर स्टेट्स का कानून। बीस साल से काम करने वाले को ३०) रुपया दिया जाता है और आज नये भरती होने वाले को पैंतालीस रुपया मिलता है। इसी प्रकार टीचर्स की भी हालत है। शिक्षा विभाग में पुराने जो अध्यापक हैं उन्हें पुराने ग्रेड्स के अनुसार तनख्वाह मिलती है उनको नया ग्रेड नहीं दिया जा रहा है और जो चन्द दिनों का मुलाजिम है उसे नये ग्रेड्स दिये जा रहे हैं। मैं कहूंगा यह सरासर पुराने अध्यापकों और पुराने पटवारियों के प्रति और लोअर पेड कर्मचारियों के

[श्री मानसिंह महार]

प्रति बड़ा भारी अन्याय है। इस प्रकार जो अन्धेरगर्दी हो रही है उसको दूर किया जाना चाहिये। वाजिब चीजों के लिए जो सुझाव विरोधी पक्ष की ओर से दिये जावें उनको कान खोलकर सुनना चाहिये, उन्हें स्वीकार करना चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री, उपाध्यक्ष जी, मैं आशा करूंगा कि मुख्य मंत्री इस प्रकार का अवश्य आश्वासन देंगे कि इस प्रकार की जो अन्धेरगर्दियां हो रही हैं सरकार उन्हें अवश्य दूर करेगी और लोअर पेड कर्मचारियों का वेतन बढ़ायगी। चाहे सरकार को सिक्यूरिटीज में पैसा लेकर वेतन बढ़ाना पड़े तो भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाना चाहिये। तो हम यह समझेंगे कि पुरानी रियासतों ने जो पैसा जमा किया था वह किसी अच्छे कार्य के लिए लग रहा है। और अगर वही रुपया मिनिस्टरों के एक्स्टेन्शन में या मिनिस्टरों की मोटरों पर खर्च होने लगेगा तो हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, इस जनरल डिस्कशन के समय सदन के सामने एक-दो पोइन्ट और रखना चाहता हूं। आज हमारे राजस्थान में लोगों के दिलों में बड़ी अनसर्टेन्टी (uncertainty) का वातावरण बना हुआ है। यह जो बजट पेश हुआ है जिसे हम यह समझते हैं कि क्या मालूम कि बजट पेश करने वाले इन साथियों में से कितने मिनिस्टर रहेंगे और कितने जायेंगे। इसके लिए मैंने पहले भी यह अपील की थी अगर इसका क्लेरिफिकेशन (clarification) हो जाता तो जनता को राहत मिलती।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--आपको तो कष्ट नहीं देंगे।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—(जारी रखते हुए) इसके अलावा बजट के बारे में अभी कुछ भाषण हो रहे थे तो उपाध्यक्ष जी, मैंने देखा मेरे कुछ मित्रों ने इस प्रकार सदन में भाषण किये जिनसे झलकता था कि वे डेप्युटी मिनिस्टर या और किसी पद के उम्मीदवार हों। मैं यह मानता हूं कि उन्होंने अपने भाषण के द्वारा भविष्य में होने वाली पदवृद्धि के लिए काफी अच्छा प्रचार किया है। इस प्रकार काम करके उन्होंने सदन में अच्छा वातावरण नहीं बनाया है। ऐसी बात पैदा नहीं की है जिसके लिए आयन्दा कोई सहारा लेकर काम कर सकें। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सदन में इस समय जो वातावरण है कम से कम बजट पेश करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष जी का हाथ घंटी पर जा रहा है। अब मैं बजट के बारे में खास जो पोइन्ट्स हैं उनमें से दो-चार के बारे में बातें कहूंगा और ज्यादा उनकी भूमिका नहीं बांधू तो ठीक रहेगा।

पहला जिस डिपार्टमेन्ट के बारे में मुझे सदन से निवेदन करना है वह है ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट। इस डिपार्टमेन्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाय वह थोड़ा है। यह डिपार्टमेन्ट सिवाय लोगों की जेब भरने के और मोटर वालों को परेशान करने के और कुछ भी नहीं करता है। दुर्भाग्यवश मेरी कॉंस्टिट्यूएन्सी ऐसा क्षेत्र है जिसमें से कोई रेल्वे लाइन नहीं गई हुई है, इसलिए जितना इस डिपार्टमेन्ट का हाल मुझे मालूम है उतना सदन के कम ही सदस्यों को मालूम होगा। बात यह है कि इस डिपार्टमेन्ट में आर.टी.ए. और एस.टी.ए. इस प्रकार की कमेटीज़ बना दी गई हैं, और उन कमेटीज के अन्दर डी.आई.जी. पुलिस और कमिश्नर ऑफ दी डिविजन और एक-दो बाहर के नॉमीनेटेड मेम्बर्स हैं, जो कि सत्तारूढ़ दल के ही

[श्री मानसिंह]

हो सकते हैं, और किसी के नहीं हो सकते हैं; उन्हें नॉमीनेट कर दिया है। लेकिन कमिश्नर और डी.आई.जी. को समय उपलब्ध नहीं होने की वजह से यह कमेटियां अमूमन मीट ही नहीं करती हैं। नतीजा यह होता है कि जो लाइनें हैं, जहां कि लारियां चल रही हैं, इन कमेटियों के मीट नहीं होने की वजह से वहां की गाड़ियां बन्द हो जाती हैं, परमिट नहीं मिलने की वजह से। इस तरह जनता को बड़ी असुविधा होती है। अब तो उन्होंने एक नया तरीका अख्तियार किया है। टेम्परेरी परमिट बन्द कर दिये हैं। उससे यह हो गया है कि परमिट नहीं मिलता है तो उस लाइन पर ६ महीने तक भी गाड़ी नहीं चल सकती है। इस प्रकार का अन्याय ग्रामीण जनता के साथ यह ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट कर रहा है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे जो मिनिस्टर महोदय हैं उनका ध्यान इसके ओवरहॉलिंग की तरफ विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। जो कई लाइनें बन्द हो गई हैं और लोरियां ओवरलोड चल रही हैं, जिनकी वजह से जनता की जान को खतरा पैदा हो रहा है वहां जल्दी से जल्दी लारियों की व्यवस्था की जाय और व्यवस्थित करके जनता को राहत पहुंचाई जाय। अगर यह काम ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है तो वह डिपार्टमेन्ट इस बजट में से एक पैसा भी लेने का हकदार नहीं होगा।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में कुछ बातें कहनी थीं। कहता तो तब जब कि कोई सुनने वाला हो, लेकिन अब यह डिपार्टमेन्ट तो इस समय निराधार सा है। इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ, अध्यापकों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार को कोशिश करके उस अभाव की पूर्ति करना चाहिये। सरकार शिक्षकों को इतनी कम तनख्वाह देती है कि लोग उससे पेट का पालन भी नहीं कर सकते हैं, वे अपना जीवन-निर्वाह भी नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों से पैसा ऐंठने को, ट्यूशन के रूप में या और किन्हीं तरीके से पैसा ऐंठने को मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको यह बतादूं कि मैं उनके इस तरीके को कभी भी रिश्वत में शामिल नहीं कर सकता हूं। राजस्थान सरकार भले ही इसमें गौरव नहीं समझे कि एक पटवारी या नाजिर या किसी शिक्षक को पकड़ कर वह कहती है कि हमारे एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट ने फलां आदमी को पकड़ा, लेकिन मैं उसको गौरव की बात नहीं मानता हूं। जब तक कि वह उनको पूरी तनख्वाह नहीं देती है तब तक वे चोरी नहीं करें तो क्या सरकार यह चाहती है कि वे डाका डालें। इसलिये उनको इस प्रकार जो मिलता है उसको मैं चोरी नहीं मानकर शुक्राना मानता हूं, (हंसी) क्योंकि सरकार जो है उनको इस प्रकार का शुक्राना लेने के लिये बाध्य करती है, अगर राजस्थान सरकार द्वारा कोई नाजिर या कम वेतन पाने वाला आदमी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो वह आदमी की कमजोरी नहीं मानता हूं, वह मैं राजस्थान सरकार की चोरी मानता हूं।

इसके अलावा शिक्षा पर ज्यादा नहीं कह कर मैं एक डिपार्टमेन्ट जिसका कि माननीय मंत्रीजी से सीधा ताल्लुक है उसके बारे में जरूर विस्तार से कहूंगा। अगर फिर भी ध्यान नहीं दिया जायगा तो कट मोशन में इसको लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। वह डिपार्टमेन्ट वह है जो कि, जिस प्रकार भारतवर्ष में चन्द्रनगर आदि फॉरेन एन्क्लेजर बने हुए हैं उसी तरह पाकिस्तानी एन्क्लेजर बना हुआ है वह डिपार्टमेन्ट है गवर्नमेन्ट प्रेस। इस गवर्नमेण्ट प्रेस के अन्दर

Page No.81

[श्री मानसिंह]

बहुत कुछ बातें हो रही हैं वह, मैं समझता हूं किसी से भी छिपी हुई नहीं है। उस प्रेस के जो सबसे बड़े अफसर हैं, सुप्रिन्टेन्डेन्ट महोदय, उनको अपना केस प्लीड करने का इतना खूबसूरत तरीका आता है कि अपनी सब गल्तियों को हमारे ऊंचे से ऊंचे अधिकारी के सामने छिपा देते हैं, और मैं समझा नहीं कि गवर्नमेन्ट प्रेस से मशीनरी वगैरह कैसे चली जावे। जितना काम होना चाहिये उससे आधा ही काम होवे और फिर भी सरकार आखें मीचे रहे और कहे कि कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार अगर इस संबंध में जांच करना चाहे तो यहां के सुप्रिन्टेन्डेन्ट को यहां से बदल देवे उनको सस्पेन्ड करदे और निष्पक्ष जांच करावे तो सब हाल रोशन हो जावेंगे और इस पर जब मैं कट मोशन लाऊंगा उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब के सामने सारी बातें पेश करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री **मानसिंह**--मुझे बहुत कुछ कहना बाकी है, अतः ५ मिनिट और दिये जायं।

श्री **उपाध्यक्ष**--अच्छा बोलिये।

श्री **मानसिंह**--(**जारी रखते हुए**) इसके अलावा इस बजट में एक बड़े खर्चे का जो मद है वह है मिनिस्टरों की तनख्वाहें। इसके बारे में मेरे कई मित्रों ने पहले भी फरमाया दिया है लेकिन एक तरफ तो हम यह सुनते हैं कि ९ मिनिस्टरों से घटा कर ७ मिनिस्टर रखने वाले हैं और दूसरी तरफ उनके आइटम में इतनी गुंजाइश कर दी जाती है कि शायद बंगाल के रेकर्ड को तोड दे। मैं समझता हूं कि सरकार चाहे ऐसा करने वाली है कि इस मद को इतना बढ़ा दे जितना चाहे और जितना चाहें मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टरों को ले ले और इस समय आपस में जो बेचैनी पैदा हो रही है उसको दूर करदें। यदि ऐसा हो जाता है और बेचैनी दूर हो जाती है तो हमको कोई ऐतराज नहीं। यदि इस बेचैनी को चीफ मिनिस्टर दूर करने में कामयाब हों तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनको मुबारिकबाद दूंगा। यह बात राजस्थान के हित की बात होगी और राजस्थान में कोई बात अनसेटल्ड नहीं होगी। अगर इसके अलावा चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टरों की तनख्वाह बढ़ावे और दूसरे मदों से खर्चे को कम करें तो उसको भी इस में तोड़ मरोड़ कर लगाना चाहिये था। तो मैं यह कहूंगा कि सरकार के लिये यह कोई शोभा की बात नहीं है।

इसके बाद में आपका ध्यान हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की तरफ आकर्षित करूंगा। मैं मानता हूं कि यह विभाग राजस्थान की कांग्रेस के बड़े ही महत्वपूर्ण कर्णधार के हाथ में है फिर भी इस विभाग में जिस प्रकार की इकतरफी कार्यवाहियें हो रही हैं उससे राजस्थान सरकार मुक्त नहीं हो सकती। अभी मेरे इसी पक्ष के मित्र ने इस विभाग के लिये आलोचना करते हुए बहुत कुछ कहा। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा अक्षर अक्षर सत्य था। फिर भी मैं यह कहूंगा कि इस सरकार के राजस्व विभाग को सही तरीके से चलाना है तो सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट को रिओर्गेनाइज करना होगा। यह गलत आदमी के हाथमें आया है। अगर वर्तमान सेटलमेन्ट कमिश्नर को यहां से वापिस वहीं पर नहीं भेजा गया जहां से कि यह आया है तो यहां के सेटलमेन्ट की हालत और भी गिर जावेगी। डिप्टी मिनिस्टर फरमाते

[श्री मानसिंह]

हैं कि वह जा रहा है। मुझे तो कोई इतला नहीं कि वह जा रहे हैं ? यदि यह बात जो उन्होंने कही वह सत्य है तो हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है। मैं तो कहूंगा.......

एक सदस्य--उप मंत्री कब से बने।

श्री चन्दनमल--इन्होंने ही बना दिये हैं।

श्री मानसिंह--इसके अलावा सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट में तनख्वाहें बहुत कम हैं इसलिये उस डिपार्टमेन्ट में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप सेटलमेन्ट की बात छोड़िये, एस. डी. ओ., कलेक्टर और कमिश्नर के वहां पर जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर भी रिश्वत का बोलबाला है, चाहे कोई भी वहां पर जावे लेकिन मैं यह दावा करके कह सकता हूं कि यदि कोई मंत्री महोदय यह बात कहें कि यह बात गलत है तो मैं उनके सामने लोगों से रिश्वत दिलवा कर बता सकता हूं वे अपनी आंखों से देखलें। इस डिपार्टमेन्ट में नीचे से ऊपर तक के ऑफिसर रिश्वत लेते हैं। जयपुर की बात मैं कह सकता हूं कि यहां पर आप कलेक्टर ऑफिस में चले जावेंगे तो आपको मालूम होगा, रीडर के खुले आम चांदी बरसती है। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट जो खुला हुआ है यदि उसके आदमी वहां पर चले जावें तो ये लोग फौरन पकड़े जावेंगे। रिश्वतखोरी की जयपुर गवर्नमेन्ट में एक समय में पुलिस और रेवेन्यू में घुड़दौड़ समझी जाती थी लेकिन बीच में उनकी कुछ बात दब गई क्योंकि सप्लाई डिपार्टमेन्ट खुल गया था। लेकिन अब तो यह डिपार्टमेन्ट मर चुका है इसलिये फिर से यह घुड़दौड़ इन डिपार्टमेन्टों में शुरू हो गई है। अब तो मैं यह कहूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने घुड़दौड़ में अपना कदम आगे बढ़ा लिया है। इसलिये मंत्री महोदय को चाहिये कि किसी तरह से इसको रिआर्गे-नाइज करें और रिश्वत को रोकें।

इसके अलावा एक खास बात कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके बारे में कहना तो बहुत कुछ था लेकिन थोड़ा सा यही कहूंगा कि वहां स्थिति डांवाडोल है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का वही एक ऐसा डिपार्टमेन्ट है जहां डिस्मिस्ड हेन्ड भर्ती किये गये हैं। माननीय मंत्री जी महोदय इसमें अपना गौरव समझते होंगे कि वहां पर डिसमिस्ड हेन्ड को रखा जाता है। जिस डिपार्टमेन्ट में डिस्मिस्डहेन्ड रहें क्या यह उस विभाग के मंत्री महोदय के लिये शोभा की बात है। यदि मंत्री महोदय इस बात को कोन्ट्राडिक्ट करें तो मैं चैलेन्ज के साथ इस बात को साबित कर सकता हूं, एक बार नहीं हजार बार।

एक थोड़ी सी बात मैं एल. एस. जी. के बारे में इशारे से बता देना चाहता हूं क्योंकि यह भी एक ऐसा डिपार्टमेन्ट है जिसपर वर्तमान बजट में एक मौके पर ऐसा सुनहरा महल दिखाया है कि राजस्थान इस ओर प्रगति कर रहा है। इस संबंध में पहली बात मैं यह कहूंगा कि पंचायतों पर सरकार ने स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किये हैं और उनकी आवश्यकता भी है, लेकिन जब एक समय डिप्टी मिनिस्टर पंजाबराव देशमुख जयपुर पधारते हैं तो वे उनका स्वागत करने खड़े होते हैं और कहते हैं कि चिन्तामणीजी देशमुख हमारे यहां पधारे हैं और आप लोगों के अहोभाग्य हैं। यह उनकी योग्यता का प्रमाण मैं सदन के सामने

Page No.83

[श्री मानसिंह]

बताना चाहता हूं। यह एक नमूना है आपके इस विभाग की एफीसियन्सी का। यदि मैं नीचे के नमूने बताने बैठूंगा तो सदन को वर्षों लग जावेंगे। गवर्नमेन्ट पंचायतों में पक्षपात के सिवाय कुछ नहीं हो रहा है। उदयपुर में गवर्नमेन्ट पंचायतों का इलेक्शन हुआ उसमें यह हुआ कि जिस पन्च के ज्यादा मत आए उसको पंचायत ऑफिसर ने पन्च मुकर्रर न करके जिनके कम मत मिले उनको इलेक्टेड कर दिया क्योंकि वहां पर लिखित में तो कोई चीज थी नहीं। उसने वोट तो आज ले लिये और कह दिया कि इसका नतीजा कल सुना दिया जावेगा। जिन्होंने जेब गरम करादी उनको पंच ले लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत है हमारे यहां ग्राम पंचायतों की (घंटी)

माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे इस बजट के विषय में अभी बहुत कुछ कहना है, पौन बज गया है।

श्री उपाध्यक्ष--पांच मिनिट और।

श्री मानसिंह महार (जारी)--सदन के सामने मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के बारे में निवेदन कर रहा था। मैंने अर्ज किया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन कराइये। अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो दूसरे आदमियों को लीजिये। तो इस बात के लिये मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने इसे मन्जूर कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का रिकॉन्स्टीट्युशन सरकार करने जा रही है। अब देखना है कि उसमें कृपापात्रों की ही भरती होती है या दूसरे लोगों को भी उचित मात्रा म लिया जाता है।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने समय समय पर यह कहा है कि वह विरोधी पक्ष का सहयोग चाहती है। विरोधी पक्ष का सहयोग सरकार को तभी मिल सकता है जब सरकार का दिल साफ हो। दिल साफ होने का नमूना यही होगा कि राजस्थान सरकार की जितनी नॉन-ऑफिशियल कमेटियां हैं उनमें सत्ता रूढ दल के आदमियों को न रखकर दूसरी पार्टियों के आदमियों को भी लिया जाय इससे बहुत अच्छी प्रगति होगी और जो धांधलियां नॉनऑफिशियल बाडीज में हो रहीं हैं वे ओपोजीशन के आदमियों के आन से शायद बहुत कम हो जावेंगी और सरकार को इससे काफी फायदा होगा।

अब मैं पुलिस विभाग के बारे में कुछ बातें कहूंगा। इस विभाग में ट्रान्सफर्स बहुत ज्यादा होती हैं। माननीय उप मंत्री जी यहां नहीं हैं, नहीं तो मैं अर्ज करता कि जिस तादाद में ट्रान्सफर्स हो रही हैं उतनी तादाद में नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा पुलिस महकमें में प्रोमोशन्स और डिमोशन्स जो हो रहे हैं उनकी मात्रा वर्तमान आई. जी. पी. के पधारने पर बढ़ गई है। प्रोमोशन्स कर दिये जांय इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं, परन्तु जल्दबाजी में प्रोमोट करके वापिस नीचे गिराया जाता है उससे जितना साहस और जितनी साहनुभूति सरकार की तरफ बढती है उससे कहीं ज्यादा गिर जाती है।

कृपापात्रों की भी पुलिस विभाग में भरमार हो रही है। इसका नमूना रखूंगा कि सारे राजस्थान में कोई सर्किल ऐसा नहीं है जो बिना डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस के हो, पर एक सब इन्सपेक्टर जो पुलिस

[श्री मानसिंह]

के अफसरों का मर्जीदान है वह अभी सर्किल इन्सपेक्टर बनाया गया है और मर्जीपात्र होने से सांगानेर के इलाके में, बिना किसी डीवाई. एस. पी. के इन्डिपेन्डेन्ट इन्चार्ज बना दिया गया है। यही एक ऐसा सर्किल है जहां डिप्टि सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्चार्ज पुलिस नहीं है और सर्किल इन्सपेक्टर, वह भी कैसा कि जो आज से ढाई महिने पहिले सब इन्सपेक्टर था। वह इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज लेकर काम कर रहा है। इस तरह के कृपापात्रों की बातें हैं। उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और इस प्रकार की शिकायतें विरोधी पक्ष वाले लाते हैं और उन्हें सरकार ठीक कर देगी तो इसमें कोई नीचे देखने की बात नहीं होगी। विरोधी पक्ष की बातों को यदि सरकार मानती है तो सरकार इससे ऊंची ही उठती है। बजट के आंकड़ों में भी मैं जाता क्योंकि मैं कम्पेरेटिव फिगर्स भी तैयार करके लाया हूं परन्तु समय नहीं होने से इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उन्हें सरकार को अवश्य राहत देनी चाहिये। उनकी तनख्वाह में किसी प्रकार से बढोतरी कर सकें तो अवश्य करना चाहिये।

इसी तरह से शिक्षा के स्तर को भी अगर ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमारे शिक्षकों की तनख्वाह बढाकर कुछ राहत दीजिये और अवश्य दीजिये।

इस प्रकार की बातें बजट म आतीं तो हमारे मित्रों ने जैसा कहा कि यह वैलफेयर स्टेट है, हम उनके कथन का स्वागत करते, इस बजट का स्वागत करते, पर यह बातें तो आई नहीं। ऊची तनख्वाह पाने वालों की बढोतरी हुई है इसलिये ऐसे बजट का स्वागत हम नहीं कर सकेंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अपील करूंगा कि अगर वे अपने बजट का चारों और से स्वागत चाहते हैं तो जो खामियां मने बताई हैं उनकी ओर ध्यान दें और इन कमियों को पूरी करें। अगर इन खामियों को पूरा नहीं किया गया तो यह ऐसा बजट है जिसे पुराने जमाने का निरंकुश शासन कहते हैं, उसी जमाने का यह बजट है।

यह सब दिखावा मात्र है।

शिक्षा के बारे में मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जो पहले शिक्षा मिलती थी उससे राजस्थान में आज स्टेन्डर्ड गिर गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो पन्द्रह वर्ष पहले के मिडिल पास से बात कराएं या आज के किसी मिडिल पास से बात करिये तो आपको मालूम होगा कि आप उन्नति कर रहे हैं या अवनति की ओर जा रहे हैं।

रेवेन्यू विभाग के मंत्रीजी से भी मैंने अर्ज किया कि उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार है और जयपुर की कमेटियों पर हावी होकर जिन लोगों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है उसकी ओर ध्यान देंगे तो ठीक होगा। रेवेन्यू विभाग में भी ट्रान्सफर्स बहुत होते हैं। बीकानेर से दूसरी जगह, दूसरी जगह से झुंझनु और झुंझनू से तीसरी जगह, यह हाल है ट्रान्सफर्स का। तो इस तरह से इन ट्रान्सफर्स को कम किया जावे।

[श्री मानसिंह]

यह बजट घाटे का है। भलेही मुख्य मंत्री जी बतावें कि १९४४ इधर और १९४४ उधर: और दोनों तरफ १९४४, तो इससे कोई मतलब नहीं। इस घाटे में भी ट्रान्सफरें कम होंगी तो कुछ न कुछ घाटे की पूर्ति होगी। अब मैं सदन से अर्ज करूंगा कि इस बजट के बारे में गौर से सोचें और इस दकियानूसी बजट को हरगिज पास नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष—बजट पर बहस कल जारी रहेगी। सवा ग्यारह बजे वित्त मंत्री जवाब देंगे। कल सवा आठ बजे (प्रातःकाल) फिर अधिवेशन होगा।

अधिवेशन स्थगित किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ५० मिनट पर, कल दिनांक २५-३-५३ को ८.१५ (प्रातः) तक के लिये स्थगित हुई)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २४-३-५३.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.86

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो संबंधित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन में नहीं लिये गए तथा जिनके प्रकाशन की अनुमति संबंधित मंत्रियों की हैं)

590. Shri Ganga Singh—Will the Minister for Public Works Department be pleased to state—

(a) Is there any plan to electrify Nagaur Town ?

(b) If so, what is that plan ?

उत्तर—

(a) There is no plan at present for the electrification of Nagaur Town.

(b) The question does not arise.

५९१. (८४/पी. डब्ल्यू. एम.) श्री प्यारेलाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ११८८ — क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

सिरोंज नगर की जन संख्या १५००० है। वहां पर बिजली लगाने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया, यद्यपि उसकी योजनायें कितनी बार बनीं ?

उत्तर—

सिरोंज नगर में बिजली लगाने की कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

600. Shri Brijendrapal Singh—Will the Minister, P. W. D., be pleased to state —

(a) What is the total grant, under the 5 Year Plan for the construction of the Karauil-Mandrail Road ?

(b) When is the work expected to be started ?

(c) In what period do the Government expect the road to be ready ?

उत्तर:—

(a) The work has not been included in the 5 year road Development plan. It is being financed from the Central Road Fund, allocations to Rajasthan Government.

(b) It is expected to be started next year.

(c) Government expects to have the road constructed within 2 years.

६०२. (२७/एफ. एम.) श्री भैरू सिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १६—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) जयपुर के St. Xavier हाई स्कूल के भवन निर्माण में राजस्थान सरकार द्वारा कितनी धनराशी सहायता के रूप में दी गई है ?

(ब) इस स्कूल को वार्षिक सहायता कितनी दी जाती है ?

(स) इस स्कूल का किस विश्वविद्यालय से Affiliation है ?

(द) क्या सरकार को मालूम है कि इस स्कूल में अनिवार्य रूप से बाइबिल पढ़ाई जाती है ?

उत्तरः—

(अ) ५००००) भवन निर्माण के लिये सहायता के रूप में इस वर्ष दिये गये हैं और २५०००) गत वर्ष दिये गये थे।

(ब) कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंध है तथा राजस्थान सरकार से मान्यीय है।

(स) कुछ नहीं।

(द) अनिवार्य नहीं है। हां, क्राइस्ट या उनके मतावलम्बी विभूतियों के उदाहरण देकर शिक्षा देना अनिवार्य है, जो अनुचित प्रतीत नहीं होता।

६०६. (९६/पी.डब्ल्यू. एम.) श्री धर्मचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

तहसील खन्डार के ४० गांव हैं जो बनास नदी के उस पार हैं। उस नदी में नाव का ठेका न होने के कारण बरसात में यातायात में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ? क्या सरकार अब प्रति वर्ष ठेका देने की व्यवस्था करेगी ताकि जनता का यातायात न रुके ?

उत्तरः—

इस सुझाव पर सरकार विचार करने को तैयार है, बशर्ते कि मुसाफिरों की संख्या को देखते हुए वहां के ठेकेदार ठेका लेने को तैयार हो जावें।

६१३. (११३/पी.डब्ल्यू.एम.) श्री संग्रामसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३४—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सच है कि भीम से जाने वाली सुबह के टाइम की बस सरकार बन्द कर रही है ?

उत्तरः—

(अ) नहीं।

६१७. (७६/इ.एम.) श्री भैरू सिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) प्राइमरी स्कूल खोले जाने के लिये किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है ?

(आ) क्या नई खुलने वाली सभी प्राइमरी स्कूलों में ये बातें संतोषजनक पाई गई हैं ?

(इ) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे भी स्थान हैं जहां इन सब बातों के होते हुए भी अभी तक प्राइमरी स्कूल नहीं खुली हैं ?

उत्तर।—

(अ) प्राइमरी स्कूल खोले जाने के लिये, उस स्थान की आबादी, छात्र संख्या, भवन, फर्नीचर, आसपास के अन्य ग्रामों की आबादी तथा उनमें जो प्रमुखता रखता हो आदि बातों पर ध्यान रखा जाता है ।

(आ) यथासम्भव और अधिकांश रूप में ऐसा होता है ।

(इ) हो सकता है ।

६१८. (७७/इ.एम.) श्री संग्रामसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३४—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या देवगढ़ हाई स्कूल में फर्नीचर काफी मात्रा में है ?

(आ) इस फर्नीचर को खरीदने में कितनी रकम खर्च हुई है ?

(इ) यह फर्नीचर कहां से मंगाया गया है ?

उत्तर।—

(अ) देवगढ़ हाई स्कूल में फर्नीचर की कुछ कमी है ।

(आ) १२८१) रुपये सन् १९५१-५२ में खर्च हुए और ८००) रुपये का फर्नीचर इस वर्ष खरीदा जा रहा है ।

(इ) गत वर्ष फर्नीचर बीकानेर से खरीदा था और इस वर्ष उदयपुर की अमुक फर्म्स से खरीदा जा रहा है ।

परिशिष्ट २

(दिनांक १८-३-५३ को मुख्य मन्त्री को सम्बोन्धित प्रश्न जो कि आज प्रश्न-काल में न लिये जा सके तथा जो प्रश्नोत्तर सदन की मेज पर रखे गये)

४८७. (६७/सी.एम.) **श्री ईश्वरीसिंह, एम.एल.ए., डिविजन नंबर ६३**—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सीकर जिले को तोड़ा जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में यह सोचा है कि इससे सीकर जिले के निवासियों को कोई असुविधा नहीं होगी, विशेष कर जब कि इस जिले में यातायात के साधनों की नितान्त कमी है ?

(३) क्या सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी ?

उत्तर:—

(१) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है ।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

491. Will the Chief Minister be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that during the month of January, 1953, the pick-up of a jeep, in which the Chief Minister was travelling, turned turtle ?

(b) Is it a fact that one Government emyloyee died as a result of it ?

(c) Is it a fact that this accident took place because the Chief Minister's jeep was being driven at a very fast speed ?

(d) Will the Government consider the grant of compensation to the family of the deceased ?

उत्तर:—

(a) The words "Pick up of a jeep" is not clear.

(b) Yes.

(c) No. The cause of the accident was that rear tyre of the pick-up got burst at a sharp turn resulting in the lessening of the control of the steering wheel. The Chief Minister was not going in a jeep.

(d) Yes.

४९२. (७५/सी.एम.) श्री नारायण चतुर्वेदी, एम.एल.ए., डिविजन नंबर १०६—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(१) कितने आर. ए. एस. अधिकारियों के स्थान पर नॉन आर. ए. एस. अधिकारी इस समय काम कर रहे हैं ?

(२) कितने आर. ए. एस. अधिकारी इस समय सरप्लस हैं ?

उत्तर:—

(1) 51 (fifty one).

(2) Nil.

495. श्री गंगासिंह--Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Has the Ranawat Committee, which was appointed to revise the seniority of officers, submitted its report or list to the Government ?

(b) Has the Government approved the above said list ? If not, are there any particular reasons for the same ?

(c) Is the Government aware of the discontent among officers on the non publication of the above list ?

उत्तर:—

(1) Yes.

(2) The report is still under consideration of the Government.

(3) No.

496. श्री गंगासिंह--Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that there are some officers who have been appointed as Magistrates inspite of the Public Service Commission recommendation to the contrary ?

(b) If so, how many cases are there of such nature and what are the Ground for their appointments ?

उत्तर—

(a) No.

(b) Does not arise.

499. श्री गंगासिंह—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that an officer was convicted in various charges by a regular magisterial court in 1948 has been, a few months back appointed on a responsible post in the Rajasthan Accounts (Finance) Service ?

(b) Will the Minister be pleased to state the reasons for this ?

उत्तर:—

(a) No.
(b) No.

500. श्री गंगासिंह—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that a number of outsiders have been taken in the services to the exclusion of Rajasthanies ?

(b) Will the Government state the number of such officers (outsiders) and reasons for their retention ?

उत्तर:—

(a) No outsiders are appointed only to such posts for which suitable local officers are not available, or under the All-India Schemes for recruitment to I.A.S. and I.P.S. officers under which Government of India allots officers to all States including Rajasthan on the result of the All-India Competetive Examination.

(b) 43. The reason for their retention is the same as given in (a) above.

502. श्री गंगासिंह—Will the Chief Minister be pleased to state:

How many officers and of what ranks have been posted in their (1) Home Towns and (2) Home District ?

उत्तर:—

The information is not readily available.

503. श्री एच. के. व्यास—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) How many officers are in the Secretariat who have no experience of courts and district administration ?

(b) Will the Government impart them such experience and according to what plan ?

उत्तर:—

(a) 6.

(b) Yes, such officers are gradually being sent out for District training which covers all aspects of District administration, e. g. Revenue, Judicial and Administrative. The training normally extends over a period of one year.

504. श्री एच. के. व्यास—Will the Chief Minister be pleased to answer:—

(a) Is the Government aware that Lal Bahadur Shastri had assured the people in his speech of October 2, 1952 at the time of inauguration of the Kundlla Railway that the Railway line from Samdari to Raniwada would be extended to Deesa ?

(b) Will the Government consider the need for approaching the Central Government for expediting the fulfilment of this legitimate demand ?

उत्तर:—

(a) Government is not aware about assurances, if any, given by Shri Lal Bahadur Shastri.

(b) The Project, however, has been included by the Government of India amongst the works to be taken up under the plan period.

506. श्री एच. के. व्यास—Will the Minister Incharge for Finance be pleased to answer:—

(a) Is the Rajasthan Government bound by agreements to pay interest for overdrafts or if its funds deposits are less than a certain minimum ?

(b) If so what are the rates of interest for the above two categories ?

(c) What is the total amount paid to the various banks as interest during the following years.—

(i) Financial year 1950-51.
(ii) Financial year 1951-52.
(iii) Financial year 1952-53.

उत्तर:—

Yes.

	Rate of Interest.
(i) Overdraft from the Imperial Bank of India against G.P. Notes pledged	3½% upto 8.49 crores. 4% Beyond the above limit.

Page No.93

(ii) Banks conducting Government Treasury business i. e. Bank of Jaipur 4½%
Bank of Rajasthan 4½%
Bank of Bikaner etc. 4½%

Interest charged by the Banks conducting Treasury business on the deficiency of 7 lacs, the minimum balance to be retained in Government account 2%

The amount of interest paid to Banks during the three years comes to 73 lakhs as follows.—

1950-51 21 lacs.
1951-52 26 ,,
1952-53 6 ,, upto 31-12-52.

507. श्री एच. के. व्यास—Will the Minister Incharge for Finance be pleased to answer.—

(a) Is it a fact that the various department of the Government spend a greater part of their budget in March only to avoid lapse of budget grant?

(b) Will the Government supply the figures of the expenses for

(i) March 1951 to the end of January 1952.

(ii) For February and March, 1952.

उत्तर:—

There is a regular procedure regarding control of expenditure and any contravention thereof amounts to breach of financial regularity. In order to check the tendency on the part of departments to rush up expenditure towards the close of the year, instructions have also been issued to all Heads of departments and Treasury officers warning them against this tendency.

Government do not propose to print the figures asked for, separately. In accordance with the rules for the preparation of Appropriation Accounts of the State, this sort of irregularity is detected by the Accountant General and the same is incorporated in the Audit report with which the Appropriation Accounts are placed before the Public Accounts Committee of the Legislature.

509. श्री एच. के. व्यास—Will the Minister Incharge for Finance be pleased to answer.—

(a) Is it a fact that the Reserve Bank of India has not yet been appointed treasurer?

(b) Have any negotiations been going on between the Rajasthan Government and the Reserve Bank ? If so, at what stage the matter stands ?

(c) Is the Rajasthan Government intending to ask the Reserve Bank to appoint those banks as its agents which are at present working as Government's treasurers ?

उत्तर:—

(a The Reserve Bank of India has not yet been appointed treasurer by Rajasthan Government.

(b Reserve Bank of India is finalising the terms of amalgamation of the Banks of Jaipur, Bikaner and Rajasthan to form a single institute for being entrusted with agency work by the Reserve Bank of India, when the latter is appointed as Rajasthan State Government Bankers. The question of appointing Reserve Bank of India as Rajasthan Government's treasurer is awaiting amalgamation of three Banks

c) This is for the Reserve Bank of India to decide. Rajasthan Government have, however, no objection to the proposal.

५१०. (९३सी.एम.). श्री मुक्तिलाल मोदी, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १०८:—क्या मुख्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान सचिवालय के स्टेनोग्राफर का एकीकरण हो जाने पर भी उसको अभी तक अमल में नहीं लाया गया ? अगर नहीं लाया गया तो क्यों ?

उत्तर:—

माननीय सदस्य का ध्यान विधान सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७सी.एम. के उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

५१३. (१०१सी.एम.) श्री तेजपाल, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १५२:—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान में रिश्वत के सिलसिले में कितने अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्यवाही की गई है ?

(ब) इनमें से कितनों को सजा मिल चुकी है ?

(स) कितने अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच इस विषय में की गई है ?

(ड) इनमें से कितनों को विभागीय और किस प्रकार की सजा दी गई है।

Page No.95

उत्तर:—

(अ) राजस्थान बनने के बाद भ्रष्टाचार विभाग ने मास फरवरी १९५३ के अन्त तक २६ राज्य कर्मचारियों को रंग हाथ घूस लेते हुए पकड़ा है और अभियुक्तों के विरुद्ध मुकद्दमे कायम किये जा चुके हैं ।

(ब) उपरोक्त २६ मुकदमों में से एक दन्डित हुआ तथा ३ न्यायालय द्वारा निर्दोष पाये जाने पर मुक्त किये गये । १ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेन्ट, अजमेर में स्थानान्तरित किया गया । ३ में विभागीय कार्यवाही के हेतु सिफारिश की गई है एवं १८ मुकदमें न्यायालयों में विचाराधीन हैं ।

(स) भ्रष्टाचार विरोधी विभाग की जांच द्वारा अपराधी पाये जाने पर राजस्थान बनने से फरवरी सन् १९५३ तक ८७ राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की गई है ।

(ड) १३ राज्य कर्मचारियों को पद से निकाला गया और ३ पदच्युत किये गये ५ को अर्थ दन्ड दिया गया, ७ शिकायत पर स्थानान्तरित किये गये, ६ के लिये भविष्य के लिये सतर्क किये गये एवं शेष के विरुद्ध आज तक सम्बन्धित विभागों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

५१५. (१०२।सी.एम.) श्री जगतसिंह झाला, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ६४—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या सरकार जिला चित्तौड की कुछ तहसीलों को समाप्त करके ग्रामों को इसी जिले या अन्य जिले की तहसीलों में मिलाना चाहती है ?

(आ) यदि हां, तो किन किन तहसीलों के ग्रामों को किस किस प्रकार ?

उत्तर:—

(१) नहीं ।

(२) पैदा नहीं होता ।